

ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

द्वितीय अंक



की प्रस्तुति



केशव सिंह प्रकरण ~ संविधान की सर्वोच्चता

विशेष संदर्भ संख्या-1, सन् 1964 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(हिन्दी में अनुवादित)

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएवसीआर
एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित



भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवंबर, १९४९ ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं।



हमें अत्यंत गर्व है कि आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण 'केशव सिंह बनाम विधान सभा अध्यक्ष' में पारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के हिन्दी अनुवाद पर आधारित ई-पुस्तिका के विमोचन के साक्षी बन रहे हैं, जो ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय का द्वितीय संस्करण है। यह निर्णय विधायी विशेषाधिकार और न्यायिक समीक्षा के बीच सीमाओं को परिभाषित करता है। 'केशव सिंह प्रकरण' भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है और इसे हम जनमानस के लिए विनम्रतापूर्वक लोकार्पित करते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी द्वारा संकल्पित यह संस्करण विधिक शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं विधि विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य संदर्भ सामग्री सिद्ध होगी।

यह विमोचन न केवल प्रकाशन को सशक्त बनाने का प्रयास है, अपितु न्याय तक पहुँच को सरल, सुलभ और बहुभाषी बनाने की दिशा में एक प्रशंशनीय कदम है। हम इस प्रयास में सहभागी सभी विद्वानों, संपादकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।



मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली
(संरक्षक, ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी)



न्यायमूर्ति अजित कुमार
(अध्यक्ष, ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी)



न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार शिन्हा
सदस्य



न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान
सदस्य



न्यायमूर्ति गौरव श्याम श्रमशेरी
सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी ई-एचसीआर एवं
आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Vijay Kumar Singh

Senior Advocate

प्रमुख पाठ्यक्रम:-

“प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥”

प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा हित ही राजा का हित है। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है। यह राजनैतिक सिद्धान्त प्राचीन भारत का ध्येय था। अमृत पड़ाव लांघ चुका भारत इस पथ पर पुनः अग्रसारित है। इस पचहत्तर वर्षीय तरुण भारत के जीवन की सत्रहवीं तरुणाई में एक वाक्या घटा जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं। केशव सिंह प्रकरण-जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की सर्वोच्चता को प्रतिस्थापित किया, धर्म की संस्थापना को पुष्ट किया। जिसे हम भारत के लोगों ने अपनी आत्मा के साथ 'मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत् दो हजार छह विक्रमी' को एतद्वारा इस संविधान को आत्मार्पित कर दिया था। अतः हमारा संविधान एक जीवन-शक्तियुक्त प्रखर राष्ट्र पुरुष बना। एक जीवित दस्तावेज बना। आइये हम केशव सिंह मामले की तह में चलें।

प्रकरण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी केशव सिंह का है। जिन्होंने तत्कालीन विधान सभा सदस्य श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार व गबन के लिए सामुहिक पर्चे बांटे। यह कृत्य अनुच्छेद 194 के तहत सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन था। परिणामतः उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने सदस्य सहित सम्पूर्ण सदन के अवमानना के लिए केशव सिंह सहित उनके सहयोगियों को समन भेजा गया। केशव सिंह के अन्य सहयोगियों ने सदन में उपस्थित हो कर गलती के लिए क्षमा मांग ली परंतु केशव सिंह सदन में उपस्थित नहीं हुए। अगले घटनाक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने प्रस्ताव पेश कर सदन के अपमान के लिए केशव सिंह को 7 दिन के कारावास का दंड दिया।

केशव सिंह के कारावास के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ सत्रपीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दाखिल की गई।

केशव सिंह की हिरासत की वैधता को चुनौती दी गई जिसमें कई अंतर्निहित प्रश्न थे-

1. क्या विधानमंडल को दंड की अधिकारिता है?

2. यदि विधानसभा के पास दंड की शक्ति है तो क्या अनुच्छेद 22 (2) का उलंघन नहीं है?
3. क्या अनुच्छेद-19 में प्रदत्त अधिकार वाक् स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है?
4. क्या संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार को न्यून करेंगे?

माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए केशव सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त आदेश से विधानसभा पुनः आहत हुई। उत्तर प्रदेश सदन ने इसे अपना अपमान मानते हुए न्यायिक स्वयं को दबाने के लिए दोनों माननीय न्यायमूर्तियों एवं केशव सिंह के विद्वान अधिवक्ता को समन जारी कर दिया। इस प्रकार संविधान के प्रमुख अंगों विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का संकट खड़ा हो गया। इस टकराव के बीच उच्च न्यायालय इलाहाबाद की 23 जजों की पूर्ण खंडपीठ बैठी। विधानमंडल ने टकराव की मंशा भांप कर तुरंत पैर पीछे किये। पूर्ण पीठ ने विधान सभा के आदेश को निरस्त करते हुए अंतरिम आदेश पारित किये।

मेरे विचार से इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों से कहा कि तीनों अंग शक्तियों के विभाजन के दायरे में रहें। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने तीनों अंगों के बीच समन्वयक रेखा खींच कर संविधान की सर्वोच्चता पर मुहर लगा दी। केशव सिंह को विधान मण्डल की अवमानना के लिए पुनः एक दिन के कारावास का दंड दिया गया।

इस प्रकार संविधान, शिखर राष्ट्र पुरुष के रूप में अविचल मुसकुरता खड़ा रहा।

अंत में, आशा करता हूँ कि आप सभी इस ऐतिहासिक निर्णयों की श्रृंखला को हिन्दी भाषा में पढ़ कर लाभ प्राप्त कर रहे होंगे।

विजय कुमार सिंह

विजय कुमार सिंह

(वरिष्ठ सम्पादक)

अस्वीकरण

ई- पुस्तिका में प्रकाशित निर्णय को ए.आई. तकनीक का प्रयोग कर अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित निर्णय की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/ सुवास प्रकोष्ठ उत्तरदायी नहीं होगा ।

अगर आप मूल निर्णय (अंग्रेजी) को पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए

मूल निर्णय स्रोत :

SPECIAL REFERENCE NO. 1 OF 1964 [1965] 1 S.C.R. 413 1964 INSC 203
(पीडीएफ पृष्ठ संख्या 15 से 100 तक)

केशव सिंह प्रकरण

पृष्ठभूमि एवं तथ्यात्मक विवरण

भारत के संविधान को लागू हुए महज़ 14 वर्ष ही हुए थे, जब देश के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें विधायिका और न्यायपालिका आमने-सामने आ गए। यह मामला संवैधानिक गलियारों में "केशव सिंह प्रकरण" के नाम से जाना जाता है। यह भारत में विधायी विशेषाधिकारों और न्यायिक समीक्षा से संबंधित था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 14 मार्च, 1964 को एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में गोरखपुर निवासी केशव सिंह की सदन की अवमानना करने और सदन के सदस्य श्री नरसिंह नारायण पांडेय के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए भर्त्सना की गई। सदन की अवमानना और विशेषाधिकारों का उल्लंघन उन पैम्फलेटों के कारण हुआ था, जो मुद्रित और वितरित किए गए थे। इन पैम्फलेटों पर केशव सिंह के हस्ताक्षर थे और इनमें श्री नरसिंह नारायण पांडेय पर शिवतरखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

विधानसभा के समक्ष उपस्थित होने के विभिन्न आदेशों के बाद भी, केशव सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें बाद में 14 मार्च, 1964 को सदन के अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट के निष्पादन में विधानसभा में लाया गया। उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लेने से मना कर दिया, जिसने सदन के प्रति अश्रेष्ठ अनादर प्रदर्शित किया।

भर्त्सना के बाद, अध्यक्ष ने सदन के ध्यान में 11 मार्च, 1964 का एक पत्र लाया। यह पत्र केशव सिंह ने उन्हें लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह "भर्त्सना का विरोध करते हैं और भ्रष्ट व्यक्ति को भ्रष्ट कहने में उन्हें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है।" उन्होंने यह भी जोड़ा था कि "उनके पैम्फलेट की अंतर्वस्तु सही थी और उन पर वारंट जारी करके लोकतंत्र पर बर्बर हमला किया गया था।"

इसलिए विधानसभा ने एक और प्रस्ताव पारित किया और केशव सिंह को सात दिन के कारावास का दंड दिया। यह दंड इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसी भाषा में पत्र लिखा था जो सदन की अवमानना गठित करती थी और सदन में उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। सदन के मार्शल और अधीक्षक, जिला जेल, लखनऊ को एक सामान्य या मूक वारंट (अनस्प्रीकिंग वारंट) जारी किया गया। इस वारंट में उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, जो अवमानना गठित करते थे। केशव सिंह को उसी दिन जेल ले जाया गया और वहां कैद किया गया।

गिरफ्तारी के छह दिन बाद, 19 मार्च, 1964 को केशव सिंह के अधिवक्ता श्री बी सोलोमन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में रिट याचिका संख्या 175/1964 इस आधार पर योजित की कि उन्हें बिना किसी विधिक अधिकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया था और यह नजरबंदी दुर्भावनापूर्ण थी। याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के अंतर्गत योजित की गई थी। (वर्ष 1964 में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिकाएं पुरानी सी.आर.पी.सी. की धारा 491 के अंतर्गत योजित होती थीं।)

मामले की सुनवाई करते हुए, माननीय न्यायमूर्ति एन.यू. बेग और माननीय न्यायमूर्ति जी.डी. सहगल की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 19/03/1964 (पृष्ठ संख्या 10) में केशव सिंह को कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।

तत्पश्चात, 21 मार्च 1964 को विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि लखनऊ बेंच के दोनों न्यायमूर्तियों और उनके अधिवक्ता को हिरासत में लेकर सदन के समक्ष लाया जाए। यह भी कहा गया कि केशव सिंह को अपने दंड का शेष भाग पूरा करने के बाद हिरासत में लेकर सदन के समक्ष लाया जाए।

(दिनांक 22 मार्च 1964 के समाचार पत्र नॉर्दर्न इंडियन पत्रिका के प्रातःकालीन संस्करण में उत्तर प्रदेश विधानसभा के संकल्प को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया था)-

“यह सदन संकल्प करता है कि न्यायमूर्ति एन.यू. बेग, न्यायमूर्ति जी.डी. सहगल, श्री केशव सिंह, तथा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री बी. सोलोमन ने सदन की अवमानना की है।

अतः आदेश दिया जाता है कि श्री केशव सिंह को तत्काल हिरासत में लिया जाए और कारावास की शेष अवधि पूर्ण करने हेतु जिला कारागार, लखनऊ में प्रतिबद्ध किया जाए तथा न्यायमूर्ति एन.यू. बेग और न्यायमूर्ति जी.डी. सहगल और श्री बी. सोलोमन को हिरासत में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

जब श्री केशव सिंह की कारावास की अवधि पूर्ण हो जाए तो उन्हें १९ मार्च को पुनः सदन की अवमानना करने के कारण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।”

उसी दिन, दोनों न्यायमूर्तियों ने 21 मार्च, 1964 के विधानसभा के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिकाएं योजित कीं। ये याचिकाएं रिट याचिका संख्या 1548/1964 तथा 1549/1964 के रूप में योजित हुईं।

विधानसभा के प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करने के लिए 23 मार्च, 1964 को सदन के मार्शल और लखनऊ के आयुक्त को वारंट जारी किए गए थे।

इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के 23 न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। जिसमें 27.03.1964 (पृष्ठ संख्या 11) के आदेश द्वारा प्रस्ताव पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। बाद में विधानसभा ने कहा कि न्यायमूर्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें सदन में अपने कार्यों को न्यायोचित ठहराने के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए। 23 मार्च, 1964 को जारी किए गए वारंट, जिन्हें कभी भी निष्पादित नहीं किया गया था, इन नोटिसों के परिणामस्वरूप वापस ले लिए गए थे।

राष्ट्रपति का संदर्भ

विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष और पूरे मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मत के लिए पांच प्रश्न तैयार किए थे। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को "कानून या तथ्यों के

प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने के लिए अधिकृत करता है, जो उनके लिए उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न होने की संभावना है, और जो ऐसी प्रकृति और ऐसे सार्वजनिक महत्व के हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मत प्राप्त करना समीचीन है।"

26 मार्च, 1964 को किए गए अपने संदर्भ में, राष्ट्रपति ने यह व्यक्त किया कि संदर्भित प्रश्न, ऐसी प्रकृति और ऐसे सार्वजनिक महत्व के हैं कि केशव सिंह के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मत प्राप्त करना समीचीन है।

तथ्यों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि राज्य विधानमंडल (सदन) और उसके अधिकारियों के संबंध में उच्च न्यायालय और उसके न्यायमूर्तियों के क्षेत्राधिकार के बीच गंभीर संघर्ष था। इसी प्रकार उच्च न्यायालय और उसके न्यायमूर्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी संघर्ष था। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष संदर्भ संख्या 1/1964 के रूप में दर्ज हुआ, जिसका हिन्दी अनुवाद इस ई पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित प्रश्न एवं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (संक्षेप में)

संख्या	सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित प्रश्न	सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
(क)	क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के लिए श्री केशव सिंह की याचिका पर कार्रवाई करना सक्षम था, जो उन पर सदन द्वारा लगाए गए कारावास के दंड के विरुद्ध था ?	लखनऊ पीठ सामान्यतः बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम थी।
(ख)	क्या श्री केशव सिंह, उनके अधिवक्ता और दो न्यायमूर्तियों ने सदन की अवमानना की?	यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि याचिका का प्रस्तुतीकरण एक अवैध कार्य था। इसलिए याचिका योजित करने के संबंध में दोनों न्यायमूर्तियों और केशव सिंह द्वारा कोई अवमानना नहीं की गई थी।
(ग)	क्या सदन के लिए दो न्यायमूर्तियों और अधिवक्ता को हिरासत में अपने समक्ष पेश करने का निर्देश देना और स्पष्टीकरण मांगना सक्षम था?	सदन के लिए न्यायमूर्तियों को सुनवाई दिए बिना अवमानना का दोषी ठहराना सक्षम नहीं था और वे उनकी हिरासत का आदेश देने के लिए भी असक्षम थे।
(घ)	क्या उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के लिए दो न्यायमूर्तियों और अधिवक्ता की याचिकाओं पर कार्रवाई करना और आदेश पारित करना सक्षम था?	पूर्ण पीठ के पास अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति थी जैसा उसने किया था।
(ङ)	क्या उच्च न्यायालय का एक न्यायमूर्ति, जो सदन के अवमानना या उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन के लिए सदन के किसी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्रवाई करता है, या जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, सदन की अवमानना करता है? और क्या सदन अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग और प्रवर्तन में ऐसे न्यायमूर्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम है?	न तो एक न्यायमूर्ति जो सदन के आदेश के खिलाफ किसी व्यक्ति की याचिका पर विचार करता है, सदन की अवमानना करता है, और न ही सदन न्यायमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात

राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मत के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका के तथ्यों और परिस्थितियों से गुजरते हुए इसे खारिज कर दिया और सदन के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उच्च न्यायालय ने केशव सिंह के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विधानसभा द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ पाए गए तथ्य विधानसभा की अवमानना की श्रेणी में नहीं आते थे।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादी द्वारा न तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ और न ही प्राकृतिक न्याय का, क्योंकि विधायिका ने विशेषाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए नियम तैयार किए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला जेल का अधीक्षक, अध्यक्ष से प्राप्त वारंट को निष्पादित करने के लिए अपनी अधिकारिता सीमाओं के भीतर था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के भाग iii के प्रावधान अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत आने वाले मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसने इस बात को दोहराया कि भाग iii में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 194(3) के आगे झुकते हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हरण अनुच्छेद 194(3) के बाद के भाग के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि विधानसभा द्वारा उनकी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी क्योंकि विधानसभा में राजनीतिक दुर्भावना और नफरत हावी थी। सदन के खिलाफ दुर्भावना का आरोप केवल इस तथ्य से प्रमाणित नहीं किया जा सकता था कि आरोपित व्यक्ति एक ऐसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित था जो सदन में बहुमत वाली पार्टी से अलग थी। उच्च न्यायालय ने केशव सिंह के मामले का निस्तारण किया और विधानसभा में दुर्भावना का अनुमान लगाने से मना कर दिया।

उच्च न्यायालय ने केशव सिंह की याचिका को निरस्त करते हुए यह माना कि किसी विशेष स्थिति में सदन की अवमानना हुई है या नहीं, यह निर्णय करना विशेष रूप से सदन का मामला है और न्यायालय कानूनी वैधता के प्रश्न में नहीं जाएगा।

मामले का महत्व

इस मामले ने विधायी विशेषाधिकारों पर न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को सुदृढ़ किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि विधायी कार्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। इसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर प्रकाश डाला, यह जोर देते हुए कि विधायी विशेषाधिकार पूर्ण नहीं हैं और न्यायिक जांच के अधीन हो सकते हैं।

केशव सिंह मामले में स्थापित सिद्धांतों को बाद की कानूनी कार्यवाहियों में बरकरार रखा गया है। विधायी विशेषाधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन भारतीय संवैधानिक कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।

नोट: यह संक्षिप्त लेख केशव सिंह प्रकरण के अध्ययन एवं ज्ञानार्जन के लिए विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया है, जिसकी विषयवस्तु और आंकड़ों के संबंध में किसी भी प्रकार की भिन्नता के लिए, संपादक मण्डल, सुवास सेल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद दायित्व वहन नहीं करता। उपरोक्त लेख में संदर्भित सूचना एवं जानकारियों आदि का प्रयोग विधिक कार्यों के लिए किए जाने की अनुशंसा नहीं करता। विधिक प्रयोगों के लिए मूल निर्णय पढ़ें।

रिट संख्या 175/1964 (लखनऊ) में पारित आदेश

माननीय न्यायमूर्ति एन. एच. बेग
माननीय न्यायमूर्ति जी.डी. सहगल

दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी कि इस आवेदन पर आज दोपहर ३ बजे सुनवाई की जाए। तदनुसार मामले की सुनवाई दोपहर ३ बजे की गई। **प्रतिवादियों** की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ की संतुष्टि के अनुरूप आवश्यक राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं रु. 1000/- प्रत्येक की राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। उप-निबंधक इस संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही करें। इस न्यायालय में इस मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

यह रिट याचिका अंगीकृत की जाती है। नोटिस जारी करें। इस मामले को यथाशीघ्र सूचीबद्ध किया जाए।

एसडी/
(अस्पष्ट)

सिविल विविध रिट संख्या 1548/1964 एवं सिविल विविध रिट संख्या 1549/1964 मे पारित आदेश

माननीय न्यायमूर्ति भार्गव
माननीय न्यायमूर्ति ओक
माननीय न्यायमूर्ति बी.दयाल
माननीय न्यायमूर्ति धवन
माननीय न्यायमूर्ति वर्मा
माननीय न्यायमूर्ति बरूम
माननीय न्यायमूर्ति माथुर
माननीय न्यायमूर्ति उनियाल
माननीय न्यायमूर्ति द्विवेदी
माननीय न्यायमूर्ति मनचंदा
माननीय न्यायमूर्ति रामभद्रन
माननीय न्यायमूर्ति गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अस्थाना
माननीय न्यायमूर्ति काटजू
माननीय न्यायमूर्ति ज्ञानेंद्र कुमार
माननीय न्यायमूर्ति पाठक
माननीय न्यायमूर्ति सेठ
माननीय न्यायमूर्ति महेश चंद्र
माननीय न्यायमूर्ति खरे
माननीय न्यायमूर्ति जी.सी.माथुर
माननीय न्यायमूर्ति गंगेश्वर प्रसाद
माननीय न्यायमूर्ति कपूर
माननीय न्यायमूर्ति त्रिपाठी

विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, जिन्होंने प्रतिपक्षी सं. 2 की ओर से नोटिस प्राप्त किया, ने कहा है कि वे इस आवेदन का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिपक्षी सं. 2 के विरुद्ध सीधे तौर पर कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है।

नोटिस जारी करें। इस बीच, प्रतिपक्षीगणों को 25, मार्च 1964 के आक्षेपित प्रस्ताव को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही न करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए और इसके अलावा हम नोटिस के संचालन पर रोक लगाते हैं और निर्देश देते हैं कि उस नोटिस के अनुसरण में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जिसके बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमें सूचित किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता को तामील किया गया है और याचिकाकर्ता से दिनांक 6, अप्रैल 1964 को स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इस अंतरिम आदेश को प्रतिपक्षी सं. 2 के विरुद्ध निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आशंका है कि प्रतिपक्षी सं. 2 की सहायता अन्य प्रतिपक्षीगणों द्वारा मांगी जा सकती है, जबकि यदि प्रतिपक्षी सं. 2 हमारे द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के विपरीत कार्य नहीं करता है तो कोई नुकसान नहीं होगा और, परिणामस्वरूप, यह आदेश प्रतिपक्षी सं. 2 को भी तामील किया जाएगा।

27-3-1964

एम.एस.

(वी.बी.)

(वी.जी.ओ.)

(बी.डी.)

(एस.एस.डी.)

(एस.के.वी.)

(डब्ल्यू.बी.)

(डी.एस.एम.)

(डी.पी.यू.)

(एस.एन.डी.)

(एस.सी.एम.)

(टी.आर.)

(बी.डी.जी.)

(के.बी.ए.)

(एस.एन.के.)

(जी.के.)

(आर.एस.पी.)

(डी.डी.एस.)

(एम.सी.)

(एस.डी.के.)

(जी.सी.एम.)

(जी.पी.)

(सी.बी.सी.)

(एच.सी.पी.टी.)

विशेष संदर्भ सं.1 सन् 1964
में पारित निर्णय
दिनांक 30 सितंबर, 1964.
का हिंदी अनुवाद

विशेष संदर्भ सं.1 सन् 1964

30 सितंबर, 1964.

(मुख्य न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्रगडकर, न्यायमूर्ति ए.के. सरकार, न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव, न्यायमूर्ति के.एन. वांघू, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह और न्यायमूर्ति एन. राजगोपाल अयंगर)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1)-के अन्तर्गत संदर्भ, क्या संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों से संबद्ध मामलों से संबंधित होना चाहिए- उत्तर देने से इनकार कब न्यायोचित है।

भारत का संविधान, अनुच्छेद 194(3)-भारतीय राज्य विधानमंडलों को प्रदान किए गए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार-क्या निर्णायक सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति ऐसे विशेषाधिकारों में से एक है- क्या विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के अधीन हैं-क्या विशेषाधिकारों के दायरे को निर्धारित करने की शक्ति न्यायालयों की नहीं बल्कि पूरी तरह से विधानमंडलों के पास है।

भारत का संविधान, अनुच्छेद 32, 226-राज्य विधानमंडलों द्वारा अवमानना के लिए दण्डित किए जाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करने और विचार करने की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति-ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति जहाँ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप हो।

भारत का संविधान, अनुच्छेद 211-निदेशक या अनिवार्य-अनुच्छेद 194(3) पर इसका प्रभाव।

उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा ने केशव सिंह नामक व्यक्ति को, जो इसके सदस्य नहीं थे, अवमानना के लिए जेल में डाल दिया। अवमानना वारंट में कथित अवमानना के तथ्य नहीं थे। अवमानना के लिए कारावास की सजा काटते समय, केशव सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें अवमानना के लिए उन्हें मिले दण्ड को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई; उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए भी प्रार्थना की। उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) ने शासकीय अधिवक्ता को नोटिस दिया, जिन्होंने विधान सभा सहित सभी प्रत्यर्थियों की ओर से इसे स्वीकार कर लिया। जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए निर्धारित समय पर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायमूर्ति बेग और न्यायमूर्ति सहगल जिन्होंने आवेदन पर सुनवाई की और आदेश दिया कि केशव सिंह को अनुच्छेद 226 के तहत उनकी याचिका के फौसले तक जमानत पर रखा किया जाए। विधानसभा ने पाया कि केशव सिंह और उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके और उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने याचिका को स्वीकार कर और विचार करके और जमानत देकर विधानसभा की अवमानना की है और एक प्रस्ताव पारित किया कि उन सभी को हिरासत में उसके समक्ष पेश किया जाए। इसके बाद न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की और उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया

और उनके खिलाफ विधानसभा के प्रस्ताव के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बाद विधानसभा ने एक स्पष्टीकरण प्रस्ताव पारित किया जिसमें उसके पहले के रुख को संशोधित किया गया। हिरासत में पेश किए जाने के बजाय, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को सदन के समक्ष पेश होने और अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया।

इस स्तर पर भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत एक संदर्भ दिया जिसमें उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल के बीच संवैधानिक संबंधों के बारे में संपूर्ण विवाद, जिसमें यह प्रश्न भी शामिल था कि क्या मामले के तथ्यों के आधार पर केशव सिंह, उनके अधिवक्ता और दोनों न्यायाधीश अपने-अपने कृत्यों से राज्य विधानमंडल की अवमानना के दोषी थे, को सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय और रिपोर्ट के लिए भेजा गया था।

संदर्भ की सुनवाई के दौरान बिहार के महाधिवक्ता की ओर से संदर्भ की सक्षमता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई कि यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले से संबंधित नहीं है। यह भी आग्रह किया गया कि यदि संदर्भ सक्षम था, तो भी न्यायालय को इसका उत्तर नहीं देना चाहिए क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था और इसके द्वारा दिए गए उत्तर राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को हल करने में मदद नहीं करेंगे। न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और पक्षों की सुनवाई शुरू कर दी, जो मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित थे - वे जो विधानसभा का समर्थन कर रहे थे और वे जो उच्च न्यायालय का समर्थन कर रहे थे।

विधानसभा की ओर से यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के आधार पर यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उसे प्रदान की गई हैं। यह अपने विशेषाधिकारों का एकमात्र न्यायाधीश है और न्यायालयों को उनके प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया कि इंग्लैंड में न्यायालयों ने हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अवमानना के लिए दिए गए दण्ड में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, जब दण्ड एक सामान्य वारंट द्वारा किया गया हो, यानी, एक ऐसा वारंट जिसमें अवमानना का गठन करने वाले तथ्यों को न बताया गया हो और इसलिए भारत में भी, न्यायालयों पर राज्य विधानमंडलों के सामान्य वारंट की वैधता की जांच करने पर रोक है। इसलिए, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय में कार्यवाही विधानमंडल की अवमानना थी।

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करने वालों ने आग्रह किया कि विधानमंडलों को संविधान के प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के अधीन हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां प्राप्त हैं, कि सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में से एक नहीं है, कि अनुच्छेद 226 और 32 के आधार पर, नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों में जाने का अधिकार है, और यह कि अनुच्छेद 211 के प्रावधानों के कारण, विधानमंडल द्वारा न्यायाधीशों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक है।

धारित किया गया: (मुख्य न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्रगडकर, न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव, न्यायमूर्ति के.एन. वांबू, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह और न्यायमूर्ति एन. राजगोपाला अयंगर के अनुसार) अनुच्छेद 143(1) के शब्द बहुत व्यापक हैं और उनमें केवल इतना अपेक्षित है कि राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि संदर्भित किए जाने वाले प्रश्न ऐसी प्रकृति के और ऐसे सार्वजनिक महत्व के हैं कि उन पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होगा। वर्तमान संदर्भ बनाने वाले राष्ट्रपति के आदेश से पता चलता है कि वह इस बात से संतुष्ट थे, और इसलिए संदर्भ सक्षम था। यह तर्क कि अनुच्छेद 143(1) के तहत संदर्भ केवल संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों से सीधे संबद्ध मामलों पर ही हो सकता है, गलत था। (431 ई-पी; 432 ई-एफ)।

अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पहले के संदर्भों में कोई एक समान पैटर्न नहीं दिखता और यह अनुच्छेद 143(1) में प्रयुक्त व्यापक शब्दों के अनुरूप था। (433 सी-डी)।

सन्दर्भ-दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 रु1951) एस.सी.आर. 747, केरल शिक्षा विधेयक, 1957 रु1959, एस.सी.आर. 995, बेरुबारी संघ और एन्वलेवों

का आदान-प्रदान [1960] 3 एस.सी.आर. 250 और सन्दर्भ-समुद्दी सीमा शुल्क अधिनियम [1964] 3 एस.सी.आर. 787- संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत दिए गए किसी संदर्भ का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है

- उस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द 'सकता है' है, जबकि अनुच्छेद 143(2) में प्रयुक्त शब्द 'करेगा' है। हालांकि, संदर्भित प्रश्नों का उत्तर देने वाली रिपोर्ट देने से इनकार करना केवल पर्याप्त और संतोषजनक कारणों से ही उचित होगा, जैसे कि संदर्भित प्रश्न विशुद्ध रूप से सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक प्रकृति के हों, जिनका कोई संवैधानिक महत्व न हो। वर्तमान संदर्भ ने गंभीर संवैधानिक महत्व के प्रश्न उठाए हैं और न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तर राष्ट्रपति को संघ और राज्य सरकारों को उपयुक्त विधायी या कार्यपालकीय कार्रवाई करने की सलाह देने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर देना न्यायालय का कर्तव्य था, [434 बी-डी; 433 जी-एच]।

(i) वर्तमान संदर्भ कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकार राय उचित रूप से न्यायनिर्णयन नहीं थी, और इस तरह से किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं करेगी। [446 एच; 447 ए]।

(ii) भारत में राज्य विधानमंडल न्यायालयों को नेपथ्य में रखकर, अनुच्छेद 194(3) के आधार पर अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों के एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा नहीं कर सकते। उनकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार केवल अनुच्छेद 194(3) में ही पाए जा सकते थे, अन्यत्र नहीं, और उस अनुच्छेद की व्याख्या करने की शक्ति भारतीय संविधान की योजना के अनुसार, विशेष रूप से इस देश की न्यायपालिका के पास है। (संविधान की योजना पर चर्चा)। [444 जी-एच 446 जी-एच]

संविधान का उद्देश्य भारत में उस 'द्वैतवाद' को कायम रखना नहीं था जिसने 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दियों के दौरान इंग्लैंड में सार्वजनिक जीवन को बुरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया था। संविधान निर्माता न्यायपालिका और संसद के सदनों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कई दुखद स्थितियों से अवगत थे, और अनुच्छेद 226, 32, 208, 212(1) और 211 (न्यायालय द्वारा परीक्षित) के प्रावधानों से दिखता था कि इरादा इस देश में इस तरह के संघर्ष से बचना था। [454 ए-बी; 455 सी-ई]।

अनुच्छेद 211 जो यह प्रावधान करता है कि विधानमंडल न्यायाधीश के उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते, अनिवार्य था। [457 जी-एच1]।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, [1958] एस.सी.आर. 533 और मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉर्मंडिन, एल. आर. [1917]। ए.सी. 170, संदर्भित।

(iii) यद्यपि अनुच्छेद 194(3) को स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों के अधीन नहीं किया गया है, फिर भी इसकी व्याख्या में अन्य प्रावधानों को अनदेखा करना अनुचित होगा, यदि वैध कारणों से वे प्रासंगिक और लागू पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ भी ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 194(3) के प्रावधानों और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के बीच संघर्ष है, सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के नियम को अपनाकर उक्त संघर्ष को हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए जैसा कि शर्मा के मामले में किया गया था। [443 सी-इ]।

पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य, [1959] अनुपूरक 1 एस.सी.आर. 806.

(iv) शर्मा के मामले में इस न्यायालय के बहुमत ने माना कि अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 194(3) की सामग्री पर प्रयोज्य था, हालांकि अनुच्छेद 19(1) प्रयोज्य नहीं था। अल्पमत का

मत था कि अनुच्छेद 194(3) सभी मौलिक अधिकारों के अधीन था। [451 बी-सी]।

यह नहीं कहा जा सकता कि शर्मा के मामले में बहुमत ने यह धारित किया कि अनुच्छेद 194(3) सभी मौलिक अधिकारों से स्वतंत्र था, इस साधारण कारण से यह माना गया था कि अनुच्छेद 21 प्रयोज्य था, हालांकि मामले के तथ्यों के आधार पर इसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाया गया था। उस मामले में उस मामले के याचिकाकर्ता ने भाग III में सभी मौलिक अधिकारों की अनुच्छेद 194(3) के लिए प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के रूप में सामान्य मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया था, और इसलिए न्यायालय के लिए उस सामान्य मुद्दे पर चर्चा करना और निर्णय करना अनावश्यक था। उनका दावा केवल दो अनुच्छेदों यानी अनुच्छेद 21 और 19(1)(ए) की प्रयोज्यता पर आधारित था। न्यायालय ने धारित किया कि पहला प्रयोज्य था और दूसरा प्रयोज्य नहीं था। इसलिए इसे शर्मा के मामले में निर्णीत माना जाना चाहिए। [451 सी-एफ]।

लेकिन शर्मा के मामले से यह मुद्दा हल नहीं हो गया कि अनुच्छेद 22(2) अनुच्छेद 194(3) पर लागू होता है या नहीं। रेडी के मामले में निर्णय की सत्यता के बारे में बहुमत की टिप्पणियां, जो इस आधार पर निर्णीत किया गया था कि अनुच्छेद 22(2) लागू होता है, को अनौपचारिक माना गया। (452 डी-ई)।

पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा एवं अन्य, [1959] अनुपूरक 1 एस.सी.आर. 806 और गुनुपरी केशवराम रेडी बनाम नफीरुल हसन एवं उ.प्र. राज्य, एआईआर. 1954 एस.सी. 636, पर चर्चा की गई।

(v) शर्मा के मामले में लिया गया दृष्टिकोण कि अनुच्छेद 194(3) के प्रथम भाग के अंतर्गत विधानमंडलों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले कानून अनुच्छेद 13 के अधीन होंगे और इसलिए मौलिक अधिकारों के अधीन होंगे, पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। [453 जी]।

अनंत कृष्णन बनाम मद्रास राज्य, एआईआर. 1952 मद्रास, 395, पर विचार किया गया।

(vi) अनुच्छेद 194(3) का प्रथम भाग राज्य विधानमंडलों को कानून द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद के दूसरे भाग में कहा गया है कि जब तक वे अपनी शक्तियों आदि को उपरोक्त तरीके से परिभाषित नहीं करते, तब तक उनकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की होंगी। दूसरे भाग का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंतरिम अवधि के लिए पहले भाग के तहत कानून बनाए जाने तक उन आकस्मिक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को प्रदान करना था, जो प्रत्येक विधानमंडल के पास होनी चाहिए ताकि वह प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम हो सके। [442 सी-ई]।

इस खंड द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स को दी गई शक्तियां वे हैं जो संविधान के प्रारंभ होने के समय भी अस्तित्व में थीं, अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को, न कि वे जो समाप्त हो गई थीं या जिनके संबंध में दावा छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, केवल उन्हीं शक्तियों को प्रदान किया गया माना जा सकता है जिनका न केवल हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था बल्कि ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी। [442 एफ-एच]।

(vii) यह दावा कि अनुच्छेद 194(3) के आधार पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियाँ भारतीय विधानमंडलों में निहित हो गईं, पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स की कई शक्तियाँ हैं - जैसे संप्रभु तक पहुँच का अधिकार, अभियोग के अधिनियम पारित करना, महाभियोग लगाना, अपना स्वयं का संविधान निर्धारित करना आदि, जिनका प्रयोग भारतीय विधानमंडलों द्वारा संभवतः नहीं किया जा सकता है। [448 डी-जी] में लिखित पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, 16वां संस्करण, पृष्ठ 86, संदर्भित।

(viii) अनुच्छेद 194(3), भारतीय राज्य विधानमंडलों को सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करने का अधिकार नहीं देता है, जिसकी वैधता की जांच बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में न्यायालयों द्वारा नहीं की जा सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में अपने सामान्य वारंट की जांच न किए जाने का कथित अधिकार इस विचार पर आधारित था कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय की स्थिति में है और अन्य उच्च न्यायालयों की तरह अवमानना के दोषी पाए गए व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए सामान्य वारंट जारी करने का अधिकार रखता है। इंग्लैंड में एक परंपरा थी जिसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना के लिए दण्ड हेतु सामान्य वारंट की जांच अन्य न्यायालयों द्वारा नहीं की जाती थी। यह उस आधार पर था और विशेषाधिकार के आधार पर नहीं था कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंट को न्यायालयों द्वारा जांच से परे माना जाता था। [482 बी-डी] 496 एफ में लिखित पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, 16वां संस्करण-अवलंबित।

एशबी बनाम व्हाइट, एल.जे. (1701-05) 714, अर्ल ऑफ शैप्ट्सबरी का मामला 86 ई.आर. 792, ब्रैडलाफ बनाम गॉसेट, एल.आर. XII क्यू.बी.डी. 271, 12 स्टेट टू. 822, सर फ्रांसिस बर्डेट, एबट, 104 ई.आर. 501, स्टॉकडेल बनाम हैसर्ड 112 ई.आर. 1112, एशबी बनाम व्हाइट और अन्य, 92 ई.आर. 126, आर. बनाम पैटी और अन्य, 92 ई.आर. 232, मरे का मामला, 95 ई.आर. 629, ब्रास क्रॉस्बी, 95 ई.आर. 1005, बर्डेट बनाम एबॉट 3 ई.आर. 1289, शेरीफ ऑफ मिडलसेक्स, 113 ई.आर. 419 और हॉवर्ड बनाम गॉसेट, 116 ई.आर. 139, पर चर्चा की गई और उनका अवलंब लिया गया।

ब्रैडलाफ बनाम गॉसेट, एल.आर. XII क्यू.बी.डी. 271, अप्रयोज्य धारित किया गया।

विक्टोरिया विधान सभा के अध्यक्ष बनाम ह्यूग ग्लास, (1869-71) एल.आर., पी.सी. 560, फीलिडिंग और अन्य बनाम थॉमस, 1896, एल.आर., ए.सी., 600, द क्वीन बनाम रिचर्ड्स, 92 सी.एल.आर. 157 और डिल बनाम मर्फी, (1864) 1 मू. पी.सी. (एन.एस.) 487 (15 ई.आर. 784), का अनुसरण नहीं किया गया।

मुन्सा ग्वेयर की सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक्ट नंबर XIV ऑफ 1938 [1939] एफ.सी.आर. 18 में इस आशय की टिप्पणियां कि अन्य संविधानों के संबंध में फैसले सुरक्षित रूप से लागू नहीं किए जा सकते, भले ही व्याख्या किए गए प्रावधान समान हों, का सहारा लिया गया।

न्यायमूर्ति पार्कर की इन रे: हंट केस [1959] 1 क्यू.बी.डी. धारा 378 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख इस बात को इंगित करने के लिए किया गया है कि एक उच्चतर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अवमानना के लिए दण्ड के संबंध में भी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दायर याचिका पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय उक्त अवमानना की वैधता पर विचार करने के लिए सक्षम होगा, भले ही दण्ड के लिए वारंट सामान्य या अत्यक्त हो।

भारतीय राज्य विधानमंडल अपने इतिहास में किसी भी समय, संविधान अधिनियम, 1935 के तहत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के तहत, रिकॉर्ड की अदालतें होने का इरादा नहीं रखते थे। अनुच्छेद 194 (3) में कानूनी कल्पना इंग्लैंड के इतिहास को भारत में स्थानांतरित नहीं कर सकती थी और भारतीय राज्य विधानमंडलों को रिकॉर्ड की उच्चतर न्यायालयों का दर्जा प्रदान नहीं कर सकती थी। इस प्रकार, जिस आधार पर अंग्रेजी न्यायालय हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट को इस आधार पर मानने के लिए सहमत हुए थे कि यह एक उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट था, वह उनके मामले में अनुपस्थित था, और इसलिए, यह तर्क देना अनुचित होगा कि सामान्य वारंट के लिए निर्णायक चरित्र का दावा करने की प्रासंगिक शक्ति, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, समझौते के द्वारा, निहित मानी जाती है, भारतीय विधानमंडलों में निहित हो गई। मामले के इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा किए गए दावे को खारिज करना पड़ा। [492 ए-बी]।

(ix) भले ही गैर-संवैधानिक योग्य सामान्य वारंट द्वारा दण्ड की शक्ति को हाउस ऑफ

कॉमन्स के विशेषाधिकारों का एक अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 194 (3) के आधार पर उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। [495-एच]

अनुच्छेद 226 और 32 के तहत न्यायालयों की शक्तियों का अस्तित्व अनिवार्य रूप से नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। (वर्तमान विवाद वास्तव में नागरिक और विधानमंडल के बीच था, न कि उच्च न्यायालय और विधानमंडल के बीच)। [494 ए-बी]

यदि कोई नागरिक इस न्यायालय में यह शिकायत करता है कि अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार [शर्मा के मामले में अनुच्छेद 194(3) पर लागू माना गया] या किसी अन्य लागू अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो स्पष्ट रूप से यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह उक्त तर्क के गुण-दोष की जांच करे। ऐसे मामले में यह कहना कोई जवाब नहीं होगा कि नागरिक के खिलाफ जारी वारंट एक सामान्य वारंट है और एक सामान्य वारंट को आगे की सभी न्यायिक जांच रोक देना चाहिए। अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग की व्याख्या पर अनुच्छेद 32 द्वारा भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का प्रभाव इस दृष्टिकोण के खिलाफ निर्णायक रूप से था कि सदन द्वारा किसी शक्ति या विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है, हालांकि यह अनुच्छेद 21 के साथ असंगत हो सकता है। इस संबंध में यह याद रखना प्रासंगिक था कि सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम अनुच्छेद 208(1) के तहत संविधान के प्रावधान के अधीन थे। [493 डी-ई]

सन्दर्भ-संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम 1770, 1958 ए.सी. 331 और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संकल्प, सी.जे. 1702-04, पृ. 555, 560, (मे के 16वें संस्करण पृ. 47 पर उद्धृत) के संबंध में न्यायमूर्ति सिमोंड्स की टिप्पणियां, संदर्भित।

यह अजीब होगा यदि सदन जो अनुच्छेद 211 के कारण एक न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आवरण पर चर्चा करने में अक्षम था, उसके पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन में की गई कथित अवमानना के लिए उसे उन्हें हिरासत में समन करने का अधिकार हो। यदि सदन के दावे को बरकरार रखा जाता तो इसका मतलब यह होता कि सदन एक न्यायाधीश के खिलाफ एक सामान्य वारंट जारी कर सकता था और इस तरह के वारंट की वैधता के संबंध में कोई न्यायिक जांच नहीं की जा सकती थी। यह न्यायिक स्वतंत्रता की मूल अवधारणा को गंभीर खतरे में डाल देगा। [493 ई-एच]

यह भी संदिग्ध था कि क्या सामान्य अत्यक्त वारंट जारी करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 554(2)(बी) और धारा 555 के साथ संगत थी। (496 ई-एफ)

अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30, सभी अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों, किसी न्यायाधिकरण या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तथा किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष, जिसके समक्ष अधिवक्ता तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत वकालत करने का अधिकार रखता है, वकालत करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है। बार काउंसिल अधिनियम की धारा 14 एक समान अधिकार को मान्यता देती है। जिस प्रकार अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका के अपने समक्ष मामलों पर विचार करने के अधिकार अनुच्छेद 194(3) के तहत सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों के अधीन नहीं हो सकते, उसी प्रकार नागरिकों के न्यायपालिका में जाने के अधिकार और अधिवक्ताओं द्वारा उस प्रक्रिया में सहायता करने के अधिकार अनुच्छेद 194(3) के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा और इस देश में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक एकीकृत योजना है। इसलिए एक निर्णायक सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार, जिसे राज्य विधानसभा ने अपनी शक्तियों या विशेषाधिकारों का एक अभिन्न अंग होने

का दावा किया था, संविधान के मूल प्रावधानों के साथ असंगत था और इसे अनुच्छेद 194(3) के उत्तराह्व के तहत शामिल नहीं माना जा सकता था। [495 ई-एव]।

इसके अलावा, विधानमंडल के सदन के प्रभावी कामकाज के लिए सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति आवश्यक नहीं थी। अमेरिकी कांग्रेस ऐसी शक्ति के बिना प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। [497 ई-ई]।

भारत में, संसद के सदनों के अलावा 14 राज्य विधानमंडल हैं। यदि उ.प्र. विधानसभा द्वारा दावा की गई शक्ति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि इसके प्रयोग से असामान्य स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, जैसे कि जब एक विधानमंडल के सदस्य को उसके अपने विधानमंडल में दिए गए भाषण के कारण दूसरे विधानमंडल द्वारा जारी सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित किया जाएगा। [497 ई-एफ]।

(x) केशव सिंह के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिका में सदन को इस आधार पर शामिल करने का विकल्प था कि उनका दण्ड सदन द्वारा पारित आदेश पर आधारित था, और इस अर्थ में सदन उनके दण्ड के लिए जिम्मेदार था, और उस पर नियंत्रण रखता था। [496 ई-सी]।

द किंग बनाम द अल ऑफ़ क्रेवे एक्स पार्ट सेकगोम [1910] 2 के.बी.डी. 576 और द किंग बनाम सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एक्स पार्ट ओशब्रायन [1923] 2 के.बी.डी. 361, संदर्भित।

(xi) यद्यपि इंग्लैंड में हाउस ऑफ़ कॉमन्स द्वारा अवमानना के लिए दण्डित होने वाले पक्षों को अदालतों द्वारा जमानत नहीं दी जाती है, भारत में स्थिति अलग है। यदि अनुच्छेद 226 न्यायालय को दण्ड के आदेश की वैधता पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, भले ही दण्ड का आदेश सदन द्वारा दिया गया हो, तो इसका अर्थ है कि न्यायालय के पास ऐसी कार्यवाहियों में अंतरिम आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है। 1498 एफ-एचआई उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा और अन्य, [1952] एससीआर 28 और मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ़ स्टैच्यूट्स, 11वां संस्करण, पृष्ठ 350, अवलंबित।

लाला जयराम दास और अन्य और किंग एम्परर, 72 1.ए. 120, को अप्रयोज्य धारित किया गया।

(xii) मामले के तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय केशव सिंह की याचिका को स्वीकार करने और विचार करने तथा उनकी याचिका के निपटारे तक उन्हें जमानत देने के लिए सक्षम था। केशव सिंह या उनके अधिवक्ता द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने या उक्त याचिका को स्वीकार करने और विचार करने तथा जमानत देने में उच्च न्यायालय द्वारा विधानसभा की अवमानना का कोई कार्य नहीं किया गया। विधान सभा के पास यह अधिकार नहीं था कि वह दो माननीय न्यायाधीशों और अधिवक्ता को हिरासत में अपने समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दे या उनके आचरण के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के पास यह अधिकार था कि वह उक्त दो माननीय न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की याचिकाओं को स्वीकार करे और विचार करे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उक्त याचिकाओं के अन्य प्रत्यर्थियों को विधानसभा के उपरोक्त निर्देश को लागू करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित करे। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जो विधानमंडल के किसी आदेश या निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करता है या उस पर विचार करता है, जिसमें याचिकाकर्ता (जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है) पर कोई दंड लगाया गया हो या याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी अवमानना (कथित अवमानना सदन की चारदीवारी के बाहर की गई हो) या उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन के लिए कोई प्रक्रिया जारी की गई हो, या जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता हो, वह उक्त विधानमंडल की कोई अवमानना नहीं करता है, और उक्त विधानमंडल अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग और प्रवर्तन में ऐसे न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। [502 ए; 503 सी]।

(xiii) यह याद रखना आवश्यक है कि विधानमंडल और न्यायपालिका, दोनों संस्थाओं की स्थिति, गरिमा और महत्व मुख्य रूप से संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए संबंधित कारणों की स्थिति, गरिमा और महत्व से प्राप्त होते हैं। इन दोनों निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका, जो लोकतांत्रिक राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, को न तो विरोध की भावना से और न ही शत्रुता की भावना से, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में तर्कसंगत, सामंजस्यपूर्ण और समझदारी की भावना से कार्य करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य के तीनों घटकों का ऐसा सामंजस्यपूर्ण कार्य ही इस देश में लोकतांत्रिक जीवन शैली के शांतिपूर्ण विकास, वृद्धि और स्थिरीकरण में मदद करेगा, [447 डी-ई]।

(xiv) अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका प्रयोग हमेशा सावधानी, बुद्धिमत्ता और परिस्थिति के हिसाब से किया जाना चाहिए, क्रोध या विद्वेह में इस शक्ति का बार-बार या अंधाधुंध उपयोग न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा, बल्कि कभी-कभी उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश यह कभी नहीं भूलते कि उनके पद की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपने निर्णयों की गुणवत्ता, अपने दृष्टिकोण की निर्भीकता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता तथा अपने न्यायिक आचरण में संयम, गरिमा और शिष्टाचार के द्वारा आम जनता से सम्मान अर्जित करें। हमें लगता है कि जो न्यायपालिका के लिए सत्य है, वह विधानमंडल के लिए भी उतना ही सत्य है। [501 एफ-जी]।

आंद्रे पॉल बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ त्रिनिदाद, एआईआर 1936, पी.सी. 141 में लॉर्ड एटकिन की टिप्पणियां, संदर्भित, न्यायमूर्ति सरकार के अनुसार (प) संविधान और इसलिए अनुच्छेद 194(3) की व्याख्या करना निस्संदेह न्यायालयों का काम है। इसका अर्थ यह है कि जब इस देश में यह प्रश्न उठता है कि क्या संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास कोई विशेष विशेषाधिकार था, तो उस प्रश्न का समाधान किया जाना चाहिए, और केवल विधि की अदालतों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यहां भयानक द्वैतवाद प्रकट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अर्थात् अदालतों का विधानमंडल के किसी सदन के साथ इस बात पर विवाद करना कि उसके विशेषाधिकार क्या हैं। [509 ए-बी]।

(ii) अनुच्छेद 194(3) में आने वाले शब्द हैं "किसी सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी.....जो हाउस ऑफ कॉमन्स की हैं।" इससे अधिक स्पष्ट भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। उस भाषा का केवल एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह है कि इसका आशय राज्य विधानसभाओं को वे शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करना था जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थी। शक्तियों के विभाजन के एक कथित सिद्धांत के प्रति निष्ठा का दावा करके शब्दों को उनके स्पष्ट अर्थ से वंचित करने में यहां चतुराई का कोई अवसर नहीं है। [511 ए-बी]।

ब्रैडलॉफ बनाम गॉसेट, (1884) 12 क्यू.बी.डी.271, बर्टे बनाम एबॉट। (1811) 14 ईस्ट 1. सन्दर्भ: दिल्ली लॉज, [1951] एस.सी.आर. 747. पीएल. एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री श्रीकृष्ण सिन्हा। [1959] अनुपूरक 1 एस.सी.आर. 806, विक्टोरिया विधान सभा के अध्यक्ष बनाम ग्लास (1871) एल.आर. 3. पी.सी. ऐप. 560 क्वीन बनाम रिचर्ड्स, 92 सी.एल.आर. 157, क्वीन बनाम रिचर्ड्स, 92 क्रि. 171 और फीलिडिंग बनाम थॉमस, [1896] एस.सी. 660- संदर्भित

(iii) न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की परिणामी वंचना के साथ एक सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति, हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में से एक थी। वह विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 194(3) के आधार पर उ.प्र. विधानसभा के पास था। [524 सी-डी]

यह दिखाने का कोई प्राधिकार नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास एक सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्तियां थी क्योंकि यह रिकॉर्ड का एक उत्ततर न्यायालय था। न तो सदन का इतिहास और न ही अंग्रेजी मामलों में दिए गए फैसले इस

धारणा का समर्थन करते हैं। अदालतों ने सदन को केवल एक उच्चतर न्यायालय के समान सम्मान का हकदार माना। उन्होंने यह नहीं कहा कि सदन एक उच्चतर न्यायालय है। [513 बी-सी] (522 बी)।

मे'ज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, 16वां संस्करण। पॉटर लिखित आउटलाइन्स ऑफ लीगल हिस्ट्री, (1958 संस्करण) एन्सन का लॉ ऑफ द कांस्टीट्यूशन 6वां संस्करण खंड 1, संदर्भित।

ब्रैडलॉ बनाम गॉसेट, (1884) 12 क्यू.बी.डी. 271 बर्डेट बनाम एबॉट, 5 डॉट 165, शेरिफ ऑफ मिडलसेक्स। (1840) 11 ए एंड ई 272। स्टॉकडेल बनाम हैसर्ड, (1839) 9 ए.डी. एंड ई और हॉवर्ड बनाम गॉसेट, (1874) 10 क्यू.बी. 359, अवलंबित।

यह कहना गलत है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास मौजूद सामान्य वारंट के तहत दण्डित करने का अधिकार न्यायालयों की विनम्रता के किसी नियम या अनुमानित साक्ष्य या न्यायालयों और सदन के बीच किसी समझौते या अंत में, पहले द्वारा दूसरे को दी गई कुछ रियायतों से उत्पन्न होता है। [522 ई-एफ]।

हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकार कानून पर आधारित हैं। उस कानून को लेक्स पार्लियामेंटी के रूप में जाना जाता है। वह कानून किसी भी अन्य कानून की तरह देश का कानून है जिसे लागू करने का अधिकार न्यायालयों को है। [522 एफ-जी]।

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के बारे में नए विचार शुरू करना हमारा कार्य नहीं है, ऐसे विचार जिनकी इंग्लैंड में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। जिस अवधि में ये विशेषाधिकार आकार ले रहे थे, उस पर शोध वर्ष 1950 में उनकी सामग्री और प्रकृति का कोई जवाब नहीं दे सकता। [523 जीएच; 524 बी-सी]।

अदभुत विद्वान लेखकों के साथ-साथ न्यायिक समिति के कुछ हालिया निर्णयों ने निर्णायक सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति को सदन के विशेषाधिकार के रूप में माना है, न कि एक उच्चतर न्यायालय के रूप में इसके पास मौजूद अधिकार के रूप में। [515 जी-एच]।

मे'ज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, 16वीं संस्करण, कीर और लॉसन द्वारा केसेज ऑन कांस्टीट्यूशनल लॉ, हेल्सबरी लिखित लॉज ऑफ इंग्लैंड, खंड 28, 467, डाइसी द्वारा लिखित कांस्टीट्यूशनल लॉ, 10वां संस्करण, संदर्भित।

विक्टोरिया की विधान सभा के अध्यक्ष बनाम ग्लास, फीलिडिंग बनाम थॉमस और शेरिफ ऑफ मिडलसेक्स अवलंबित।

(iv) न्यायिक समिति के निर्णय भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी भले न हों, लेकिन उनका उच्च प्रेरक मूल्य है, जब तक कि गलत साबित न हो जाए। सवाल यह है कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स को कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त था। यदि विशेषाधिकार का न्यायिक संज्ञान लेना है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के तहत, इंग्लैंड की अधिकृत कानून रिपोर्टों का संदर्भ वैध होगा, और यदि विशेषाधिकार के अस्तित्व को विदेशी कानून के मामले के रूप में तय किया जाता है, तो फिर से उस अधिनियम की धारा 38 के तहत इन रिपोर्टों का संदर्भ न्यायोचित होगा। और चूंकि उनमें इंग्लैंड की सबसे बड़ी अदालतों में से एक के फैसले शामिल हैं, इसलिए हम यह कहने के हकदार नहीं हैं कि जिसे वे अपने देश के हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार कहते हैं, वह विशेषाधिकार नहीं है, जब तक कि विपरीत दृष्टिकोण रखने वाला कोई समान रूप से उच्च अधिकारी सामने न आए। [517 डी-एफ]।

(v) यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रश्नगत विशेषाधिकार का प्रयोग भारतीय राज्य विधानसभाओं द्वारा केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिक के मौलिक अधिकारों के अधीन किया जा सकता है। शर्मा के मामले में इस अदालत ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद

194(3) द्वारा राज्य विधानमंडल के सदन को प्रदान किए गए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त करते हैं। यह निर्णय सही था और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं थी। [524 ई-एफ; 525 बी-सी, एफ]।

सन्दर्भ : दिल्ली कानून अधिनियम, 1950 [1951] एस.सी.आर. 747, संदर्भित।

शर्मा के मामले में यह नहीं धारित किया गया था कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 194(3) में निहित विशेषाधिकारों पर वरीयता प्राप्त करता है। मुख्य न्यायाधीश दास ने निस्संदेह कहा कि उस मामले में अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि स्वतंत्रता से वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार था। लेकिन वह केवल एक वैकल्पिक कारण था क्योंकि वह मान सकते थे-जैसा कि उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(ए) के मामले में किया था कि अनुच्छेद 21 एक सामान्य प्रावधान है और अनुच्छेद 194(3) विशेष है इसलिए पहला वाला दूसरे को रास्ता देगा। [531 ई-एफ; 532 बी-ई]।

यह कहने का एक और कारण कि मुख्य न्यायाधीश दास ने यह नहीं माना कि अनुच्छेद 21 सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के विशेषाधिकार पर वरीयता लेता है, यह तथ्य है, कि उन्होंने माना कि रेडी के मामले में गलत तरीके से फैसला किया गया था। उस मामले में माना गया था कि अनुच्छेद 22 को दण्डित करने के विशेषाधिकार पर वरीयता थी। यदि अनुच्छेद 22 को वरीयता नहीं थी, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश दास ने माना होगा क्योंकि उन्होंने रेडी के मामले की सत्यता को स्वीकार नहीं किया था, तो वे यह नहीं मान सकते थे कि अनुच्छेद 21 को अवमानना के लिए दण्डित करने के विशेषाधिकार पर वरीयता होगी। [532 ई-एफ]

(vi) शर्मा के मामले में बहुमत ने निस्संदेह बिना चर्चा के कहा कि अनुच्छेद 194(3) के तहत कानून सभी मौलिक अधिकारों के अधीन होगा, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 13 ऐसा कहता है। [528 सी-डी]।

अनुच्छेद 13 किसी कानून को गलत बना देता है यदि वह मौलिक अधिकारों के साथ टकराता है। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 194 के खंड (3) के तहत बनाए गए कानूनों को शून्य बना सकता है, इसलिए दूसरे भाग द्वारा दिए गए विशेषाधिकार भी शून्य होने चाहिए। अनुच्छेद 13 का संविधान के प्रावधानों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। यह केवल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को नियंत्रित करता है, जो अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत नहीं आता है। तथ्य यह है कि अनुच्छेद 194 के खंड (1) में संविधान के प्रावधानों के अधीन शब्द आते हैं, जबकि उन्हें खंड (3) से हटा दिया गया है, यह एक मजबूत संकेत है कि बाद वाले खंड को ऐसा करने का इरादा नहीं था। [528 ई-एच]।

(vii) जब अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग द्वारा सदन को दिए गए विशेषाधिकार और मौलिक अधिकार के बीच कोई संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष को शर्मा के मामले की तरह दोनों प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करके हल किया जाना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का अर्थ है कि दोनों प्रावधानों को एक दूसरे को खत्म किए बिना अधिकतम प्रभाव दिया जाना चाहिए। इस मामले में संघर्ष सदन के उस विशेषाधिकार के बीच था जिसमें वह किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए दण्डित कर सकता है, बिना उस दण्ड की न्यायालय द्वारा जांच किए, और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत उस अधिकार के प्रवर्तन में न्यायालयों में जाने के अधिकार के बिना। यदि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन में न्यायालयों में जाने के अधिकार को वरीयता दी जाती है, तो वह विशेषाधिकार जो यह उपबंध करता है कि यदि कोई सदन किसी व्यक्ति को सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करता है तो उस दण्ड की न्यायालयों द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी, अपना सारा प्रभाव खो देगा और यह ऐसा होगा मानो अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग द्वारा सदन को विशेषाधिकार प्रदान ही न किया गया हो।

यह सामंजस्यपूर्ण व्याख्या नहीं थी। ऐसा होने पर, यह अर्थ होगा कि जब कोई सदन किसी व्यक्ति को सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करता है तो उस व्यक्ति को न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही न्यायालय ऐसे आदेश पर निर्णय दे सकते हैं। [533 जी-एच, 534 ए-सी]।

बर्डेट बनाम एबॉट में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलेनबोरो की टिप्पणी, नियम के संभावित अपवादों के लिए संदर्भित। [534 सी-डी]।

(viii) लखनऊ पीठ को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि केशव सिंह की हिरासत एक सामान्य वारंट के तहत थी, और जब तक उसे अवगत नहीं कराया गया था, तब तक उसके पास अनुच्छेद 226 के तहत याचिका स्वीकार करने और विचार करने की पूरी क्षमता थी। वर्तमान संदर्भ में यह प्रश्न निर्णीत करना आवश्यक नहीं था कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में जहां दण्ड अवमानना के लिए है, कानून जमानत पर रिहाई की अनुमति देता है, क्योंकि संदर्भ का उद्देश्य उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना नहीं था। माननीय न्यायाधीशों या बी. सोलोमन या केशव सिंह द्वारा याचिका के संबंध में उनकी भूमिकाओं के लिए कोई अवमानना नहीं की गई थी क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उनमें से किसी को भी पता था कि दण्ड एक सामान्य वारंट के तहत था। चूंकि वे दोषी नहीं थे, इसलिए विधानसभा उन्हें हिरासत में पेश करने का आदेश देने में सक्षम नहीं थी। सरखी से कहा जाए तो, सदन के समक्ष उन्हें हिरासत में लाने का सवाल मामले के तथ्यों पर नहीं उठता क्योंकि विधानसभा ने उस संबंध में अपने प्रस्ताव को संशोधित किया था। विधानसभा दोनों न्यायाधीशों और बी. सोलोमन से स्पष्टीकरण मांगने के लिए सक्षम थी। चूंकि इसमें अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति थी, इसलिए इसमें अवमानना से संबंधित तथ्यों को पता लगाने की शक्ति भी आवश्यक रूप से निहित थी। पूर्ण पीठ दोनों न्यायाधीशों और बी. सोलोमन एडवोकेट की याचिका स्वीकार करने और विचार करने के लिए सक्षम थी यदि मामले के तथ्यों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं कहा जा सकता था। इसका अर्थ यह होगा कि पूर्ण पीठ के पास अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति थी जो उसने किया। मामले के तथ्यों के आधार पर, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो किसी विधानमंडल के किसी आदेश या निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करता है और विचार करता है, जिसमें याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी अवमानना या उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन के लिए कोई प्रक्रिया जारी की जाती है या जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, वह उक्त विधानमंडल की अवमानना नहीं करता है और उक्त विधानमंडल अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग और प्रवर्तन में ऐसे न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। [534 डी, 537 डी]।

(ix) संविधान के लागू होने के चौदह वर्षों के दौरान, विधानमंडलों ने इस दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं किया है कि वे शक्ति दिए जाने योग्य नहीं हैं। हालांकि अनुच्छेद 211 लागू करने योग्य नहीं है, विधानमंडलों ने संयम की एक सराहनीय भावना दिखाई है और इन सभी वर्षों में एक बार भी न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की है। हमें अपने लोगों पर विश्वास नहीं खोना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि विधानमंडल संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे या यह कि न्यायिक सुधार में सुरक्षा निहित है। ऐसा सुधार अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। एक आधुनिक राज्य में देश की भलाई के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि विभिन्न प्राधिकारियों में समानांतर शक्तियां मौजूद हों। यह अपरिहार्य नहीं है कि ऐसी शक्तियों में टकराव होगा। [541 सी-ई]।

परामर्श अधिकारिता विशेष संदर्भ सं. १ सन् १९६४

भारत के संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत विशेष संदर्भ

सी.के. दफतरी, अटॉर्नी जनरल, एच.एन. सान्याल, सॉलिसिटर जनरल, एस.वी. गुप्ते, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बी.आर.एल. अग्रवाल और आर.एच. ढेबर, भारत संघ की ओर से।

एम.सी. सीतलवाड़, जी.एस. पाठक, जगदीश स्वरूप, एस.एन. एंडले, पी.एल. वोहरा, रामेश्वर नाथ, महिंदर नारायण, हरश के. पुरी और सुरेश वोहरा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की ओर से।

जी.एस. पाठक, जगदीश स्वरूप, बिशुन सिंह, गोपाल बिहारी, जे.एस. त्रिवेदी, एस.एन. पवनिकर, एस.एन. एंडले, पी.एल. वोहरा और रामेश्वर नाथ, माननीय न्यायमूर्ति एन.यू. बेग की ओर से।

एन.सी. चटर्जी, आसिफ अंसारी, एम.के. राममूर्ति और आर.के. गर्ग, माननीय न्यायमूर्ति जी.डी. सहगल की ओर से।

एच. एम. सीरवई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र, टी. आर. अंध्यारुजिना और एस.पी. वर्मा, उ.प्र. विधान सभा की ओर से।

एन.ए. पालकीवाला, जे.बी. दादावंजी, ओ.सी. माथुर और रविंदर नारायण माननीय मुख्य न्यायाधीश, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की ओर से।

जे. एम. ठाकुर, महाधिवक्ता, गुजरात, जे. बी. दादावंजी, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण, माननीय मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से।

डी. नरसाराजू, एन. रामदार, ओ.पी. मल्होत्रा, बी. पार्थसारथी, जे.बी. दादावंजी, ओ.सी. माथुर, और रविंदर नारायण, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय की ओर से।

मुरली मनोहर व्यास, एस. मूर्ति, बी.एन. कृपाल, बी.एल. खन्ना, के. के. जैन, चितले और एम. एस. गुप्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से।

मुरली मनोहर, एस. मूर्ति, बी. एन. कृपाल, बी. एल. खन्ना, के. के. जैन, चितले और एम. एस. गुप्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से।

डी.पी. सिंह, एस. बालकृष्णन, शांति भटनागर और लाल नारायण सिंह, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की ओर से।

ए.सी. मित्रा और डी.एन. मुखर्जी, माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा की ओर से।

एस. एस. सान्याल, एस. के. आचार्य और डी. एन. मुखर्जी, माननीय अध्यक्ष, प.बं. विधान परिषद की ओर से।

एच.एम. सीरवई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र, टी.आर. आनन्दार्जिना, आर.ए. गंगराट और वी.जे. मर्वेट, माननीय अध्यक्ष/सभापति महाराष्ट्र विधान सभा एवं विधान परिषद की ओर से।

जी.एन. जोशी, अतीकुर रहमान और के.एल. हाथी, माननीय अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा की ओर से।

अतीकुर रहमान और के.एल. हाथी, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ओर से।

बी.सी. बरुआ, महाधिवक्ता, असम और नौनित लाल, माननीय अध्यक्ष, असम विधान सभा की ओर से।

डी.एम. सेन, महाधिवक्ता, नागालैंड और नौनित लाल, नागालैंड विधान सभा की ओर से।

बी.पी. झा, माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् एवं माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की ओर से।

के.एल. मिश्रा, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, बी.सी. मिश्र, डी.डी. चौधरी और सी.पी. लाल, उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता की ओर से।

एम. अधिकारी, महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश और आई. एन. श्राफ मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता की ओर से ।

एन. कृष्णास्वामी रेड्डी, महाधिवक्ता, मद्रास, वी. रामास्वामी और ए.वी. रंगम, मद्रास राज्य के महाधिवक्ता की ओर से।
बी.टी. सुब्रमण्यम, महाधिवक्ता, आंध्र प्रदेश राज्य, एम. जगनधा राव और टी.टी.आर. ताताचारी, आंध्र प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता की ओर से।

बी. सेन, एस.सी. बोस और पी.के. बोस, पश्चिम बंगाल राज्य के महाधिवक्ता की ओर से।

जी.सी. कासलीवाल, राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता, एम. वी. गोस्वामी, राजस्थान राज्य की ओर से।

बिहार राज्य की ओर से अधिवक्ता एस.पी. वर्मा।

जे.पी. गोयल, मेसर्स केशव सिंह और बी. सोलोमन की ओर से।

एम. के. नंबियार और एन. एन. केसवानी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से।

अवध बार एसोसिएशन की ओर से एम.के. नंबियार, चौधरी हैदर हुसैन, बीके धवन, बिशुन सिंह, शिव शास्त्री और एसएस शुक्ला।

आर. जेठमलानी, पी.के. कपिला, ए.के. नाग वेस्टर्न इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन (हस्तक्षेपकर्ता) की ओर से।

एसएन कक्कड़, सीएस सरन, जीपी गुप्ता और एससी अग्रवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (हस्तक्षेपकर्ता) के लिए।

एम.के. नंबियार और वी.ए. सैयद मुहम्मद, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (हस्तक्षेपकर्ता) की ओर से ।

आवेदकों-हस्तक्षेपकर्ताओं (ए) लोक रक्षा समाज (सेवक), (बी) ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज काउंसिल (सी) सपू लॉ सोसायटी की ओर से आर. वी. एस. मणि, शौकत हुसैन, ई. सी. अग्रवाल, शहजादी मोहिउद्दीन और पी. सी. अग्रवाल: आवेदक-हस्तक्षेपकर्ता दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की ओर से एम. के. राममूर्ति, आर. के. गर्ग, डी. पी. सिंह और एस. सी. अग्रवाल।

आवेदक-हस्तक्षेपकर्ता, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से के. राजेंद्र चौधरी और के. आर. चौधरी।
चिंता सुब्बा राव, आवेदक-हस्तक्षेपकर्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की ओर से।

मु. न्या. गजेंद्रगडकर ने न्यायमूर्ति सुब्बा राव, न्यायमूर्ति वांचू, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ,
न्यायमूर्ति शाह और न्यायमूर्ति राजगोपाल अयंगर की ओर से और स्वयं अपनी राय दी।

न्यायमूर्ति सरकार ने अलग से अपनी राय दी।

मु. न्या. गजेंद्रगडकर: यह विशेष संदर्भ सं. 1 सन् 1964 है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के अंतर्गत इस न्यायालय की राय के लिए पांच प्रश्न तैयार किए हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को इस न्यायालय को विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न संदर्भित करने के लिए अधिकृत करता है जो उसे उत्पन्न हुए प्रतीत हों या जिनके उत्पन्न होने की संभावना है और जो इस प्रकार के हैं तथा ऐसे सार्वजनिक महत्व के हैं कि उन पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। अनुच्छेद 143(1) में यह प्रावधान है कि जब ऐसे प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय को संदर्भित किए जाते हैं, तो न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात, जिसे वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय से अवगत करा सकता है। 26 मार्च, 1964 को दिए गए अपने संदर्भ आदेश में राष्ट्रपति ने अपना निष्कर्ष व्यक्त किया है कि संदर्भ आदेश में निर्धारित विधि के प्रश्न इस प्रकार के हैं तथा ऐसे सार्वजनिक महत्व के हैं कि उन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है।

ऐसा प्रतीत होता है कि 14 मार्च, 1964 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने विधान सभा (इसके पश्चात "सदन" के रूप में संदर्भित) के नाम से तथा उसके आदेश के तहत, केशव सिंह, जो गोरखपुर के निवासी हैं, को सदन की अवमानना करने तथा सदन के सदस्य नरसिंह नारायण पांडे के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई थी। अवमानना तथा विशेषाधिकारों का उल्लंघन एक पुस्तिका के कारण हुआ था, जिसे मुद्रित तथा प्रकाशित किया गया था तथा जिस पर अन्य व्यक्तियों के साथ केशव सिंह के भी हस्ताक्षर थे। उसी दिन सदन द्वारा बाद में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि केशव सिंह को सदन में अपने आवरण द्वारा, जब उन्हें उक्त फटकार के लिए समन किया गया था, सदन की एक और अवमानना करने तथा सदन के अध्यक्ष को पहले अपमानजनक पत्र लिखने के लिए जेल भेजा जाए। इस आदेश के अनुसार, सदन के अध्यक्ष श्री वर्मा के हस्ताक्षर से एक वारंट जारी किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि केशव सिंह को सात दिनों की अवधि के लिए जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध किया जाए, और वारंट के निष्पादन में केशव सिंह को जेल में निरुद्ध किया गया।

19 मार्च, 1964 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में वकालत करने वाले अधिवक्ता श्री बी. सोलोमन ने केशव सिंह की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 491 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। इस याचिका में सदन के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला कारागार, लखनऊ के अधीक्षक, जहां केशव सिंह सदन द्वारा उन पर लगाए गए दण्ड के तहत कारावास की सजा काट रहे थे, को क्रमशः प्रत्यर्थी 1 से 4 के रूप में प्रत्यर्थी बनाया गया था। इस प्रकार केशव सिंह की ओर से प्रस्तुत याचिका में आरोप लगाया गया कि जेल में उनका निरुद्ध होना कई आधारों पर अवैध था। याचिका के अनुसार, केशव सिंह को फटकार लगाने के बाद जेल में बंद करने का आदेश दिया गया था, और इससे कारावास का आदेश अवैध और प्राधिकार रहित हो गया। याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि केशव सिंह को अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें निरुद्ध किया जाना दुर्भावनापूर्ण था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था। उनका यह भी कहना था कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के पास उन्हें जिला जेल, लखनऊ भेजने का कोई प्राधिकार नहीं था, और इससे जेल में उन्हें निरुद्ध किया जाना अवैध था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में उक्त याचिका दायर होने के बाद दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता दोपहर 2 बजे न्यायमूर्ति बेग और न्यायमूर्ति सहगल के समक्ष उपस्थित हुए और इस बात पर सहमत हुए कि याचिका पर उसी दिन अपराह्न 3 बजे सुनवाई की जानी चाहिए। श्री सोलोमन ने केशव सिंह का प्रतिनिधित्व किया और श्री के. एन. कपूर, सहायक शासकीय अधिवक्ता सभी प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए। तदनुसार, याचिका अपराह्न 3 बजे न्यायालय में सुनवाई के लिए ली गई। इस अवसर पर श्री सोलोमन याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए लेकिन श्री कपूर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने आदेश पारित किया कि आवेदक

को जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की संतुष्टि के लिए 1,000 रुपये की राशि के दो जमानतदार और इतनी ही राशि का निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। न्यायालय के उप रजिस्ट्रार को आदेश के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदक भविष्य में मामले की प्रत्येक सुनवाई में न्यायालय में उपस्थित रहेगा। इस प्रकार, याचिका स्वीकार कर ली गई और प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया, साथ ही यह अतिरिक्त निर्देश भी दिया गया कि मामले की सुनवाई यथाशीघ्र की जाए। यह 19 मार्च को अपराह्न 3 बजे हुआ।

20 मार्च, 1964 को शासकीय अधिवक्ता श्री श्रीराम ने श्री निगम, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्यायिक विभाग, लखनऊ को पत्र लिखकर केशव सिंह के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी दी। इस पत्र में श्री श्रीराम ने कहा है कि मामला अपराह्न 2 बजे न्यायालय के समक्ष उल्लेखित किए जाने के बाद पक्षकारों के अनुरोध पर इसे अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया; इसके तुरंत बाद श्री कपूर ने श्री निगम से फोन पर संपर्क किया, लेकिन जब बातचीत चल रही थी, न्यायालय ने अपराह्न 3 बजे मामले की सुनवाई की और केशव सिंह को उन शर्तों व नियमों पर रिहा करने का आदेश पारित किया, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। श्री श्रीराम ने केशव सिंह द्वारा दिए गए आवेदन की तीन प्रतियां श्री निगम को भेजी और सुझाव दिया कि संबंधित व्यक्तियों का उचित हलफनामा बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने श्री निगम को यह भी बताया कि आवेदन को बहुत जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।

शासकीय अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध का अनुपालन करने और केशव सिंह द्वारा दिए गए आवेदन में रिटर्न दाखिल करने का निर्देश देने के बजाय, सदन ने केशव सिंह के आवेदन पर आदेश पारित करने वाले दो विद्वान न्यायाधीशों के खिलाफ, साथ ही केशव सिंह और उनके अधिवक्ता के खिलाफ 21 मार्च, 1964 को कार्रवाई की। ऐसा प्रतीत होता है कि सदन के दो सदस्यों ने 20 मार्च को सदन के अध्यक्ष के ध्यान में लाया कि केशव सिंह द्वारा दिए गए आवेदन के संबंध में न्यायालय के समक्ष क्या हुआ था। केशव सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए, सदन ने 21 मार्च, 1964 को एक प्रस्ताव पारित किया कि मेसर्स जी.डी. सहगल, एन.यू. बेग, केशव सिंह और बी. सोलोमन ने सदन की अवमानना की थी और इसलिए यह आदेश दिया गया कि केशव सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उनकी कैद की शेष अवधि के लिए उन्हें जिला जेल, लखनऊ में निरुद्ध किया जाए और मेसर्स एन.यू. बेग, जी.डी. सहगल और बी. सोलोमन को हिरासत में सदन के समक्ष लाया जाए। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि केशव सिंह द्वारा अपनी कैद की अवधि पूरी करने के बाद, उन्हें 19 मार्च, 1964 को सदन की पुनः अवमानना करने के लिए सदन के समक्ष लाया जाना चाहिए।

दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने 21 मार्च की शाम को रेडियो पर इस प्रस्ताव के बारे में सुना और 22 मार्च, 1964 को प्रकाशित नार्दन इंडिया पत्रिका के सुबह के संस्करण में इसके बारे में पढ़ा। यही कारण है कि वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अलग-अलग याचिकाओं के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि सदन द्वारा पारित आक्षेपित प्रस्ताव पूरी तरह से असंवैधानिक था और संविधान के अनुच्छेद 211 के प्रावधानों का उल्लंघन करता था। याचिकाओं के अनुसार, केशव सिंह द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत किया गया आवेदन सक्षम था और केशव सिंह को रिहा करने का आदेश देने में, न्यायाधीश अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी अधिकारिता और प्राधिकार का प्रयोग कर रहे थे। उनका तर्क था कि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव न्यायालय की अवमानना के बराबर है और चूंकि यह अधिकारिता रहित था, इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए और एक अंतरिम आदेश द्वारा इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी जानी चाहिए। ये याचिकाएं 23 मार्च, 1964 को दायर की गई थीं।

इस बात की आशंका के चलते कि इन घटनाक्रमों ने एक बहुत गंभीर समस्या को जन्म दिया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 28 न्यायाधीशों वाली एक पूर्ण पीठ ने उसी दिन लखनऊ के अपने दो सहयोगियों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं पर विचार किया, निर्देश

दिया कि उक्त याचिकाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थियों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें अध्यक्ष को 21 मार्च, 1964 को दिए गए सदन के निर्देश के अनुसरण में वारंट जारी करने और यदि वारंट जारी हो चुका है तो उसके निष्पादन को सुनिश्चित करने से रोका गया और उत्तर प्रदेश सरकार और सदन के मार्शल को वारंट को निष्पादित करने से रोका गया।

इस बीच, 25 मार्च, 1964 को केशव सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री सोलोमन ने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक समान याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दायर याचिकाओं के समान ही परमादेश रिट के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने आग्रह किया कि सदन के खिलाफ उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने न्यायालय की अवमानना की है। अपनी याचिका में श्री सोलोमन ने सात प्रत्यर्थियों को पक्षकार बनाया था; वे थे: सदन के अध्यक्ष, श्री वर्मा: विधान सभा, उ.प्र.; उ.प्र. विधान सभा के मार्शल: श्री सरन और श्री अहमद, उ.प्र. विधान सभा के सदस्य, जिन्होंने उच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों को सदन के ध्यान में लाया; और उत्तर प्रदेश राज्य।

इस आवेदन पर 25 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 28 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ द्वारा फिर से सुनवाई की गई, और याचिका को स्वीकार करने के बाद, प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसकी वैधता को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी। इस याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता को नोटिस दिया गया था। उन्होंने न्यायालय को बताया कि उस समय आवेदन का विरोध करने के लिए उनके पास कोई निर्देश नहीं था। इसीलिए न्यायालय ने आवेदन का नोटिस जारी किया तथा जो उचित समझा, उसे पारित किया।

उसी दिन सदन ने स्पष्टीकरण प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव इस कथन के साथ शुरू हुआ कि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के संबंध में संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि इसे संबंधित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण के अवसर से वंचित करने के रूप में समझा जा सकता है, तथा इसमें यह भी कहा गया कि सदन का यह कभी भी इरादा नहीं था कि विशेषाधिकार का उल्लंघन करने या सदन की अवमानना करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप का निस्तारण उससे भिन्न तरीके से किया जाए जैसा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन या अवमानना के मामले में किया जाता है। इसलिए सदन ने संकल्प लिया कि अवमानना के प्रश्न का निर्णय 20 मार्च, 1964 के मूल प्रस्ताव में नामित व्यक्तियों को नियमों के अनुसार स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, दोनों विद्वान न्यायाधीशों और श्री सोलोमन की गिरफ्तारी के लिए जारी किए गए वारंट वापस ले लिए गए, जिसके परिणामस्वरूप दोनों विद्वान न्यायाधीशों और श्री सोलोमन को सदन के समक्ष उपस्थित होने और यह स्पष्टीकरण देने का दायित्व दिया गया कि सदन को सदन की कथित अवमानना के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिए।

जब 19 मार्च से 25 मार्च, 1964 तक इतनी जल्दी-जल्दी घटित हुई घटनाएं इस स्तर पर पहुंच गईं, तो राष्ट्रपति ने 26 मार्च, 1964 को संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत इस न्यायालय को संदर्भ देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। संदर्भ आदेश से पता चलता है कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हुआ कि विचाराधीन घटनाओं ने उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल के बीच गंभीर संघर्ष को जन्म दिया है, जिसमें राज्य विधानमंडल और उसके अधिकारियों के संबंध में उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के संबंध में राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में कानून के महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न शामिल थे। राष्ट्रपति इस बात से भी संतुष्ट थे कि उनके संदर्भ आदेश में निर्धारित कानून के प्रश्न ऐसी प्रकृति

और ऐसे सार्वजनिक महत्व के थे कि उन पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन था। यही वर्तमान संदर्भ की उत्पत्ति है।

इस संदर्भ के अंतर्गत इस न्यायालय को भेजे गए प्रश्न इस प्रकार हैं :-

(1) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति एन. यू. बेग और माननीय न्यायमूर्ति जी. डी. सहगल शामिल हैं, द्वारा श्री केशव सिंह की याचिका स्वीकार करने और उस पर विचार करने में सक्षम थी, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उसकी अवमानना और उसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उन्हें दी गई कारावास की सजा की वैधता को चुनौती दी गई थी और श्री केशव सिंह को उनकी उक्त याचिका के निस्तारण तक जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया था;

(2) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर श्री केशव सिंह ने अपनी ओर से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करवाकर, अधिवक्ता श्री बी. सोलोमन ने उक्त याचिका प्रस्तुत करके और उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों ने उक्त याचिका को स्वीकार करके और उस पर विचार करके तथा उक्त याचिका के निस्तारण तक श्री केशव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर उत्तर प्रदेश विधान सभा की अवमानना की थी;

(3) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों और श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता को हिरासत में अपने समक्ष पेश करने का निर्देश देने या अपनी अवमानना के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगने में सक्षम थी;

(4) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों और श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता, की याचिकाओं को स्वीकार करने और उन पर विचार करने तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और उक्त याचिकाओं के अन्य प्रत्यर्थियों को उक्त विधान सभा के पूर्वोक्त निर्देश को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने में सक्षम थी; और

(5) क्या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जो विधानमंडल के किसी आदेश या निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करता है या उस पर विचार करता है, जिसमें याचिकाकर्ता पर कोई दंड लगाया गया हो या याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी अवमानना या उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन के लिए कोई प्रक्रिया जारी की गई हो या जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता हो, उक्त विधानमंडल की अवमानना करता है और क्या उक्त विधानमंडल अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग और प्रवर्तन में ऐसे न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

इस संदर्भ की सुनवाई के दौरान, श्री वर्मा ने बिहार के महाधिवक्ता की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। उनका तर्क है कि वर्तमान संदर्भ अनुच्छेद 143(1) के तहत अमान्य है क्योंकि इस न्यायालय को भेजे गए प्रश्न सूची I और III में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं हैं और इस प्रकार, उन्हें संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई किसी भी शक्ति, कर्तव्य या कार्य से संबंधित नहीं कहा जा सकता है। तर्क यह प्रतीत होता है कि केवल राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में ही वह अनुच्छेद 143(1) के तहत इस न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए प्रश्न तैयार करने के लिए सक्षम होगा। हमारी राय में, यह तर्क पूरी तरह से गलत है। अनुच्छेद 143(1) के शब्द राष्ट्रपति को किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न को, जो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, सलाहकारी राय के लिए इस न्यायालय को अग्रणी करने के लिए सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त हैं, बशर्ते कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा प्रश्न ऐसी प्रकृति का या ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि इस पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। यह बिल्कुल सच है कि

अनुच्छेद 143(1) के तहत भले ही प्रश्न इस न्यायालय को सलाहकारी राय के लिए भेजे गए हों, यह न्यायालय हर मामले में ऐसी सलाहकारी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को इस न्यायालय द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद, वह ऐसी सुनवाई के बाद, जैसा वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकता है। अनुच्छेद 143 (2) द्वारा निर्धारित प्रावधान में "करेगा" शब्द के विपरीत "कर सकता है" शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप

से इस तथ्य को सामने लाता है कि किसी दिए गए मामले में, यह न्यायालय सम्मानपूर्वक अपनी सलाहकारी राय व्यक्त करने से इंकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उसे भेजे गए प्रश्नों की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद 143(2) उन मामलों से संबंधित है जिनमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक द्वारा निर्धारित निषेध के बावजूद इस न्यायालय को कोई विवाद संदर्भित कर सकता है, और यह जोड़ता है कि जब ऐसा संदर्भ किया जाता है, तो न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद, जैसा वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय की रिपोर्ट करेगा। दूसरे शब्दों में, जहाँ अनुच्छेद 143 (2) के तहत किए गए संदर्भ के मामले में यह इस न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है कि वह अपनी सलाहकारी राय को शामिल करते हुए उस संदर्भ पर रिपोर्ट करे, अनुच्छेद 143(1) के तहत किए गए संदर्भ में ऐसा कोई दायित्व नहीं है। संदर्भ के इस उत्तरार्द्ध वर्ग के संबंध में, यह न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या उसे संदर्भित प्रश्नों पर अपनी सलाहकार राय देते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी चाहिए या नहीं।

हालाँकि, इस स्थिति का श्री वर्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न पर कोई असर नहीं पड़ता है। श्री वर्मा द्वारा उठाई गई आपत्ति की वैधता का मूल्यांकन अनुच्छेद 143(1) के शब्दों के प्रकाश में ही किया जाना चाहिए और ये शब्द इतने व्यापक आयाम के हैं कि इस तर्क को स्वीकार करना असंभव होगा कि श्री वर्मा द्वारा सुझाए गए संकीर्ण परीक्षण को ही संदर्भ की वैधता निर्धारित करने में लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 143(1) की अपेक्षा यह है कि राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उठ चुका है या उठने की संभावना है। उसे इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा प्रश्न ऐसी प्रकृति का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि इस पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। प्रथम दृष्टया, इन दोनों मामलों में राष्ट्रपति की संतुष्टि संदर्भ को उचित ठहराएगी, और जब यह न्यायालय ऐसा महसूस करता है कि इस पर अपनी सलाहकारी राय व्यक्त करना उसके लिए उचित नहीं होगा, तभी वह कोई भी राय व्यक्त करने से सम्मानपूर्वक इनकार कर सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वर्तमान मामले में यह सुझाव देना असंभव होगा कि तथ्य और कानून के जो प्रश्न इस न्यायालय को संदर्भित किए गए हैं, वे उत्पन्न नहीं हुए हैं और वे काफी सार्वजनिक महत्व के नहीं हैं। इसलिए, हमें नहीं लगता कि श्री वर्मा द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार है।

वर्ष, 1950 में संविधान को अपनाए जाने के बाद से इस न्यायालय में किए गए संदर्भ यह दर्शाते हैं कि संदर्भ की उपयुक्तता या वैधता का निर्धारण करने में श्री वर्मा द्वारा सुझाए गए संकीर्ण परीक्षण को लागू करना अनुचित होगा। दिल्ली कानून अधिनियम, 1912, अजमेर-मेरवाड़ा (कानूनों का विस्तार) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (कानून अधिनियम, 1951) के सारवान प्रावधानों की वैधता और संवैधानिकता के प्रश्न पर इस न्यायालय की सलाहकारी राय प्राप्त करने के लिए पहला विशेष संदर्भ सं. 1 सन् 1951 इस न्यायालय के समक्ष किया गया था। दूसरा विशेष संदर्भ सन् 1958 में किया गया था। यह केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के कतिपय प्रावधानों की वैधता के संदर्भ में था, जिसे केरल विधानसभा ने पारित किया था, लेकिन राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया था। तीसरा विशेष संदर्भ सन् 1959 में किया गया था और इसने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच एक समझौते के सारवान प्रावधानों की वैधता के संबंध में इस न्यायालय की सलाहकारी राय मांगी थी, जिसे भारत-पाकिस्तान समझौता कहा गया था। चौथा संदर्भ सन् 1962 में दिया गया था, इस संदर्भ द्वारा राष्ट्रपति ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के उद्देश्य से संसद में पेश किए जाने वाले मसौदा विधेयक के प्रासंगिक प्रावधानों पर सलाहकारी राय मांगी थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत इस न्यायालय की सलाहकार राय के लिए अब तक भेजे गए प्रश्न एक समान पैटर्न पर आधारित नहीं करते हैं और यह अनुच्छेद 143(1) में प्रयुक्त व्यापक शब्दों के साथ बिल्कुल सुसंगत है।

इस बात पर जोर देना शायद ही आवश्यक है कि वर्तमान अवसर पर इस न्यायालय को भेजे गए कानून के प्रश्न बहुत बड़े संवैधानिक महत्व के हैं। जिन घटनाओं ने इस संदर्भ को जन्म दिया है, उन्होंने एक बहुत ही कठिन समस्या खड़ी कर दी है और जब तक दोनों प्रतिष्ठित निकायों द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में आने की घटनाओं को रोका नहीं जाता, तब तक वे एक बहुत ही गंभीर और कठिन स्थिति को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति ने यह विचार किया कि इस न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए संदर्भ का मामला स्थापित हो चुका है। अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए विद्यमान कानूनों के आरोपित प्रावधानों की वैधता से संबंधित तथ्य और विधि के प्रश्न तैयार करने का अधिकार हो सकता है; विधानमंडलों के समक्ष आने वाले विधेयकों में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रावधानों की वैधता के

संबंध में प्रश्न तैयार करने का विकल्प हो सकता है; वर्तमान जैसे संवैधानिक महत्व के प्रश्नों को इस न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए तैयार करने का भी उनके पास विकल्प है; और यह हो सकता है कि राष्ट्रपति हमारे उत्तर प्राप्त करने पर विचार करें कि क्या संघ सरकार या राज्य सरकार से इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय के अनुसार कोई उपयुक्त या समुचित कार्रवाई, चाहे वह विधायी हो या कार्यकारी, करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। इसलिए हमें यह मानने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है कि वर्तमान संदर्भ सक्षम है।

जैसा कि हम पहले ही संकेत कर चुके हैं, जब अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत इस न्यायालय को संदर्भ प्राप्त होता है, तो यह न्यायालय किसी दिए गए मामले में पर्याप्त और संतोषजनक कारणों से राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर अपने उत्तरों वाली रिपोर्ट देने से सम्मानपूर्वक इनकार कर सकता है; ऐसी स्थिति शायद तब उत्पन्न हो सकती है जब इस न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए तैयार किए गए प्रश्न विशुद्ध रूप से सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक प्रश्न हों जिनका संविधान के किसी भी प्रावधान से कोई संबंध न हो, या अन्यथा उनका कोई संवैधानिक महत्व न हो। इस न्यायालय को ऐसे मजबूत और बाध्यकारी कारणों से प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान ने अनुच्छेद 143(1) में 'कर सकते हैं' शब्द का प्रयोग किया गया है जो अनुच्छेद 143(2) में प्रयुक्त 'करेगा' शब्द से अलग है। वर्तमान मामले में, हमारी स्पष्ट राय है कि हमारी सलाहकारी राय के लिए तैयार किए गए प्रश्न गंभीर संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रपति को उनके द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर अपने उत्तरों को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट दें।

इससे हम उस विवाद के मेरिट पर पहुँचते हैं, जिसका खुलासा राष्ट्रपति द्वारा हमारी सलाहकारी राय के लिए तैयार किए गए प्रश्नों द्वारा किया गया है। इस संदर्भ पर हमारे समक्ष विस्तृत रूप से बहस की गई है। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने हमारे समक्ष कार्यवाही शुरू की और संदर्भ की ओर ले जाने वाले प्रासंगिक तथ्यों को बताया, तथा मोटे तौर पर उन प्रतिद्वंद्वी तर्कों को इंगित किया, जिन्हें सदन और उच्च न्यायालय ने अपनी ओर से दायर मामले के बयानों के माध्यम से हमारे समक्ष उठाने का प्रयास किया था। महाराष्ट्र के विद्वान एडवोकेट जनरल श्री सीरवई सदन की ओर से उपस्थित हुए तथा न्यायालय के समक्ष एक बहुत ही विद्वत, प्रभावशाली और विस्तृत तर्क प्रस्तुत किया। उनके बाद कई विद्वान अधिवक्ता आए, जिन्होंने सदन द्वारा अपनाए गए रुख का मोटे तौर पर समर्थन किया। श्री सीतलवाड़, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ओर से उपस्थित हुए, ने अपनी विशिष्ट संक्षिप्तता और स्पष्टता के साथ हमारे समक्ष एक बहुत ही सक्षम तर्क प्रस्तुत किया; और उनके बाद, कई विद्वान अधिवक्ता आए, जिन्होंने न्यायाधीशों द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन किया। बहस के दौरान, हमारे समक्ष कई उपधारणाएं प्रस्तुत की गईं तथा संवैधानिक कानून के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया गया। इसलिए, हमें शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय, हम केवल ऐसे बिंदुओं पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, जो हमारी राय में, "उक्त प्रश्नों द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर प्रत्यक्ष और सारवान प्रभाव डालते हैं। इस बात पर जोर देना शायद ही आवश्यक है कि संवैधानिक मामलों पर विचार करते समय न्यायालय को उन प्रश्नों पर विचार करने की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जो सीधे उत्पन्न नहीं होते हैं।" अनुच्छेद 143(1) के तहत इस न्यायालय को किए गए संदर्भ के संबंध में यह सतर्कता और भी आवश्यक है।

तो आइए हम सदन की ओर से और न्यायाधीशों और अधिवक्ता की ओर से उठाए गए मुख्य तर्कों को मोटे तौर पर बताते हुए शुरू करें। श्री सीरवई ने इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए अपने तर्क शुरू किए कि अनुच्छेद 143(1) के तहत संदर्भ पर विचार करते समय न्यायालय वह नहीं कर रहा है जिसे उसका न्यायिक कार्य कहा जा सकता है। ऐसे संदर्भ में न्यायालय के समक्ष कोई पक्ष नहीं होता है और कोई वाद नहीं होता है। इसलिए संदर्भ पर न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय सलाहकारी होती है; और इसलिए, उनका तर्क है कि हालांकि वे सदन की ओर से वर्तमान संदर्भ में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सदन प्रश्नों द्वारा कवर किए गए विवाद के क्षेत्र के संबंध में किसी भी तरह से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कहा कि हमारे सामने उनकी

उपस्थिति उनके मुख्य तर्क के प्रति पूर्वाग्रह के बिना थी कि सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अस्तित्व और सीमा के बारे में प्रश्न, साथ ही शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के बारे में प्रश्न पूरी तरह से और अनन्य रूप से सदन की अधिकारिता में थे; और यह न्यायालय जो कुछ भी कहे, वह सदन को इस संदर्भ के तहत हमारे पास भेजे गए मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने से नहीं रोकेगा। यह रुख इस आधार पर आधारित था कि हमारे द्वारा व्यक्त की गई राय परामर्शदायी प्रकृति की है और न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच न्यायिक न्यायनिर्णयन की प्रकृति की नहीं है।

श्री सीरवाई ने संविधान के अनुच्छेद 194(3) के संबंध में भी यही रुख अपनाया। अनुच्छेद 194(3) विधानमंडलों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में प्रश्न से संबंधित है। हमें बाद में इस अनुच्छेद के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। फिलहाल, यह कहना पर्याप्त है कि श्री सीरवाई के अनुसार, अनुच्छेद 194(3) के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करना तथा स्वयं निर्धारित करना सदन का विशेषाधिकार है कि उसकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्या हैं, तथा ऐसा होने पर, अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों के अस्तित्व और सीमा से संबंधित प्रश्नों पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय, सदन को इस न्यायालय के विचारों से अप्रभावित होकर स्वयं उन प्रश्नों का निर्धारण करने से नहीं रोकेगी।

इस प्रकार सदन द्वारा अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों के संबंध में किए जाने वाले दावे के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद, श्री सीरवाई ने तर्क दिया कि इंग्लैंड में भी न्यायपालिका और संसद द्वारा दावा किए गए दो प्रतिद्वंद्वी अधिकार क्षेत्रों के बीच यह द्वैतवाद हमेशा से मौजूद रहा है और यह अभी भी अनसुलझा है। कुछ अवसरों पर, न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच विवाद ने बहुत ही कटु रूप धारण कर लिया और इसने दो संबंधित प्रतिष्ठित निकायों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों में पूर्ण विरोधाभास या अन्तर्विरोध को उजागर किया है। न्यायालयों ने दावा किया कि उन्हें संबंधित शक्तियों और विशेषाधिकारों के अस्तित्व और सीमा से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय देने का अधिकार है और संसद ने 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान इस संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देने से लगातार इनकार किया। संसद ने स्वीकार किया कि वह कोई नया विशेषाधिकार नहीं बना सकती, लेकिन उसने खुद को मौजूदा विशेषाधिकारों का एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश मानने पर जोर दिया और यह निर्धारित करने के लिए अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी कि वे क्या थे, या उनके उल्लंघन से कैसे निपटें, और दोषी नागरिकों को कैसे दंडित करें। दूसरी ओर, न्यायालयों ने विशेषाधिकार हनन के आधार पर संसद द्वारा पारित आदेशों की वैधता की जांच करने पर जोर दिया, और इस प्रकार उजागर हुआ द्वैतवाद कई वर्षों तक कायम रहा।

श्री सीरवाई का तर्क है कि जिस सदन के लिए वे उपस्थित हुए हैं, वह उसी रुख पर कायम है जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने ऐसे ही विवादों में अपनाया था, जिसके कारण अतीत में कई मौकों पर न्यायपालिका और उसके बीच टकराव हुआ था। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, वे केशव सिंह द्वारा अपनी रिट याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से इनकार करते हैं। तार्किक रूप से, उनका तर्क यह है कि केशव सिंह और उनके अधिवक्ता द्वारा याचिका प्रस्तुत करना सदन की अवमानना के बराबर है, और जब विद्वान न्यायाधीशों ने याचिका पर विचार किया और उस पर अंतरिम आदेश पारित किया, तो उन्होंने सदन की अवमानना की। सदन द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया है, और इस दृष्टिकोण की औचित्य, शुद्धता या वैधता इस देश में न्यायपालिका द्वारा जांच योग्य नहीं है।

वैकल्पिक रूप से, श्री सीरवाई ने अपने तर्क को थोड़े अलग आधार पर रखा। उन्होंने माना कि इंग्लैंड में एक सदी से भी अधिक समय से यह विवाद न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच समझौते से काफी हद तक सुलझा हुआ माना जा सकता है। अब ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने यह मान लिया है कि विशेषाधिकार के अस्तित्व और सीमा की जांच न्यायालयों द्वारा की जा सकती है। ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने यह भी मान लिया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग

करते हुए वह आख्यापक वारंट जारी करता है, तो न्यायालय के लिए यह विचार करने का विकल्प खुला होगा कि वारंट में बताए गए कारण अवमानना के बराबर हैं या नहीं। इस सीमित सीमा तक, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को मान्यता दी गई है और पिछली शताब्दी से लगातार, जब भी इसकी अवमानना के लिए पारित आदेशों को उचित ठहराना आवश्यक हुआ है, तो हमेशा न्यायालयों में रिटर्न दाखिल किया गया है। हालांकि, श्री सीरवाई इस तथ्य पर जोर देते हैं कि विशेषाधिकार की प्रकृति और सीमा के बारे में प्रश्न पर न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच इस बड़े पैमाने पर सहमति के परिणामस्वरूप, यह तय माना जाता है कि यदि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के लिए एक अव्यक्त या सामान्य वारंट जारी किया जाता है जो इसकी अवमानना का दोषी है, तो न्यायालय हमेशा उक्त सामान्य वारंट को निर्णायक मानेंगे और सदन द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच नहीं करेंगे। वर्तमान मामले में, श्री सीरवाई के अनुसार, दो विद्वान न्यायाधीशों के साथ-साथ श्री सोलोमन के खिलाफ सदन द्वारा पारित प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव की प्रकृति का है और यद्यपि न्यायाधीशों के खिलाफ जारी किए गए वारंट वापस ले लिए गए हैं, यह स्पष्ट है कि सदन का निर्णय और वारंट जिन्हें शुरू में उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में जारी करने का आदेश दिया गया था, सामान्य प्रस्ताव और सामान्य वारंट की प्रकृति के थे, और इसलिए, यह न्यायालय उन कारणों की जांच करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जिनके लिए उक्त वारंट जारी किए गए थे। विचाराधीन प्रस्ताव और उसके अनुसरण में जारी किए गए वारंट निर्णायक हैं और उन्हें ऐसे ही माना जाना चाहिए। इसलिए, तर्क यह है कि वर्तमान संदर्भ के तहत तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर देते समय, हमें इस स्थिति को प्रभावी बनाना चाहिए जो न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच किसी तरह के निहित समझौते से विकसित हुई प्रतीत होती है। यह सहमति दर्शाती है कि अवमानना के प्रश्नों को निर्णीत करने तथा उक्त अवमानना के लिए दंड की पर्याप्तता तय करने का अधिकार विशेष रूप से सदन का है, तथा यदि उक्त अनन्य शक्ति के अनुसरण में कोई सामान्य वारंट जारी किया जाता है, तो सदन को उक्त वारंट की उत्पत्ति या कारणों को स्पष्ट करने के लिए कभी नहीं कहा जा सकता। यह अपने आप में सदन के विशेषाधिकारों तथा शक्तियों का एक अभिन्न अंग है, तथा सदन के अनुसार यह अभिन्न अंग संविधान के अनुच्छेद 194(3) के परिणामस्वरूप भारत में लाया गया है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि भले ही इस न्यायालय के पास अनुच्छेद 194(3) के दायरे तथा प्रभाव को निर्धारित करने का अधिकार हो, लेकिन उसे यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि एक अव्यक्त सामान्य वारंट जारी करने की यह विशेष शक्ति तथा न्यायपालिका से उक्त वारंट को निर्णायक मानने पर जोर देना उन विशेषाधिकारों का एक हिस्सा है, जिनका अनुच्छेद 194(3) का उत्तरार्द्ध भाग संदर्भित करता है। इसी व्यापक आधार पर श्री सीरवाई चाहते थे कि हम उन प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जो संदर्भ की विषय-वस्तु हैं।

दूसरी ओर, न्यायाधीशों की ओर से श्री सीतलवाड़ ने तर्क दिया कि हमारे संविधान में न्यायपालिका और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच इंग्लैंड में मौजूद द्वैधता को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका तर्क है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद 194(3) की व्याख्या करने का प्रश्न इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है और यह न्यायालय अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध में प्रयुक्त प्रासंगिक शब्दों की जो व्याख्या करेगा, वह अंततः प्रश्नगत विशेषाधिकारों के दायरे, सीमा और चरित्र को निर्धारित करेगा। श्री सीतलवाड़ के अनुसार, अनुच्छेद 194(3) को अलग-थलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि इसे इसके संदर्भ में और अनुच्छेद 32, 211 और 226 जैसे अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। जब अनुच्छेद 194(3) के सारवान भाग को इस प्रकार पढ़ा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय और सदन की शक्तियों के बीच किसी भी विरोधाभास या संघर्ष या द्वैधता को पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो वर्तमान प्रश्नों को जन्म देते हैं। उन्होंने आगे आग्रह किया कि सदन के लिए वह रवैया अपनाना बेकार होगा जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अपनाया था जब उक्त सदन और न्यायपालिका के बीच संघर्ष उत्पन्न हुए थे। श्री सीतलवाड़ कहते हैं कि एक शताब्दी से अधिक समय से हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा यह तर्क देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि यदि किसी नागरिक को उसके द्वारा की गई कथित अवमानना के लिए सदन द्वारा दंडित किया जाता है तो न्यायालय के बंदी प्रत्यक्षीकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत याचिका दायर करने पर वह एक अन्य अवमानना का दोषी होगा, न ही इस अवधि के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किसी अधिवक्ता के खिलाफ, जो

बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है या ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रयास किया गया है; और इसलिए, तर्क यह है कि हमें वर्तमान विवाद से उस आम सहमति के आधार पर निपटना चाहिए जो परंपरा से दो प्रतिष्ठित और शक्तिशाली संस्थाओं, न्यायपालिका और विधायिका के बीच विकसित हुई है।

श्री सीतलवाड़ ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी न्यायालयों में कुछ ऐसी परंपराओं को मान्यता प्राप्त है जिसके तहत वे सदन द्वारा जारी सामान्य या अव्यक्त वारंट को आमतौर पर निर्णायक मानते हैं; लेकिन उनके अनुसार, इस मामले का यह पहलू परंपरा या शिष्टाचार का परिणाम है और इसे सदन के विशेषाधिकार का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। इस परंपरा को विकसित करने का आधार इंग्लैंड के इतिहास में निहित है, क्योंकि एक समय में संसद सर्वोच्च न्यायालय थी और इसी इतिहास के कारण हाउस ऑफ कॉमन्स को भी रिकॉर्ड का एक श्रेष्ठतर न्यायालय माना जाने लगा। वर्तमान कार्यवाही में सदन के संबंध में ऐसी धारणा नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा, सामान्य वारंट के प्रभाव के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32, 211 और 226 के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन तर्कों को मोटे तौर पर आधार बनाते हुए, श्री सीतलवाड़ ने तर्क दिया कि संविधान ने हमारे देश में द्वैधवाद की समस्या का समाधान उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को उन नागरिकों द्वारा किए गए दावों से निपटने के लिए अधिकारिता प्रदान करके किया है, जिनके मौलिक अधिकारों पर आक्रमण किया गया हो, और इसका अर्थ यह है कि इस देश में, यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो यह न्यायालय या उच्च न्यायालय विधायिका सहित किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच करने के लिए सक्षम होगा, और इसमें अनिवार्य रूप से यह परिणाम शामिल होना चाहिए कि एक अव्यक्त वारंट अनन्यता के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। संक्षेप में, व्यापक रूप से, यही वह दृष्टिकोण है जिसे श्री सीतलवाड़ ने हमारे सामने अपनाया है।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए पांच प्रश्नों द्वारा उजागर किया गया मुख्य विवाद अंततः एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में आता है। क्या सदन इस मुद्दे का एकमात्र और अनन्य निर्णायक है कि क्या उसकी अवमानना तब की गई है जब कथित अवमानना सदन की चारदीवारी के बाहर हुई है? क्या सदन उस सजा का एकमात्र और अनन्य निर्णायक है जो उस पक्ष पर लगाई जानी चाहिए जिसे उसने अपनी अवमानना का दोषी पाया है? और, यदि अपने निर्णय के प्रवर्तन में सदन सामान्य या अव्यक्त वारंट जारी करता है, तो क्या उच्च न्यायालय सदन द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की हिरासत की वैधता को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने का हकदार है? सदन की ओर से श्री सीरवाई द्वारा प्रस्तुत तर्क यह है कि सामान्य वारंट के मामले में, वारंट की जाँच पड़ताल करने का उच्च न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है; और वर्तमान मामले में, चूंकि उसने याचिका पर विचार किया है और वारंट की जांच किए बिना केशव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है, और यहां तक कि प्रतिवादियों द्वारा रिटर्न दाखिल किए जाने से पहले भी, उसने अवैध रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया है, और इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, अधिवक्ता और पक्ष सभी सदन की अवमानना के दोषी हैं। श्री सीरवाई ने कहा कि, किसी भी स्थिति में, इस प्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में, उच्च न्यायालय को अंतरिम जमानत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

श्री सीतलवाड़ ने इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया है कि सदन को यह पता लगाने की शक्ति है कि क्या इसकी अवमानना इसकी चारदीवारी के बाहर भी किसी व्यक्ति द्वारा की गई है और ऐसी अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है; लेकिन उनका तर्क यह है कि हमारे संविधान के सारवान प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सदन के पास यह दावा करने का विकल्प नहीं होगा कि इसके सामान्य वारंट को निर्णायक माना जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में जहां किसी पक्ष को सदन द्वारा अवमानना के लिए सजा सुनाई गई हो और उसे निरुद्ध किया गया हो, तो उसके लिए अनुच्छेद 226 के तहत उचित राहत के लिए उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होगा और उच्च न्यायालय उसके तर्कों के गुण-दोष की जांच करने का हकदार होगा, भले ही वारंट सामान्य या अव्यक्त हो।

श्री सीतलवाड़ के अनुसार, चूंकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार है, इसलिए उसके पास अंतरिम जमानत का आदेश पारित करने की भी शक्ति है। इस प्रकार, विवाद वास्तव में उच्च न्यायालय के उस अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर सकता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां सदन द्वारा अवमानना के लिए पक्षकार को निरुद्ध करने का निर्देश देते हुए सामान्य या अव्यक्त वारंट जारी किया गया हो।

यद्यपि हमारे सामने उपरिष्ठ प्रश्नों द्वारा उत्पन्न समस्या का अंतिम समाधान बहुत ही सीमित दायरे में है, फिर भी समस्या के कुछ व्यापक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है जो संयोगवश सामने आते हैं और जिसका निर्णय हमें वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करेगा। इस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत सम्पूर्ण समस्या का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 194(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जाना है, और इस अर्थ में अनुच्छेद 194(3) की व्याख्या ही वास्तव में मामले का सार है। इस स्तर पर अनुच्छेद 194 को पढ़ना आवश्यक है:

194.(1) इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्य-स्वतंत्र्य होगा।

(2) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की और ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही होंगी जो संविधान के प्रारम्भ में यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके सदस्यों और समितियों की थी।

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 194 के पहले तीन महत्वपूर्ण खंड तीन अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं। खंड (1) यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की विधायिका में भाषण की स्वतंत्रता, जो इसके द्वारा निर्धारित है, संविधान के प्रावधानों और विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। इस खंड की व्याख्या करते समय, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि संविधान के वे उपबंध, जिनके अधीन रहते हुए विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, संविधान के सामान्य उपबंध नहीं हैं, बल्कि केवल वे उपबंध हैं जो विधायिका की प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित हैं। नियम और स्थायी आदेश विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित कर सकते हैं और संविधान के कुछ प्रावधान भी इसे विनियमित करने का दावा कर सकते हैं; उदाहरण के लिए, ये अनुच्छेद 208 और 211 हैं। विशेषण खंड "विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करना" "संविधान के प्रावधानों" और "नियमों और स्थायी आदेशों" से संबंधित दोनों पूर्ववर्ती खंडों को नियंत्रित करता है। इसलिए, खंड

- (1) विधायकों को विशेष रूप से अपने पहले भाग द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि इस खंड को केवल संविधान के निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन बनाकर, संविधान निर्माता यह स्पष्ट करना चाहते थे कि वे विधायकों को अलग से और एक अर्थ में अनुच्छेद 19(1)(ए) से स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक समझते हैं। यदि विधायकों को अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित

केवल वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा करने का अधिकार देना होता, तो अनुच्छेद 194(1) द्वारा अपनाए गए तरीके से विशेष रूप से वैसे ही अधिकार प्रदान करना अनावश्यक होता; और इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) संविधान के उन प्रावधानों में से एक नहीं है जो अनुच्छेद 194 के खंड (1) के पहले भाग को नियंत्रित करता है।

विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद, खंड (2) इस तथ्य पर जोर देता है कि उक्त स्वतंत्रता पूर्ण और अप्रतिबंधित है। विधायकों को विधायिका या उसकी किसी समिति में दिए जाने वाले वोटों के संबंध में भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई विधायक अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 211 का उल्लंघन करते हुए भी करता है, तो भी वह किसी भी न्यायालय में किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि किसी विधायक पर अपने भाषण या मत द्वारा विधान सभा में संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है, तो वह किसी भी अदालत में उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आक्षेपित भाषण मानहानि के बराबर है या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत कार्रवाई योग्य या अभियोग योग्य हो जाता है, तो इस खंड द्वारा उसे किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। वह ऐसे भाषण के लिए सदन के प्रति उत्तरदायी हो सकता है और अध्यक्ष उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है; लेकिन यह एक अलग मामला है। यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने विधान मंडलों के भीतर वाद-विवाद में पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता को इतना महत्व दिया कि उन्होंने विधायकों को विधान मंडलों में उनके भाषणों के संबंध में खंड (2) द्वारा निर्धारित व्यापक शर्तों के अंतर्गत किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करना आवश्यक समझा। इस प्रकार, खंड (1) विधायिका के भीतर विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और खंड (2) यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता वस्तुतः पूर्ण और अप्रतिबंधित है।

यह हमें खंड (3) पर ले जाता है। इस खंड का पहला भाग राज्यों के विधानमंडलों को उनकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है; दूसरा भाग यह प्रावधान करता है कि जब तक ऐसे कानून नहीं बनाए जाते, संबंधित विधानमंडलों को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो संविधान के प्रारंभ पर हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थी। संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि विधानमंडलों को अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में कानून बनाने में कुछ समय लगेगा। इस अंतराल के दौरान, उन्हें आवश्यक शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करना स्पष्ट रूप से आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि खंड (3) द्वारा जिन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की कल्पना की गई है, वे आकस्मिक शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो प्रत्येक विधान मंडल के पास होनी चाहिए ताकि वह प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम हो सके, और यही खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग का उद्देश्य स्पष्ट करता है।

इस खंड में यह अपेक्षित है कि सदन द्वारा दावा की गई शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संविधान के प्रारंभ के समय अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को विद्यमान दर्शायी जानी चाहिए। यह सर्वविदित है कि मान्यता के लिए अपने कटु संघर्ष के दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स ने जिन अनेक विशेषाधिकारों और शक्तियों का दावा किया था, उनमें से कुछ को समय के साथ छोड़ दिया गया और कुछ अप्रचलन के कारण लगभग समाप्त हो गए; इसलिए, प्रत्येक मामले में जहां किसी शक्ति का दावा किया जाता है, यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या वह प्रासंगिक समय पर विद्यमान शक्ति थी। यह भी प्रतीत होना चाहिए कि उक्त शक्ति का दावा न केवल हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया गया था, बल्कि अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा भी इसे मान्यता दी गई थी। यह तर्क देना स्पष्ट रूप से बेकार होगा कि यदि कोई विशेष शक्ति जिसका दावा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया जाता है, उसकी मांग हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा की गई थी, लेकिन अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा उसे मान्यता नहीं दी गई थी, तो भी इसे खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग के तहत केवल इस आधार पर बरकरार रखा जाएगा कि इसका दावा वास्तव में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया

गया था। दूसरे शब्दों में, इस खंड द्वारा निर्धारित जांच यह है: क्या प्रश्नगत शक्ति प्रासंगिक समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स में विद्यमान थी या साबित हुई है?

खंड (4) पूर्ववर्ती तीन खंडों द्वारा निर्धारित प्रावधानों को उनमें वर्णित कुछ व्यक्तियों पर लागू करता है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 194 के सभी चार खंड भाग III में निहित प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। वास्तव में, खंड (2) को इतने व्यापक शब्दों में प्रस्तुत किया गया है कि खंड (1) द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यदि विधायक अपने भाषणों द्वारा भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो वे किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। फिर भी, यदि अन्य वैध विचारों के लिए, यह प्रतीत होता है कि खंड (3) की सामग्री संविधान के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर नहीं कर सकती है, तो यह सुझाव देना उचित नहीं होगा कि उन प्रावधानों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उक्त खंड "संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन" शब्दों के साथ शुरू नहीं होता है। अनुच्छेद 194 के खंड (3) में निहित प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने में, जहां भी यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रावधानों और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के बीच संघर्ष है, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के नियम को अपनाकर उक्त संघर्ष को हल करने का प्रयास करना होगा। इस तरह के नियम को अपनाने का क्या नतीजा होगा, इस पर हमें अभी विचार करने की जरूरत नहीं है। हम बाद में पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करते समय इसका उल्लेख करेंगे।

हालाँकि, इस चरण में खंड (3) के पहले भाग के निहितार्थों की जाँच की जा सकती है। सवाल यह है कि अगर किसी राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो उसकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो क्या यह कानून अनुच्छेद 13 के अधीन होगा या नहीं? यह याद किया जा सकता है कि अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून शून्य होंगे। अनुच्छेद 13 का खंड (1) संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों के संबंध में संदर्भित है, और खंड (2) उन कानूनों को संदर्भित करता है जो राज्य भविष्य में बनाएंगे। प्रथम दृष्टया, यदि किसी राज्य का विधानमंडल खंड (3) द्वारा उसे प्रदत्त प्राधिकार के अनुसरण में कोई कानून बनाता है, तो वह अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून होगा और अनुच्छेद 13 का खंड (2) उसे शून्य कर देगा यदि वह भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनका न्यूनीकरण करता है। जैसा कि हम अभी बताएंगे, पंडित शर्मा मामले में इस न्यायालय के निर्णय का यही प्रभाव है। दूसरे शब्दों में, अब यह तय माना जाना चाहिए कि यदि खंड (3) के पहले भाग द्वारा प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग के तहत कोई कानून बनाया जाता है, तो उसे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करना होगा। यदि ऐसा है, तो यह जानना तुरन्त आवश्यक हो जाता है कि क्या संविधान निर्माताओं का वास्तव में यह आशय था कि मूल अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए ही किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करते हुए कानून बनाया जा सकता है, को उक्त खण्ड के उत्तरार्द्ध भाग की व्याख्या करते समय अप्रासंगिक माना जाना चाहिए। इसी बात को दूसरे रूप में भी आसानी से कहा जा सकता है। यदि ऐसा लगता है कि सदन द्वारा दावा की गई कोई भी शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, तो संघर्ष का समाधान कैसे होगा। क्या संविधान का उद्देश्य धारा (3) के उत्तरार्द्ध में निर्दिष्ट शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को उस कानून से कहीं अधिक ऊँचे स्थान पर रखना था, जिसे राज्य की विधायिका भविष्य में उस संबंध में बना सकता है? धारा (3) की व्याख्या के मामले में, यह तथ्य कि उक्त धारा का पहला भाग भविष्य के कानूनों को संदर्भित करता है जो मौलिक अधिकारों के अधीन होंगे, धारा (3) के उत्तरार्द्ध भाग की व्याख्या करने में महत्व प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 194 के पहले तीन महत्वपूर्ण प्रावधानों की स्थिति यही है।

अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, वह श्री सीरवाई द्वारा उठाए गए प्रारंभिक तर्क से उत्पन्न होता है कि सदन की ओर से हमारे समक्ष उनके उपस्थित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि सदन ने न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 194(3) की ऐसी व्याख्या करने

की अधिकारिता को मान लिया है जो इसे बाध्य करे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उनका रुख यह है कि विशेषाधिकारों के मामले में सदन सभी चरणों में एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश है। हो सकता है कि तकनीकी रूप से, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर इस न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी राय उचित रूप से न्यायिक निर्णय के बराबर न हो और चूंकि संदर्भ में न्यायालय के समक्ष कोई पक्ष नहीं है, इसलिए कोई भी हमारे उत्तरों से बाध्य नहीं होगा। लेकिन मामले के इस तकनीकी पहलू के अलावा, यह आवश्यक है कि हम इस मूल प्रश्न का निर्धारण करें कि क्या विशेषाधिकारों के मामले में भी संविधान सदन को एकमात्र और अनन्य अधिकारिता प्रदान करता है, जैसा कि श्री सीरवर्ड ने दावा किया है। यह सर्वमान्य है कि शक्तियां अनुच्छेद 194(3) में पाई जानी चाहिए। यह प्रावधान शक्तियों का एकमात्र आधार है, और इसमें शामिल न होने वाली किसी भी शक्ति का दावा सदन द्वारा नहीं किया जा सकता है; और इसलिए, अपनी चर्चा की शुरुआत में ही, हमें इस प्रश्न का निर्णय करना चाहिए।

इस प्रश्न पर विचार करते समय, संघीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इंग्लैंड में संसद संप्रभु है; और डाइसी के शब्दों में, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत की तीन विशिष्ट विशेषताएं हैं: संसद को कोई भी कानून बनाने या रद्द करने का अधिकार है; इंग्लैंड के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी व्यक्ति या निकाय को संसद के कानून को अपास्त करने या उसे रद्द करने का अधिकार नहीं है; और संसद का अधिकार या शक्ति महारानी के प्रभुत्व के हर हिस्से तक फैली हुई है। दूसरी ओर, संघवाद की अनिवार्य विशेषता है "समन्वयित और स्वतंत्र निकायों के बीच सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकार का वितरण।" संविधान की सर्वोच्चता संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक है, ताकि संघीय इकाई के विधायिका या सदस्य राज्यों के विधानमंडलों को शक्ति के उस नाजुक संतुलन को नष्ट करने या बिगाड़ने से रोका जा सके, जो उन राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है जो संघ के डब्लुक हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगतता को एकता में विलय करने के लिए तैयार नहीं हैं। संविधान की यह सर्वोच्चता एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के प्राधिकार द्वारा संरक्षित है जो शक्तियों के वितरण की योजना के व्याख्याता के रूप में कार्य करता है। संघीय या राज्य विधान की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संविधान में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता का दावा हमारे जैसे संघीय संविधान द्वारा नहीं किया जा सकता।

हमारी विधायिका के पास निरसंदेह पूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां लिखित संविधान की मूल अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनका प्रयोग सातवीं अनुसूची के अंतर्गत तीन सूचियों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आवंटित विधायी क्षेत्रों के भीतर किया जा सकता है; लेकिन विधानमंडल सूचियों से परे नहीं जा सकते। वे निरसंदेह अपने पूर्ण विधायी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं; लेकिन शक्ति का आधार संविधान ही है। इसके अलावा, संसद सहित हमारे विधानमंडलों की विधायी सर्वोच्चता आमतौर पर संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। यदि विधानमंडल अपने निर्धारित विधायी क्षेत्रों से आगे बढ़ते हैं, या अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, जो कि उक्त मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा उचित नहीं है, तो उनके विधायी कार्यों को भारत में न्यायालयों द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसलिए, यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारे विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं, लेकिन वे संविधान के सारवान और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं। लेकिन शक्ति का आधार संविधान ही है। इसके अलावा, संसद सहित हमारे विधानमंडलों की विधायी सर्वोच्चता सामान्यतः संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। यदि विधानमंडल उन्हें सौंपे गए विधायी क्षेत्रों से आगे बढ़ते हैं, या अपने संबंधित क्षेत्रों में इस प्रकार कार्य करते हैं, जिससे वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं जो उक्त मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा उचित नहीं है, तो उनकी विधायी कार्यवाई भारतीय न्यायालयों द्वारा रद्द की जा सकती है। इसलिए, यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारे विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं, तथापि वे संविधान के सारवान और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं।

लिखित संविधान द्वारा शासित लोकतांत्रिक देश में संविधान ही सर्वोच्च और

संप्रभु होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 में स्वयं इस संबंध में प्रावधान किया गया है और संविधान में संशोधन केवल उक्त अनुच्छेद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही वैध रूप से किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि जब संसद संविधान में संशोधन करना चाहती है, तो उसे संविधान के प्रासंगिक अधिदेश का पालन करना होता है। विधायक, मंत्री और न्यायाधीश सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, क्योंकि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों से ही उन्हें अपना अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है तथा संविधान के प्रावधानों के प्रति ही उनकी निष्ठा होती है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस संप्रभुता का दावा इंग्लैंड में संसद द्वारा किया जा सकता है, उसका दावा भारत में किसी भी विधानमंडल द्वारा इसके शाब्दिक निरूपण अर्थ में नहीं किया जा सकता।

इस मामले का एक और पहलू है जिसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए; भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट और कठोर पृथक्करण है या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान ने इस देश की न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। जब किसी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि उसे विधानमंडल द्वारा बिना प्राधिकार के पारित किया गया है, या अन्यथा असंवैधानिक रूप से मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, तो विवाद का निपटारा करना तथा यह तय करना न्यायालय का कार्य है कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून वैध है या नहीं। जिस प्रकार विधानमंडलों को विधायी प्राधिकार प्रदान किया गया है और उनके कार्य सामान्यतः विधायी कार्यों तक ही सीमित होते हैं, तथा कार्यपालिका के कार्य और प्राधिकार कार्यपालिका प्राधिकार के क्षेत्र तक सीमित होते हैं, उसी प्रकार इस देश में न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार और प्राधिकार न्यायनिर्णयन के क्षेत्र में होता है। यदि किसी कानून की वैधता को न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो यह सुझाव कभी नहीं दिया जाता है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय विधानमंडलों द्वारा स्वयं किया जा सकता है कि क्या विधायी प्राधिकार का अतिक्रमण किया गया है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं। इस तरह के विवाद का निर्णय पूरी तरह से और अनन्य रूप से इस देश की न्यायपालिका को सौंपा गया है; और इसलिए, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अनुच्छेद 194(3) की व्याख्या के बारे में निर्णय अंततः अनन्य रूप से इस देश की न्यायपालिका द्वारा ही होना चाहिए। इसलिए हमें श्री सीरवई के इस तर्क को खारिज करना चाहिए कि सदन की शक्तियों की प्रकृति, दायरा और प्रभाव को निर्धारित करने का प्रश्न विशेष रूप से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, यह निष्कर्ष श्री सीरवई के इस तर्क की वैधता को कम नहीं करेगा कि वर्तमान संदर्भ कार्यवाही में हमारे द्वारा दी गई सलाहकारी राय शब्द के वास्तविक अर्थ में निर्णय नहीं है और इस तरह से किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं करेगी।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अनुच्छेद 194(3) की विषय-वस्तु का निर्धारण अंततः न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि विधानमंडलों द्वारा, हम संविधान के तहत विधानमंडलों को सौंपे गए कार्य की भव्यता और प्रभाव से अनभिज्ञ नहीं हैं। व्यापक रूप से कहा जाए तो, आज हमारे देश के सभी विधान मंडल कल्याणकारी राज्य के आदर्श को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसे संविधान द्वारा हमारे देश के समक्ष रखा गया है, और यह स्वाभाविक रूप से विधान मंडलों को आज के इतिहास के निर्माण में उच्च स्थान प्रदान करता है। उच्च न्यायालयों को भी विधि के शासन के विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विधि के शासन का सफल संचालन लोकतांत्रिक जीवन पद्धति का मूल आधार है। इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि इन दो संबंधित संस्थाओं, विधानमंडलों और न्यायपालिका की स्थिति, गरिमा और महत्व मुख्य रूप से संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए संबंधित कारणों की स्थिति, गरिमा और महत्व से प्राप्त होते हैं। इन दो प्रतिष्ठित निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका, जो लोकतांत्रिक राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, को अपने क्षेत्र में न तो विरोध की भावना से और न ही शत्रुता की भावना से, बल्कि तर्कसंगत, सामंजस्य और समझदारी की भावना से कार्य करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य के तीन घटकों का ऐसा सामंजस्यपूर्ण संचालन ही इस देश में लोकतांत्रिक जीवन पद्धति के शांतिपूर्ण विकास, वृद्धि और स्थिरता में मदद करेगा।

लेकिन जब, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ, सदन और उच्च न्यायालय के बीच

कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो हमें समस्या से वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रूप से निपटना होगा। बहस या चर्चा में गरमाहट लाने का कोई अवसर नहीं है और न ही कठोर भाषा के प्रयोग का कोई औचित्य है। वर्तमान संदर्भ द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत समस्या संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करने की है और यद्यपि इस पर विचार करने में कुछ कठिन पहलू सामने आ सकते हैं, फिर भी हमें यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान जैसे विवाद से निपटने में, जो राज्य में दो प्रतिष्ठित निकायों के अधिकार क्षेत्र, गरिमा और स्वतंत्रता से संबंधित है, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण की निष्पक्षता संयोगवश कसौटी पर हो सकती है। इसलिए, न्यायिक प्रक्रिया की विशिष्ट विशेषता, पृथक वस्तुनिष्ठ जांच की भावना में हम अपने सलाहकारी राय के लिए तैयार किए गए प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रस्ताव करते हैं। यदि अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री सीतलवाड़ द्वारा उच्च न्यायालय की ओर से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण गलत है, तो हम उस दृष्टिकोण के विरुद्ध अपना निर्णय सुनाने में संकोच नहीं करेंगे। दूसरी ओर, यदि हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री सीरवाई द्वारा सदन की ओर से किए गए दावे को कायम नहीं रखा जा सकता है, तो हम तदनुसार अपना निर्णय सुनाने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण और विशिष्ट समस्या से निपटने में, यह आवश्यक है कि हम बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तथा इस पूर्ण चेतना के साथ आगे बढ़ें कि संविधान और कानूनों को बनाए रखना हमारा एकमात्र दायित्व है।

यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 194(3) में दो भाग हैं। पहला भाग विधानमंडल को समय-समय पर कानून द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है, जबकि दूसरा भाग यह प्रावधान करता है कि जब तक विधानमंडल अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का विकल्प नहीं चुनता, तब तक उसकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके सदस्यों और समितियों जैसी होंगी। श्री सीरवाई का तर्क है कि अनुच्छेद 194(3) का उत्तरार्द्ध स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि प्रासंगिक समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित सभी शक्तियाँ सदन में निहित हैं। हालाँकि, इस व्यापक दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका दावा स्पष्ट रूप से सदन द्वारा नहीं किया जा सकता है। पहुंच की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार को लें, जिसका प्रयोग हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा एक निकाय के रूप में तथा इसके अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है, "अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से अपने संप्रभु के समक्ष हर समय याचिका, परामर्श या विरोध करने का अधिकार रखने तथा उसके शब्दों पर अनुकूल व्याख्या करने के अधिकार को कॉमन्स द्वारा मौलिक विशेषाधिकार के रूप में उचित रूप से धारित किया जाता है।" यह इंगित करना शायद ही आवश्यक है कि सदन इस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसी तरह, अभियोग के अधिनियमों को पारित करने के विशेषाधिकार और महाभियोग के विशेषाधिकार का दावा सदन द्वारा नहीं किया जा सकता। हाउस ऑफ कॉमन्स भी अपने संविधान के संबंध में विशेषाधिकार का दावा करता है। यह विशेषाधिकार तीन तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पहला संसद के दौरान कॉमन्स में उत्पन्न होने वाली शक्तियों को भरने के लिए नए रिट आदेश द्वारा; दूसरा, विवादित चुनावों के परीक्षण द्वारा; और तीसरा, संदेह के मामलों में अपने सदस्यों की योग्यता निर्धारित करके। कथित रूप से, इस विशेषाधिकार का दावा भी सदन द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि प्रासंगिक समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स के पास जो भी शक्तियाँ और विशेषाधिकार थे, उनका दावा सदन द्वारा किया जा सकता है।

अनुच्छेद 194(3) के प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, हमें पंडित शर्मा के मामले में इस न्यायालय के पिछले निर्णय के प्रकाश में इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। इसलिए, यह याद रखना ज़रूरी है कि उस मामले में बहुमत के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 194(3) में निहित प्रावधान की स्थिति क्या है। उस मामले में, पटना के अंग्रेजी दैनिक अखबार सर्व लाइट के संपादक को पटना विधान सभा के सचिव ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष कारण बताने के लिए कहा था कि उनके खलिफा अध्यक्ष और विधानसभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि उन्होंने एक सदस्य द्वारा विधानसभा में दिए गए भाषण को पूरा

प्रकाशित किया था, जिसके कुछ हिस्सों को अध्यक्ष ने हटाने का निर्देश दिया था। संपादक, जिन्होंने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में याचिका दायर की थी, ने तर्क दिया कि उक्त नोटिस और समिति द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी का भी अतिक्रमण करती है। इन्हीं दो आधारों पर उन्होंने नोटिस की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाया। इस दावे का सदन ने अनुच्छेद 194(3) का सहारा लेकर विरोध किया। दो प्रश्न उठे, पहला यह कि क्या सदन द्वारा दावा किया गया विशेषाधिकार प्रासंगिक समय पर इंग्लैंड में विद्यमान विशेषाधिकार था; और दूसरा यह कि अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध में निहित प्रावधानों पर अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 के प्रभाव का क्या परिणाम हुआ? बहुमत का निर्णय यह था कि विचाराधीन विशेषाधिकार प्रासंगिक समय पर विद्यमान था और इसलिए इसे अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध में शामिल माना जाना चाहिए। यह भी धारित किया गया कि अनुच्छेद 19(1)(ए) लागू नहीं होता, क्योंकि सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के नियम के तहत, वर्तमान जैसे मामले में जहां अनुच्छेद 19(1)(ए) अनुच्छेद 194(3) के सीधे टकराव में था, बाद के अनुच्छेद का विशेष प्रावधान पहले वाले में निहित सामान्य प्रावधान पर अभिभावी होगा; इसने आगे यह अवधारित किया गया कि यद्यपि अनुच्छेद 21 लागू होता है लेकिन इसका उल्लंघन नहीं किया गया है।

दूसरी ओर, अल्पमत का दृष्टिकोण यह था कि विचाराधीन विशेषाधिकार वास्तव में स्थापित नहीं किया गया था, और वैकल्पिक रूप से, यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा विशेषाधिकार स्थापित किया गया था और इसलिए, अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो इसे अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा इस आधार पर नियंत्रित किया जाना चाहिए कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार सर्वोपरि महत्व के थे और उन्हें अनुच्छेद 194(3) में निहित प्रावधान जैसे किसी प्रावधान पर अभिभावी होना चाहिए जो उनके साथ असंगत हो सकता है।

इस स्तर पर, उस मामले में बहुमत और अल्पमत दोनों निर्णयों द्वारा तय किए गए बिंदुओं को व्यापक रूप से इंगित करना उपयोगी होगा। न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता द्वारा यह आग्रह किया गया कि यद्यपि अनुच्छेद 194(3) को संविधान के प्रावधानों के अधीन नहीं बनाया गया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यह ऐसा विषय नहीं है, और अनुच्छेद 194 के कई खंडों को अलग-अलग और पृथक् प्रावधानों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इस तरह से पढ़े जाने पर सभी खंडों को संविधान के प्रावधानों के अधीन माना जाना चाहिए, जिसमें निश्चित रूप से अनुच्छेद 19(1)(ए) शामिल होगा। इस तर्क को बहुमत और अल्पमत दोनों ने खारिज कर दिया।

उस मामले में अगला तर्क यह दिया गया कि अनुच्छेद 194(1) वास्तव में राज्य विधानमंडलों में प्रयोग किए जाने पर अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हनन के रूप में कार्य करता है, लेकिन अनुच्छेद 194(3) अनुच्छेद 19(1)(ए) के अपवाद के रूप में नहीं है। इस तर्क को भी बहुमत और अल्पमत दोनों ने खारिज कर दिया। बहुमत के निर्णय में यह बताया गया कि अनुच्छेद 194 का खंड (1) निस्संदेह उक्त खंड के मूल प्रावधान को संविधान के प्रावधानों के अधीन बनाता है; लेकिन संदर्भ में, वे प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(ए) में नहीं आ सकते, क्योंकि इस उत्तरार्द्ध अनुच्छेद का आशय विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करने का नहीं है और संविधान के ऐसे प्रावधान ही जो विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं, अनुच्छेद 194(1) के पहले भाग में शामिल हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया तीसरा तर्क यह था कि अनुच्छेद 19 एक पारलौकिक सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और इसे अनुच्छेद 194(3) के प्रावधानों पर अभिभावी होना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि ये बाद के प्रावधान क्षणिक प्रकृति के हैं। इस तर्क को बहुमत के दृष्टिकोण से खारिज कर दिया गया, लेकिन अल्पमत के दृष्टिकोण से इसे बरकरार रखा गया।

चौथा तर्क यह था कि यदि विधानमंडल द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करते हुए कोई कानून बनाया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन होगा और भाग III में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की सीमा तक शून्य हो जाएगा। इस तर्क को बहुमत और अल्पमत दोनों निर्णयों द्वारा स्वीकार किया गया।

इससे एक और बिंदु पर विचार किया जाना शेष रह गया और इसमें इस न्यायालय द्वारा गुनुपति केशवराम रेड्डी बनाम नफीसुल हसन और उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए पहले के निर्णय में की गई टिप्पणियों का संदर्भ था। बहुमत के निर्णय में इस पहले के निर्णय पर टिप्पणी की गई है और यह टिप्पणी की गई है कि उक्त निर्णय पूरी तरह से रियायत पर आधारित था और इसलिए इसे इस न्यायालय का एक सुविचारित निर्णय नहीं माना जा सकता। जैसा कि हम अभी बताएंगे, उक्त निर्णय अनुच्छेद 194(3) के उत्तराह्व के अंतर्गत आने वाले मामले में अनुच्छेद 22(2) की प्रयोज्यता से संबंधित था। हालाँकि, अल्पमत की राय ने उक्त निर्णय को एक सुविचारित निर्णय माना जो न्यायालय पर बाध्यकारी था।

हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि बहुमत के निर्णय में, यह धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 लागू होता है, लेकिन, मेरिट के आधार पर, यह निष्कर्ष निकला कि इसका कथित उल्लंघन साबित नहीं हुआ है। अल्पमत के दृष्टिकोण से यह विचार करना अनावश्यक था कि क्या अनुच्छेद 21 लागू होता है, क्योंकि उक्त दृष्टिकोण ने भाग III द्वारा गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि माना और इसलिए, उनमें से प्रत्येक अनुच्छेद 194(3) के प्रावधानों को नियंत्रित करेगा।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पंडित शर्मा के मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों ने भाग III द्वारा गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों की प्रासंगिकता और प्रयोज्यता के बारे में कोई सामान्य मुद्दा नहीं उठाया। केवल दो अनुच्छेदों के उल्लंघन का तर्क दिया गया और वे अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 थे। इसलिए, सराव से कहें तो, इस बड़े मुद्दे पर विचार करना अनावश्यक था कि क्या अनुच्छेद 194(3) का उत्तराह्व सामान्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन था, और वास्तव में, बहुमत के दृष्टिकोण पर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि उक्त दृष्टिकोण ने सभी मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता को बाहर रखा, इस स्पष्ट और सरल कारण से कि अनुच्छेद 21 को लागू माना गया और याचिकाकर्ता के मामले में इसके कथित उल्लंघन के बारे में तर्क के मेरिट की जांच की गई और उसे स्वारिज कर दिया गया। इसलिए, हमें नहीं लगता कि बहुमत के फैसले को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पढ़ना सही होगा कि जब भी अनुच्छेद 194(3) के उत्तराह्व के प्रावधानों और भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रावधान के बीच कोई संघर्ष होता है, तो उत्तराह्व वाला पर पूर्वाह्व पर अभिभावी होना चाहिए। इसलिए, बहुमत के फैसले को इस रूप में लिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 19(1)(ए) लागू नहीं होगा, और अनुच्छेद 21 लागू होगा।

इस निष्कर्ष पर पहुँच कर, बहुमत के निर्णय ने संयोगवश गुनुपति केशवराम रेड्डी के मामले में दिए गए निर्णय पर टिप्पणी की। इस तथ्य के अलावा कि उस मामले में अनुच्छेद 22 की प्रयोज्यता के बारे में कोई विवाद नहीं था, हमें सम्मान के साथ यह बताना चाहिए कि पहले के निर्णय पर बहुमत के फैसले द्वारा की गई टिप्पणी आंशिक रूप से सटीक नहीं है। उस मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त विधानसभा के विशेषाधिकार हनन के लिए पारित आदेश के तहत श्री मिस्त्री की हिरासत से पर विचार कर रही थी। श्री मिस्त्री को निरुद्ध किए जाने की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसने संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन किया है। इस दलील के समर्थन में लाए गए तथ्यों को अटॉर्नी जनरल ने सही माना और उन स्वीकृत तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि श्री मिस्त्री को निरुद्ध किया जाना स्पष्ट रूप से अवैध था। इस निर्णय का हवाला देते हुए, बहुमत के फैसले ने टिप्पणी की है कि यह "पूरी तरह से अधिवक्ता की रियायत पर आने बढ़ा और इसे इस विषय पर एक सुविचारित राय नहीं माना जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस टिप्पणी

का पहला भाग सटीक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने रियायत कानून के उस बिंदु पर नहीं दी थी जिस पर न्यायालय ने निर्णय लिया था, बल्कि तथ्य के बिंदु पर दी थी; और इसलिए, टिप्पणी के इस हिस्से को सख्ती से उचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि, यह सच है कि श्री मिस्त्री की ओर से उठाए गए तर्क के मेरिट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और उस सीमा तक, बहुमत के फैसले को यह कहना स्वीकार्य हो सकता था कि यह न्यायालय की सुविचारित राय नहीं थी। लेकिन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बहुमत के फैसले के लिए अनुच्छेद 22(2) की प्रयोज्यता से संबंधित बिंदु पर विचार करना शायद ही आवश्यक था, क्योंकि पंडित शर्मा मामले में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में वह बिंदु नहीं उठा था। इसलिए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुनुपति केशवराम रेड्डी मामले में इस न्यायालय के पिछले निर्णय की वैधता या शुद्धता के बारे में बहुमत के फैसले में की गई टिप्पणियों को प्रश्नगत बिंदु तय करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह प्रश्न कि क्या अनुच्छेद 22(2) ऐसे मामले पर लागू होगा, इस न्यायालय को तब विचार करना पड़ सकता है जब ऐसा करना आवश्यक हो।

पंडित शर्मा के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से संबंधित बात समाप्त करने से पहले एक अन्य बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक है। हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुमत के निर्णय ने उस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 194(3) के पहले भाग द्वारा अधिकृत अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करते हुए कोई कानून पारित किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 13 के अधीन होगा। श्री सीरवई ने इस निष्कर्ष की शुद्धता को चुनौती देने का प्रयास किया है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 194(3) के पहले भाग द्वारा विधानसभाओं को दी गई शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, और इसलिए, यदि उक्त शक्ति के प्रयोग में कोई कानून पारित किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर होगा। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह सच है कि इस तरह का कानून बनाने की शक्ति विधानसभाओं को अनुच्छेद 194(3) के पहले भाग द्वारा प्रदान की गई है; लेकिन जब राज्य विधानमंडल इस शक्ति का प्रयोग करने का दावा करते हैं, तो वे निस्संदेह अनुच्छेद 246 संपठित सूची II की प्रविष्टि 39 के तहत कार्य करते हैं। इस तरह के कानून के अधिनियमन को संविधान शक्ति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए, ऐसे कानून को अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर एक कानून के रूप में माना जाना चाहिए। पंडित शर्मा के मामले में बहुमत के फैसले में यही दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है, और हम उस दृष्टिकोण से सम्मानजनक सहमति रखते हैं।

श्री सीरवई ने अनंतकृष्णन बनाम मद्रास राज्य में न्यायमूर्ति वेंकटराम अय्यर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला देकर अपने तर्क को पुष्ट करने का प्रयास किया। उस मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि "[अनुच्छेद 13] केवल संविधान के लागू होने से पहले लागू कानूनों और राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों, यानी भविष्य में लागू होने वाले कानूनों पर लागू होता है। केवल उन दो प्रकार के कानूनों को ही भाग III के प्रावधानों के सापेक्ष शून्य घोषित किया गया है। यह संविधान पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियमित नहीं करता है कि संविधान के अन्य हिस्से भाग III के प्रावधानों के सापेक्ष शून्य होने चाहिए और अगर ऐसा होता है तो यह आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि वे सभी एक ही जैविक समष्टि के हिस्से हैं।" यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से अपवाद रहित है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल तब किया जा सकता था जब हमारे सामने यह तर्क दिया जाता कि अनुच्छेद 194(3) का पहला या दूसरा भाग ही अमान्य है क्योंकि यह भाग III में मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान करने वाले प्रासंगिक प्रावधानों से असंगत है। हालांकि, यह श्री सीतलवाड़ का तर्क नहीं है, न ही यह पंडित शर्मा के मामले में इस न्यायालय के समक्ष दिया गया तर्क था। तर्क यह था और है कि यदि अनुच्छेद 194(3) के पहले भाग द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो यह अनुच्छेद 13 के अर्थ में एक कानून है, और यह तर्क अनुच्छेद 13(2) के शब्दों पर ही आगे बढ़ता है। अनुच्छेद 13(2) में प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III

द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। जिस कानून पर हम विचार कर रहे हैं, उसका उद्देश्य संविधान में संशोधन करना नहीं है और इसलिए, जब इसे पारित किया जाएगा, तो यह संविधान का हिस्सा नहीं होगा; विधानमंडलों द्वारा उन्हें प्रदत्त विधायी शक्तियों के प्रयोग में पारित किए गए अन्य कानूनों की तरह, यह कानून भी अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर कानून होगा, और

इसलिए, यह तर्क देना अनुचित है कि पंडित शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि ऐसा कानून मौलिक अधिकारों के अधीन होगा और अनुच्छेद 13 (2) के उल्लंघन के अंतर्गत आएगा, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, स्थिति यह है कि वर्तमान विवाद से निपटने में हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि अनुच्छेद 194 (3) का उत्तरार्द्ध अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अधीन नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के अधीन है।

अगला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना चाहिए वह यह है कि क्या संविधान का उद्देश्य द्वैतवाद को कायम रखना था जिसने 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इंग्लैंड में सार्वजनिक जीवन को बुरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया था? संविधान निर्माता न्यायपालिका और संसद के सदनों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप उत्पन्न कई दुखद स्थितियों से अवगत थे और वे जानते थे कि इन स्थितियों ने इंग्लैंड के सार्वजनिक जीवन में गतिरोध पैदा कर दिया था। जब उन्होंने अनुच्छेद 194(3) को अधिनियमित किया, तो क्या उनका इरादा इस टकराव के बिंदु को छोड़ देने का था, या उन्होंने उस टकराव को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की एक योजना अपनाई है? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर निर्भर करेगा।

सर्वप्रथम हम अनुच्छेद 226 का सन्दर्भ लेते हैं। यह अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को उसके अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है जैसा कि वह उन क्षेत्रों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी एवं समुचित मामलों में किसी सरकार को निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है, जिसमें भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार या किसी अन्य उद्देश्य के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण या इनमें से किसी भी प्रकृति रिट जारी कर सकता है। इस विषय-वस्तु पर महत्व देना शायद ही आवश्यक हो कि उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करने में अनुच्छेद 226 द्वारा प्रयुक्त भाषा बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 12 में "राज्य" की परिभाषा का वर्णन ऐसे राज्य के विधानसभा को शामिल करते हुए की गई है, अतः प्रथम दृष्टया किसी भी उचित मामले में अनुच्छेद 226(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति विधानसभा के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती है। यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाता है, तो सदन द्वारा यह प्रारंभिक आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा कि उच्च न्यायालय के पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि निरोध सदन के आदेश द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 226(1) को स्वतः पढ़ने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसे तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति है। इस न्यायालय की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 32, मामले को और भी उच्चतर स्थान पर रखता है; मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अंतर्गत उचित कार्यवाही द्वारा इस न्यायालय में जाने का अधिकार स्वतः एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, और इसलिए, हमने अनुच्छेद 226(1) के संबंध में जो कहा है वह अनुच्छेद 32(1) के बारे में और भी अधिक सत्य है।

जबकि हम इस मामले के पहलू पर विचार करते हैं तो इस बात पर जोर देना प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय और सदन के बीच जो टकराव उत्पन्न हुआ है, वह वास्तव में उच्च न्यायालय और सदन के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि सदन और इस देश के नागरिक के बीच का टकराव है। केशव सिंह कुछ मौलिक अधिकारों का दावा करते हैं जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं और वह इस आधार पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का अवैध रूप से उल्लंघन किया गया है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 (1) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केशव सिंह द्वारा किए गए दावों की मेरिट की जांच करना चाहता है और एक अंतरिम आदेश जारी करता है। यह वह अंतरिम आदेश है जिसने वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण विवाद को जन्म दिया है। निःसंदेह, सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीशों को अपने आवरण को स्पष्ट करने के लिए सदन के बार के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी नागरिक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए हस्तक्षेप किया, जिसके कारण न्यायाधीश इस स्थिति में पहुँच गए। मूल रूप से और मौलिक रूप से, विवाद उत्तर प्रदेश के नागरिक और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मध्य है। यही कारण है कि अपनी चारदीवारी के बाहर किए गए अवमानना के मामलों का निस्तारण करने में सदन की शक्तियों का दायरे के बारे में प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के

प्रावधान महत्व रखते हैं। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पंडित शर्मा के मामले में इस न्यायालय ने धारित किया है कि अनुच्छेद 21 वहां लागू होता है जहां अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत विधायिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई नागरिक इस आधार पर उच्च न्यायालय जाता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो उच्च न्यायालय उसके दावे की जांच करने का हकदार होगा, और यह अपने आप में वर्तमान कार्यवाही में सदन द्वारा दावा की गई शक्तियों के दायरे पर कुछ सीमाएं लगाएगा।

दो अन्य अनुच्छेद हैं जिनका संदर्भ अवश्य दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 208(1) में प्रावधान है कि किसी राज्य के विधानसभा का एक सदन इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। यह प्रावधान पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि यदि सदन इसके द्वारा निर्धारित कोई नियम बनाता है, तो वे नियम भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अधीन होंगे। दूसरे शब्दों में, जहां सदन अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियम बनाता है, वे नियम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अधीन होने चाहिए।

इसी तरह, अनुच्छेद 212(1) एक प्रावधान करता है जो प्रासंगिक है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य विधानसभा की किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 212(2) विधानसभा के उन अधिकारियों और सदस्यों को उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होने से उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिन्हें संविधान द्वारा या उसके अधीन विधानसभा में प्रक्रिया या कार्य संचालन को विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 212(1) किसी नागरिक के लिए विधानसभा कक्षा के अंदर किसी कार्यवाही की वैधता पर उचित न्यायालय में प्रश्न उठाने को संभव बनाता है, यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही प्रक्रिया की अनियमितता से नहीं, बल्कि अवैधता से ग्रस्त है। यदि आक्षेपित प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, तो इसकी न्यायालय में जांच की जा सकती है, हालांकि यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत केवल इस बात से अधिक नहीं है कि प्रक्रिया अनियमित थी तो ऐसी जांच निषिद्ध होती है। यह फिर से एक और संकेत है जो अनुच्छेद 194(3) द्वारा सदन को प्रदान की गई शक्तियों के दायरे और सीमा को समझने में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है।

यह हमें अनुच्छेद 211 पर ले जाता है। यह अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य के विधानसभा में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आवरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी। यह प्रावधान इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के न्यायिक आवरण के संबंध में किसी राज्य के विधानसभा में किसी भी चर्चा के विरुद्ध पूर्ण संवैधानिक निषेध है। न्यायाधीशों की ओर से पेश हुए श्रीमान सीतलवाड़ ने अपने तर्क को मुख्य रूप से इस अनुच्छेद के प्रावधानों पर आधारित किया है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 211 में संवैधानिक निषेध को जिस स्पष्ट और पूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है, वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश का आवरण अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों या विशेषाधिकारों के प्रयोग में सदन द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का विषय कभी नहीं बन सकता है। यदि कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सदन की अवमानना करता है, तो उसके खिलाफ उठाया जा सकने वाला एकमात्र कदम अनुच्छेद 121 में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 121 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या आवरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना के लिए राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद ही चर्चा संभव है, जैसा कि आगे प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 121 और 211 को एक साथ पढ़ने पर

दो बिंदु स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। न्यायाधीश के न्यायिक आवरण पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर संसद में केवल राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ही चर्चा की जा सकती है जिसमें न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना की गई हो। संविधान निर्माताओं ने इस देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इतना महत्व दिया कि उन्होंने अनुच्छेद 121 द्वारा प्रदान किए गए तरीके को छोड़कर, इसे किसी भी विवाद से परे रखना आवश्यक समझा।

यदि किसी न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है, तो यह अकल्पनीय है कि उसी आचरण को अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदन द्वारा वैध रूप से कार्रवाई का विषय बनाया जाए। मूलतः यही मुख्य तर्क है जो श्री सीतलवाड़ ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।

दूसरी ओर, श्रीमान सीरवई ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 211 में निहित प्रावधानों के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 211 अध्याय III में निहित है जो राज्य विधानसभा से संबंधित है और "सामान्य प्रक्रिया" विषय के अंतर्गत आता है, और इसलिए, इसका एकमात्र उद्देश्य विधानसभा के कक्ष के अंदर प्रक्रिया का विनियमन करना है। उन्होंने अनुच्छेद 194(2) के प्रावधानों पर भी अवलम्ब लिया है जो विधानसभा के किसी सदस्य के खिलाफ विधानसभा में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए किसी भी कार्रवाई को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि विधानसभा का कोई सदस्य अनुच्छेद 211 द्वारा निर्धारित पूर्ण निषेध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जैसा श्रीमान सीरवई कहते हैं वह यह दर्शाता है कि अनुच्छेद 211 में निहित निषेध के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। इसके अलावा, निर्माण के विषय के रूप में, श्री सीरवई सुझाव देते हैं कि अनुच्छेद 211 में निहित निषेध का पालन करने में विफलता किसी भी संवैधानिक परिणाम को जन्म नहीं दे सकती है, और इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने उ.प्र. राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलम्ब लिया है। उस मामले में, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 320 में निहित प्रावधानों के प्रभाव पर विचार कर रहा था। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों को निर्धारित करता है, और खंड 3 (सी) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या जैसा भी मामला हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सिविल वर्ग में सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श किया जाएगा, जिसमें ऐसे मामलों से संबंधित ज्ञापन या याचिकाएं शामिल हैं। यह धारित किया गया कि इस खंड के प्रावधान अनिवार्य नहीं थे और किसी लोक सेवक को कोई अधिकार नहीं देते थे तथापि परामर्शकर्ता की अनुपस्थिति या परामर्श में कोई अनियमितता उसे कानून की अदालत में कोई वाद हेतुक प्रदान नहीं करता। श्रीमान सीरवई का तर्क है कि अनुच्छेद 211 में प्रयुक्त शब्दों की भी इसी प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए तथा जिस निषेधाज्ञा पर श्रीमान सीतलवाड़ निर्भर हैं, उसे मात्र निर्देशात्मक माना जाना चाहिए, न कि अनिवार्य माना चाहिए।

हम श्रीमान सीरवई के तर्कों से प्रभावित नहीं हैं। तथ्य यह है कि अनुच्छेद 211 "सामान्य रूप से प्रक्रिया" से संबंधित विषय के अंतर्गत आता है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि इसके द्वारा निर्धारित निषेध अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, इस निषेध के पूर्ण महत्व को समझने के प्रयास में, हमें अनुच्छेद 211 और 121 को एक साथ पढ़ना चाहिए। यह सच है कि अनुच्छेद 194(2) विधान सभा में किसी सदस्य द्वारा दिए गए भाषण या उसके द्वारा दिए गए वोट के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करता है। लेकिन यह प्रावधान अपने आप में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि संविधान विधान सभा के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्सुक था, और इसलिए, इसने यह कहकर भाषण और अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करने की सावधानी बरती कि अनुच्छेद 211 द्वारा निर्धारित संवैधानिक निषेध का उल्लंघन भी किसी कार्रवाई को जन्म नहीं देना चाहिए। निःसंदेह, अध्यक्ष किसी सदस्य को अनुच्छेद 211 का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे; लेकिन अगर अनजाने में या किसी और तरह से विधानसभा के भीतर कोई भाषण दिया जाता है जो अनुच्छेद 211 का उल्लंघन करता है, तो संविधान निर्माताओं ने ऐसे भाषण को किसी भी अदालत में कार्रवाई से संरक्षण दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन स्वयं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और करेगा।

यह भी सच है कि अगर यह सवाल उठता है कि कोई भाषण अनुच्छेद 211 का उल्लंघन करता है या नहीं, तो इस मुद्दे पर अपना निर्णय देना अध्यक्ष का काम होगा। ऐसे प्रश्न पर विचार करते समय, अध्यक्ष को यह विचार करना पड़ सकता है कि कोई सदस्य जो टिप्पणियां करना चाहता है, क्या वे न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में

आवरण से संबंधित है, और इस लिहाज से, यह अध्यक्ष को तय करना है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य अभी भी बना हुआ है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 194(2) द्वारा एक विशिष्ट प्रावधान करना आवश्यक समझा और यही वह सीमा है जिस तक संविधान विधानसभा की चारदीवारी के भीतर भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के अपने उद्देश्य में रखा गया है।

अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग में ऐसा कोई अपवाद नहीं है, और इसलिए, यह मानना तर्कसंगत होगा कि जहां अनुच्छेद 211 के उल्लंघन में दिया गया भाषण अनुच्छेद 194(2) द्वारा न्यायालय में कार्यवाई से संरक्षित है, वहीं अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध के अंतर्गत सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करने में ऐसा कोई अपवाद या संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। यदि कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई आदेश पारित करता है या ऐसी टिप्पणियां करता है, जो सदन की राय में अवमानना के बराबर है, और सदन उस संबंध में न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाई करने के लिए आगे बढ़ता है, तो सदन की ओर से ऐसी कार्यवाई अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा किए गए किसी विशिष्ट प्रावधान द्वारा संरक्षित या उचित नहीं ठहराई जा सकती है। हमारी राय में, अनुच्छेद 194(2) द्वारा किए गए वास्तविक प्रावधान के साथ तुलना करने पर ऐसा कोई प्रावधान करने में त्रुटि महत्वहीन नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस विरोधाभास से यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान निर्माताओं ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि विधान मंडल के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जो अधिक से अधिक किया जा सकता है, वह अनुच्छेद 194(2) में प्रावधान करना होगा; और यह सभी के लिए है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में एक न्यायाधीश का आवरण सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग में कार्यवाई का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए, स्थिति यह है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में एक न्यायाधीश के आवरण पर सदन के अंदर वैध रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है, हालांकि अगर ऐसा है, तो कानून की अदालत में कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस तरह के आवरण को अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही का विषय नहीं बनाया जा सकता है। यदि यह सही स्थिति नहीं होती, तो अनुच्छेद 211 एक अर्थहीन घोषणा के बराबर होता और यह स्पष्ट रूप से संविधान का इरादा नहीं हो सकता था।

तब अनुच्छेद 211 की व्याख्या के संबंध में, निरसंदेह श्रीमान सीरवई उ.प्र. राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लेने की स्थिति में है। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अनुच्छेद 320(3)(सी) में निहित प्रावधान अनिवार्य नहीं था, इस न्यायालय ने कुछ अन्य तथ्यों का उल्लेख किया है जो उक्त व्याख्या को निर्धारित करते हैं। फिर भी, इस न्यायालय ने मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉर्मंडिन के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांत को स्वीकार किया है जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि "यह प्रश्न इस देश में बहुत बार उठता है कि क्या किसी कानून में प्रावधान निर्देशात्मक है या अनिवार्य, लेकिन यह कहा गया है कि कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और हर मामले में कानून के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए।" यह सवाल कि कोई कानून अनिवार्य है या निर्देशात्मक, विधानसभा की मंशा पर निर्भर करता है, न कि उस भाषा पर जिसमें मंशा को व्यक्त किया गया है। विधानसभा का अर्थ और इरादा निर्धारक होना चाहिए, और इन्हें न केवल प्रावधान की शब्दावली से, बल्कि इसकी प्रकृति, इसकी बनावट और इसके एक या दूसरे तरीके से व्याख्या करने से होने वाले परिणामों पर विचार करके भी पता लगाया जाना चाहिए।" ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से उस व्याख्या को नकारते हैं जिसके लिए श्रीमान सीरवई तर्क देते हैं। संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लेख करना शायद ही आवश्यक है, जिनका उद्देश्य इस देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। एक निर्भीक और स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व भारत में संवैधानिक ढांचे का मूल आधार कहा जा सकता है, और इसलिए, हमारा विचार है कि यह तर्क देना निरर्थक होगा कि अनुच्छेद 211 द्वारा निर्धारित पूर्ण निषेध को केवल निर्देश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और सदन को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश के आवरण के संबंध में उसके खिलाफ कार्यवाई करने की अनुमति देकर इसे एक अर्थहीन घोषणा तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि श्रीमान सीतलवाड़ सही हैं जब वे तर्क देते हैं कि अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा सदन को प्रदान की गई शक्तियों और विशेषाधिकारों की सीमा चाहे जो भी हो, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए कथित अवमानना के

लिए एक न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति उनमें शामिल नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, श्रीमान सीतलवाड़ का पक्ष यह है कि जहां तक न्यायाधीशों का संबंध है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद 226 और 211 में निहित प्रावधानों के प्रभाव के परिणामस्वरूप, न्यायिक आचरण कभी भी अनुच्छेद 194(3) के उत्तराह्व के अंतर्गत अवमानना कार्यवाही का विषय नहीं बन सकता है, भले ही यह धारित किया जाए कि ऐसा आचरण इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास मौजूद शक्तियों और विशेषाधिकारों के अंतर्गत अवमानना कार्यवाही का विषय बन सकता है।

दूसरी ओर, श्री सीरवर्ड ने अनुच्छेद 194(3) के उत्तराह्व पर 226 और 211 के प्रभाव के संबंध में श्री सीतलवाड़ के तर्क पर विवाद किया है और कहा है कि यदि श्रीमान सीतलवाड़ इस तर्क के संबंध में सही भी हों, तो भी वे हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा की गई शक्ति और विशेषाधिकार की वैधता पर विवाद करने के हकदार नहीं होंगे, जिसका दावा वर्तमान कार्यवाही में सदन द्वारा किया जा सकता है कि कोई भी न्यायालय सामान्य या अत्यंत वारंट की जाँच नहीं कर सकता। इन प्रतिद्वंद्वी तर्कों की वैधता निर्धारित करने के लिए, अब बहुत संक्षेप में इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि संविधान के प्रारंभ में इस विशेष शक्ति और विशेषाधिकार की स्थिति क्या थी। इस प्रश्न पर विचार करते हुए, हम इंग्लैंड में संसद के दोनों सदनों में निहित शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के व्यापक पहलू का भी व्यापक रूप से उल्लेख करेंगे।

अंग्रेजी संसद की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रश्न पर विचार करते समय, हमें लगता है कि श्रीमान मे की लिखित पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में दिए गए प्रासंगिक कथनों पर खुद को आधारित करना काफी सुरक्षित होगा। इस कार्य ने इस विषय पर एक क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है और इसे आमतौर पर संसदीय प्रथाओं का एक आधिकारिक विवरण माना जाता है; और इसलिए, हमें लगता है कि श्रीमान मे के संदर्भ के बिना इस प्रश्न पर विचार करने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। श्रीमान मे के अनुसार, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के उच्च न्यायालय के एक घटक भाग के रूप में प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट अधिकारों का योग है, जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अधिकारों से अधिक हैं। इस प्रकार, विशेषाधिकार, हालांकि देश के कानून का हिस्सा है, उन्हें एक निश्चित सीमा तक सामान्य कानून से स्वतंत्रता प्राप्त है। हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेष विशेषाधिकारों को "क्राउन के विशेषाधिकारों के विरुद्ध सदन और उसके व्यक्तिगत सदस्यों के मौलिक अधिकारों का योग; कानून की सामान्य अदालतों का अधिकार और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेष अधिकारों" के रूप में परिभाषित किया गया है। विशेषाधिकार और कार्य के बीच एक अंतर होता है, हालांकि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। हालांकि, कुल मिलाकर "विशेषाधिकार" शब्द को प्रत्येक सदन के कुछ मौलिक अधिकारों के लिए आरक्षित रखना अधिक सुविधाजनक है, जिन्हें आम तौर पर इसके संवैधानिक कार्यों के अभ्यास के लिए आवश्यक माना जाता है। विशेषाधिकार का विशिष्ट चिह्न इसका सहायक चरित्र है। संसद के विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो "इसकी शक्तियों के उचित निष्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं"। इनका उपयोग व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा किया जाता है, क्योंकि सदन अपने सदस्यों की सेवाओं के निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्य नहीं कर सकता है; और प्रत्येक सदन द्वारा अपने सदस्यों की सुरक्षा और अपने स्वयं के अधिकार और गरिमा की पुष्टि के लिए है।

श्रीमान मे ने कहा है कि एक मामले को छोड़कर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बचे हुए विशेषाधिकार उसी आवश्यकता के आधार पर उचित हैं, जिस तरह से स्व-शासित डोमिनियन और कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों की विधान सभाओं द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार, उनके विधायी अधिकार की विधिक घटना के रूप में सामान्य कानून के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकार हैं। यह अपवाद अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। कीली बनाम कार्सन के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बाद से यह माना जाता रहा है कि यह शक्ति हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित है, विधायी कार्यों वाले निकाय के रूप में नहीं, बल्कि संसद के उच्च न्यायालय के वंशज के रूप में और लेक्स एट कॉन्सुएटूडो पार्लियामेंटी के आधार पर है। ऐतिहासिक रूप से मूल रूप से कमजोर

निकाय के रूप में, कॉमन्स को अपने विशेषाधिकारों के दावे के लिए न केवल क्राउन और न्यायालयों के विरुद्ध, बल्कि लॉर्ड्स के विरुद्ध भी अधिक उग्र और अधिक लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार विशेषाधिकार की अवधारणा जो राजा के विरुद्ध विशेष संरक्षण में उत्पन्न हुई, कॉमन्स द्वारा प्रथागत अधिकारों के रूप में दावा किया जाने लगा, और इनमें से कुछ दावे उन्हें लागू करने के बार-बार प्रयासों के दौरान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त "विशेषाधिकारों" में बदल गए।

अपने विशेषाधिकारों को उग्र तरीके से लागू करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किए गए अत्यधिक संघर्ष के संबंध में श्रीमान मे ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि विशेषाधिकार के ये दावे पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए थे और सत्रहवीं शताब्दी में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा राजा के विरुद्ध और अठारहवीं शताब्दी में मनमाने ढंग से व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए थे। उन्नीसवीं शताब्दी तक संतुलन नहीं बना था और संसद, क्राउन और न्यायालयों द्वारा विशेषाधिकार की सीमाएँ निर्धारित और स्वीकार की गई थी। इस प्रकार दोनों सदनों को विशेषाधिकारों के एक सामान्य निकाय के प्रशासन में समान अधिकार प्राप्त हैं। संसद के एक घटक भाग के रूप में प्रत्येक सदन ने स्वतंत्र रूप से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया। हालाँकि, उनका प्रयोग प्रत्येक के लिए किसी भिन्न अधिकार द्वारा नहीं प्रदान किया गया बल्कि केवल संसद के विधि और प्रथा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः सभी विशेषाधिकार उचित या तथाकथित रूप से, दोनों सदनों पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्हें प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित और वर्णित किया जाता है; और विशेषाधिकार के उल्लंघन का निर्णय प्रत्येक द्वारा किया जाता है और उसकी निंदा की जाती है; लेकिन अनिवार्य रूप से, यह अभी भी संसदीय विधि है जिसे इस प्रकार प्रशासित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि यद्यपि कोई भी सदन संसद के कानून की व्याख्या कर सकता है, तथा अपने स्वयं के विशेषाधिकारों की पुष्टि कर सकता है, लेकिन यह सहमति है कि कोई नया विशेषाधिकार नहीं बनाया जा सकता है। यह स्थिति 1704 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित ऐतिहासिक संकल्प के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। इस संकल्प में घोषित किया गया कि "संसद के किसी भी सदन को किसी भी मत या घोषणा द्वारा अपने लिए नए विशेषाधिकार बनाने की शक्ति नहीं है, जो संसद के ज्ञात कानूनों और प्रथाओं द्वारा पुष्ट न हो।" इस संकल्प को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स को संप्रेषित किया गया तथा उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपने संकल्पों द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स अपने विशेषाधिकारों और शक्तियों की सूची में कुछ नहीं जोड़ सकता है।

इस स्तर पर मुख्य विशेषाधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिनका दावा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक स्वतंत्र परिषद या विधायिका के लिए आवश्यक विशेषाधिकार है, तथा इसका दावा दोनों सदनों द्वारा एक बुनियादी विशेषाधिकार के रूप में किया जाता है। यह विशेषाधिकार वर्ष 1541 से संसद के प्रारंभ में राजा को कॉमन्स की याचिका में स्थापित प्रथा द्वारा शामिल किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि इस विशेषाधिकार को बार-बार मान्यता दिए जाने के बावजूद, क्राउन और कॉमन्स हमेशा इसकी सीमाओं पर सहमत नहीं थे। इस विशेषाधिकार को 1688 की क्रांति के बाद अंतिम वैधानिक मान्यता मिली। अधिकार विधेयक के 9वें अनुच्छेद में यह घोषित किया गया कि "भाषण की स्वतंत्रता, संसद में बहस या कार्यवाही पर संसद से बाहर किसी भी न्यायालय या स्थान में आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए या उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।"

अन्य विशेषाधिकारों में अनजान व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार, बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को नियंत्रित करने का अधिकार, संसद में कार्यवाही का विशेष संज्ञान लेने का अधिकार, प्रत्येक सदन का अपनी कार्यवाही की वैधानिकता का एकमात्र न्यायाधीश होने का अधिकार, तथा संसद में अपने आवरण के लिए अपने सदस्यों को दंडित करने का निहित अधिकार शामिल है।

इन विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, संसद के दोनों सदनों के व्यक्तियों को गिरफ्तारी या छेड़छाड़ से स्वतंत्रता, तथा अभियोग से मुक्त होने का विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसका दावा कॉमन्स ने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर किया था। यद्यपि इस विशेषाधिकार को बहुत पहले ही शाही और वैधानिक मान्यता दे दी गई थी, लेकिन विडंबना यह है कि विशेषाधिकार का प्रवर्तन

लॉर्ड्स और राजा पर निर्भर था, जो हमेशा कॉमन्स की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। इस संबंध में, श्रीमान मे ने थोर्प के मामले का उल्लेख किया है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष थे और ड्यूक ऑफ यॉर्क के मुकदमे में कोर्ट ऑफ एक्सचेकर से निष्पादन के अंतर्गत 1452 में कैद कर लिए गए थे। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रभुत्व और हाउस ऑफ कॉमन्स की कमजोरी का एक स्पष्ट प्रमाण है जो अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि जब कॉमन्स के आवेदन के उत्तर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला सुनाया कि थोर्प को जेल में रहना चाहिए, तो कॉमन्स ने इस निर्णय को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया कि उन्होंने तुरंत दूसरे अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी।

श्रीमान मे ने बताया कि समय के साथ कुछ विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं। उनमें से एक का उल्लेख किया जा सकता है - अभियोजन से स्वतंत्रता। इसी तरह, संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770 द्वारा गिरफ्तारी से स्वतंत्रता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा प्रभावित हुई। जूरी सेवा से छूट के विशेषाधिकार के संबंध में कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। वास्तव में, प्रारम्भिक दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकारों की एक लंबी और कठिन सूची थी और यह दर्शाता है कि उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स अपने और अपने सदस्यों के लिए सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए इच्छुक था। हालांकि, समय के साथ, इनमें से कई विशेषाधिकार अप्रचलित हो गए और अस्तित्व में नहीं रहे, कुछ को कानून द्वारा नियंत्रित किया गया जबकि प्रमुख विशेषाधिकार, जिन्हें सदन के कुशल कामकाज के लिए आवश्यक विशेषाधिकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो अभी भी लागू रहे।

इन विशेषाधिकारों की प्रकृति पर सामान्य रूप से विचार करते समय, तथा विशेष रूप से सदन द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करने के लिए दावा किए गए विशेषाधिकार की प्रकृति पर विचार करते समय, विशेषाधिकारों के इस सिद्धांत की ऐतिहासिक उत्पत्ति को याद रखना आवश्यक है। इस संबंध में, श्रीमान मे ने इस बात पर बल दिया है कि आधुनिक संसद की उत्पत्ति उसके न्यायिक कार्यों में निहित है। श्रीमान मे कहते हैं, "हाल के शोध की एक प्रमुख पंक्ति ने संसद की उत्पत्ति में न्यायिक तत्वों के महत्व को उजागर किया है।" मैटलैंड ने 1305 के संसद रोल के अपने परिचय में, इस तथ्य के महत्व पर जोर देने वाले पहले व्यक्ति थे कि उस समय संसद राजा की "महान अदालत" थी और इस प्रकार (अन्य बातों के अतिरिक्त) शाही न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च अदालत थी। अब प्रारम्भिक संसदों के चरित्र में दृढ़ न्यायिक प्रवृत्ति को पहचानने में आम सहमति है और यह तथ्य कि एडवर्ड तृतीय के अधीन भी, यद्यपि संसदों ने अपने समय का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक और आर्थिक व्यवसाय के लिए समर्पित किया, न्याय देना राजा के विषयों की दृष्टि में उनके प्रमुख कार्यों में से एक रहा। जैसा कि सर्वविदित है, यूनाइटेड किंगडम की संसद में सॉवरेन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं। ये कई शक्तियां सामूहिक रूप से विधानसभा का निर्माण करती हैं; और, संविधान के अलग-अलग सदस्यों के रूप में, वे प्रत्येक के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं और विशेषाधिकारों का उपभोग करते हैं।

हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आध्यात्मिक और लौकिक, एक साथ बैठते हैं, और संयुक्त रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन करते हैं। विधानसभा में कॉमन्स के एक अलग स्थान पर प्रवेश की तिथि हमेशा विवाद का विषय रही है; लेकिन जैसा कि यह स्वीकार किया जाता है कि वे अक्सर विचार-विमर्श के लिए अलग-अलग बैठते थे, विशेष उदाहरण जिनमें वे अलग-अलग स्थानों पर मिलते थे, यह निर्धारित नहीं करेंगे कि उनका अलगाव, उस समय, अस्थायी था या स्थायी है। जब कॉमन्स अलग-अलग विचार-विमर्श करते थे, तो वे वेस्टमिंस्टर ऑफ एबोट के कक्ष या चौप्टर हाउस में बैठते थे; और अपने अंतिम अलगाव के बाद भी वे उसी स्थान पर अपनी बैठकें जारी रखते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमेशा से ही एक न्याय-कक्ष था और आज भी है। श्रीमान मे के अनुसार, लॉर्ड्स की सबसे विशिष्ट विशेषता उनका न्याय-कक्ष है, जिसका वे कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। उन्हें सत्रावसान और विघटन के दौरान न्यायालय के रूप में बैठने की शक्ति है; हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अपील न्यायालय का गठन किया जाता है और अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार उनके पास होता है। श्रीमान मे ने अभियोग और महाभियोग के कृत्यों के संबंध में संसद

द्वारा दावा की गई शक्ति का भी उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इस विशेषाधिकार का प्रयोग कैसे किया गया। "महाभियोग में" श्रीमान ने कहते हैं, "कॉमन्स केवल अभियोक्ता और अधिवक्ता होते हैं; जबकि लॉर्ड्स अकेले अपराध के न्यायाधीश होते हैं। दूसरी ओर, अभियोग के विधेयक पारित करने में, कॉमन्स किसी भी आरोप द्वारा स्वयं को प्रतिबद्ध नहीं करते हैं, न ही उनकी शक्तियां अपराधी के खिलाफ निर्देशित होती हैं: लेकिन वे लॉर्ड्स के समान क्षेत्राधिकार और समान जिम्मेदारी वाले न्यायाधीश होते हैं; और अभियुक्त को केवल क्राउन, लॉर्ड्स और कॉमन्स के संयुक्त निर्णय द्वारा ही दोषी ठहराया जा सकता है।" विशेषाधिकार का यह पहलू इंग्लैंड में संवैधानिक कानून के ऐतिहासिक विकास की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ-साथ हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किए गए क्षेत्राधिकार का एक हिस्सा आधुनिक संसद के ऐतिहासिक मूल में स्पष्ट रूप से खोजा जा सकता है, जो कि संसद के न्यायिक कार्यों में शामिल है, जैसा कि हमने अभी संकेत किया है।

लॉर्ड्स और कॉमन्स द्वारा दिए गए दंडों में अंतर भी इस संदर्भ में कुछ महत्व रखता है। श्रीमान ने कहते हैं, "जबकि दोनों सदन एक ही अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन मानने पर सहमत हैं," "कई महत्वपूर्ण विवरणों में उनके दंड के तरीकों में अंतर होता है। लॉर्ड्स ने अभिलेखीय न्यायालय होने का दावा किया है और इस तरह, न केवल कारावास बल्कि जुर्माना भी लगाया है। वे एक निश्चित समय के लिए कारावास का दण्ड भी देते हैं, और अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा देने का आदेश देते हैं; और दण्ड का उनका पारंपरिक तरीका कुर्की है। दूसरी ओर, कॉमन्स किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए दण्डित नहीं करते हैं, और पिछली दो शताब्दियों के दौरान जुर्माना नहीं लगाया है। इस बात पर कोई सवाल नहीं उत्पन्न हो सकता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपनी न्यायिक क्षमता में अभिलेखीय न्यायालय है; लेकिन, लॉर्ड केन्यन के अनुसार, 'जब विधायी क्षमता का प्रयोग किया जाता है, तो यह अभिलेखीय अदालत नहीं होती है'। हाउस ऑफ कॉमन्स, कानून में, अभिलेखीय अदालत है या नहीं, यह निर्धारित करना मुश्किल होगा; क्योंकि दावा, एक बार दृढ़ता से बनाए जाने के बाद, बाद में लगभग त्याग दिया गया है, हालांकि कभी भी स्पष्ट रूप से त्याग नहीं किया गया है"। श्रीमान ने द्वारा की गई यह अंतिम टिप्पणी निर्णायक महत्व की होगी जब हमें बाद में इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिलेगा कि क्या श्रीमान सीरवर्ड द्वारा दावा किया गया विशेषाधिकार कि सामान्य वारंट की अदालतों द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, अपने आप में विशेषाधिकार का एक हिस्सा है, या अदालतों और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच स्थापित सम्मेलन का परिणाम है।

अब हम संक्षेप में श्रीमान ने के शब्दों में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास मौजूद दण्डित करने की शक्ति की सामान्य विशेषताओं को इंगित करें। श्रीमान ने कहते हैं, "दण्डित करने की शक्ति को वास्तव में संसदीय विशेषाधिकार की आधारशिला के रूप में वर्णित किया गया है।" जैसा कि 1593 में कॉमन्स में कहा गया था, "इस न्यायालय को अपनी गरिमा और उच्चता के कारण विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसा कि अन्य सभी न्यायालयों को है। और, जैसा कि यह अन्य सभी न्यायालयों से ऊपर है, इसलिए इसे अन्य सभी न्यायालयों से ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त है; और जैसा कि इसके पास विशेषाधिकार और क्षेत्राधिकार है, इसलिए इसमें दबाव और बाध्यता भी है; अन्यथा यदि इसमें दबाव नहीं है तो न्यायालय में क्षेत्राधिकार कुछ भी नहीं है"। श्रीमान ने द्वारा दण्डित करने की इस शक्ति पर की गई टिप्पणी बहुत शिक्षाप्रद है। इस शक्ति की उत्पत्ति जो अपनी प्रकृति में न्यायिक है, स्वाभाविक रूप से संसद की मध्ययुगीन अवधारणा में मुख्य रूप से न्याय के न्यायालय-"संसद के उच्च न्यायालय" के रूप में पाई जाती है। न्यायिक रूप से कार्य करने वाले न्यायालय के रूप में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास निरसंदेह कम से कम वेस्टमिंस्टर हॉल के किसी भी न्यायालय के बराबर ही दण्डित करने की शक्ति थी।

लेकिन न्यायिक स्मृति के समय में "संसद में नव निर्मित" कॉमन्स, प्राचीन काल के आधार पर शक्ति का दावा नहीं कर सकते थे। 1399 के अंत तक उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था कि वे संसद के निर्णयों में भागीदार नहीं थे, बल्कि केवल याचिकाकर्ता थे। कॉमन्स द्वारा अधिकार के कब्जे को इस आधार पर चुनौती दी गई थी, और उन तर्कों द्वारा बचाव किया गया था जो विधायी और न्यायिक क्षेत्राधिकार को भ्रमित करते थे। यह संभवतः मध्ययुगीन अक्षमता के कारण

था कि संवैधानिक प्राधिकरण को किसी अर्थ में न्याय की अदालत के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में कल्पना करने में असमर्थता के कारण कॉमन्स लॉर्ड्स के समान शर्तों पर अपराधियों को दंडित करने के अपने अधिकार का दावा करने में सफल रहे। दण्डित करने के मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार की उत्पत्ति यही है।

जैसा कि इंग्लैंड का इतिहास दर्शाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स को राजा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कई मामलों में स्वयं लोगों से इस अधिकार के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक तीव्र संघर्ष में शामिल होना पड़ा। इस शक्ति को लॉर्ड्स ने 1704 में एशबी बनाम व्हाइट के मामले में दोनों सदनों के बीच सम्मेलन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था और इसे बार-बार विधिक न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है। वास्तव में यह शक्ति संविधि ८, सी. 13, एस. 3 द्वारा भी वस्तुतः स्वीकार की गई है, जो यह प्रावधान करती है कि इसमें कुछ भी "संसद में निंदा द्वारा किसी भी व्यक्ति पर लगाए जाने वाले किसी भी दंड को कम करने तक विस्तारित नहीं होगा।"

अब हम विशेषाधिकार के मामलों में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में विवादास्पद प्रश्न पर श्रीमान मे की पुस्तक में कानून के कथन का संदर्भ लेंगे। मे कहते हैं, संवैधानिक कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने वाले विषय पर पर्याप्त रूप से विचार करने के लिए एक अलग ग्रंथ की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार, संसदीय विशेषाधिकार को प्रभावित करने वाले मामलों में न्यायालयों की क्षमता और किसी भी सदन के अनन्य क्षेत्राधिकार के बीच सीमा का पता लगाना संवैधानिक कानून का एक कठिन प्रश्न है, जिसने विशेष रूप से सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक कई पेचीदा मामले प्रस्तुत किए हैं। सदनों और न्यायालयों के बीच यह आम बात रही है कि विशेषाधिकार "संसद के ज्ञात कानूनों और प्रथाओं" पर निर्भर करता है, न कि किसी भी सदन के स्व-निर्देशन पर निर्भर है। विवादित प्रश्न यह था कि क्या संसद का कानून एक "विशेष" कानून था या अपने व्यापक और विस्तारित अर्थ में सामान्य कानून का हिस्सा था, और पूर्व मामले में क्या यह एक श्रेष्ठ कानून था जो सामान्य कानून को दरकिनारा कर देता था। इस प्रश्न से न्यायालयों और संसद के बीच विवाद का एक और मुद्दा उठा और वह यह था कि क्या विशेषाधिकार के मामले पर केवल उस सदन द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, जिससे वह संबंधित है, भले ही इसमें तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल हों, या क्या कुछ मामलों में इसका निर्णय न्यायालयों में किया जा सकता है, और यदि ऐसा है, तो किस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में किया जा सकता है। संसद और न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण असंगत प्रतीत हुए। न्यायालयों ने दावा किया कि जब उनके समक्ष लाई गई कार्यवाही में इन विशेषाधिकारों के अस्तित्व या सीमा से संबंधित प्रश्नों पर स्वयं निर्णय लेना आवश्यक हो जाए, तो स्वयं निर्णय लेना उनका अधिकार है, जबकि दोनों सदनों ने अपने विशेषाधिकारों के अनन्य न्यायाधीश होने का दावा किया। अंततः, दोनों दृष्टिकोणों का व्यवहार में सामंजस्य हो गया और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान धीरे-धीरे विकसित हुआ। न्यायालयों द्वारा विहित यह समाधान संसदीय क्षेत्राधिकार के पक्ष में कुछ बड़े अपवादों के साथ, उनके समक्ष मुकदमेबाजी में उठने वाले विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के अपने सिद्धांत के अधिकार पर जोर देना है। इनमें से दो हैं प्रत्येक सदन का अपनी आंतरिक कार्यवाही पर अनन्य क्षेत्राधिकार, और किसी भी सदन का 'अवमानना करने और दंडित करने का अधिकार है। श्रीमान मे ने कहा कि हालांकि यह दावा नहीं किया जा सकता कि न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधिकार की इस धारणा में किसी भी सदन ने औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की है, लेकिन एक शताब्दी से अधिक समय तक किसी भी संघर्ष की अनुपस्थिति मौन स्वीकृति के एक निश्चित उपाय का संकेत दे सकती है। दूसरे शब्दों में, विशेषाधिकार के अस्तित्व और सीमा के बारे में प्रश्न को सामान्यतः न्यायालयों में न्यायोचित माना जाता है, जहां यह न्यायालयों के समक्ष लाए गए किसी भी विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो जाता है।

अवमानना के लिए दंड के संबंध में, प्रथाओं के अनुसार लेनदेन की एक समान प्रक्रिया चल रही है और धीरे-धीरे व्यवहार में सहमति का एक बड़ा क्षेत्र विकसित हुआ है। सैद्धांतिक रूप से, हाउस ऑफ कॉमन्स का दावा है कि विशेषाधिकार के उल्लंघन पर निर्णय लेने का उसका स्वीकृत अधिकार सिद्धांत रूप में विशेषाधिकारों के अस्तित्व और सीमा को

निर्धारित करने के अधिकार को दर्शाता है। इसने कभी भी इस दावे को स्पष्ट रूप से नहीं छोड़ा है। दूसरी ओर, न्यायालय संसद के विशेषाधिकारों को देश के कानून का हिस्सा मानते हैं, जिसका न्यायिक संज्ञान लेने के लिए वे बाध्य हैं। वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उठने वाले विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को तय करना और कानून की अपनी व्याख्या के अनुसार इसे तय करना अपना कर्तव्य मानते हैं। स्वाभाविक रूप से, इस द्वैतवाद के परिणामस्वरूप विशेषाधिकार के मामलों में न्यायालयों के निर्णयों को सदन द्वारा बाध्यकारी नहीं माना जाता है और न ही न्यायालयों द्वारा सदन के निर्णयों को बाध्यकारी माना जाता है; और जैसा कि श्रीमान मे ने बताया है, सैद्धांतिक स्तर पर, पुराना द्वैतवाद अभी भी अनसुलझा है। तथापि व्यवहार में "क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर गतिरोध की अपेक्षा विशेषाधिकार की प्रकृति और सिद्धांतों पर कहीं अधिक सहमति है और मे इन सामान्य निष्कर्षों का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करते हैं:

(1) ऐसा प्रतीत होता है कि विशेषाधिकार के प्रश्नों पर निर्णय देने के उद्देश्य से, कोई भी सदन स्वयं न्याय के सामान्य न्यायालयों पर सर्वोच्चता का दावा करने का हकदार नहीं है, जिसका आनंद संसद के अविभाजित उच्च न्यायालय को प्राप्त था। राजा और दोनों सदनों से मिलकर बनी संसद की सर्वोच्चता एक विधायी सर्वोच्चता है, जिसका अकेले कार्य करने वाले किसी भी सदन के विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार से कोई लेना-देना नहीं है।

(2) दोनों सदनों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि, चूंकि कोई भी सदन स्वयं कानून में कुछ नहीं जोड़ सकता, इसलिए कोई भी सदन अपनी घोषणा द्वारा कोई नया विशेषाधिकार नहीं बना सकता। इसका तात्पर्य यह है कि विशेषाधिकार वस्तुनिष्ठ है और इसकी सीमा निश्चित की जा सकती है, और यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि यह न्यायालयों को ज्ञात है।

दूसरी ओर, न्यायालय स्वीकार करते हैं:-

(3) यह कि प्रत्येक सदन का अपनी आंतरिक कार्यवाही पर नियंत्रण पूर्ण है और न्यायालयों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

(4) किसी भी सदन द्वारा अवमानना के लिए किया गया समर्पण व्यवहार में उसके अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि कथित अवमानना के तथ्यों को समर्पण के वारंट पर बताए जाने की आवश्यकता नहीं है।

यह उस उल्लेखनीय अंग्रेजी प्रतिभा को श्रद्धांजलि है, जिसने पारंपरिक तरीके से लेनदेन के माध्यम से उन समस्याओं के लिए व्यावहारिक तदर्थ समाधान खोजे, जो सुलझने योग्य नहीं लगती। श्रीमान मे के शब्दों में, इस प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ है कि सौ वर्षों से हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने विशेषाधिकारों को न्यायालयों के निर्णय के अधीन करने से इनकार नहीं किया है, और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि इसने अपने विशेषाधिकारों के अस्तित्व और सीमा पर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को व्यावहारिक मान्यता दी है। दूसरी ओर, न्यायालयों ने हमेशा किसी भी अंतिम उपाय में सदन द्वारा अपने किसी भी मान्यता प्राप्त विशेषाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मोटे तौर पर कहा जाए तो, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा की गई शक्तियों और विशेषाधिकारों की स्थिति यही है।

अब विचार करने के लिए जो बात बची है, वह उस विशेष विशेषाधिकार की स्थिति के बारे में है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, अर्थात् यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार कि क्या अवमानना की गई है और ऐसी अवमानना के लिए दंडित करना तथा यह दावा करना कि किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंडित करने वाला सामान्य आदेश या वारंट न्यायालय में परीक्षण योग्य नहीं है। क्या सदन की ओर से श्रीमान सीरवर्ड द्वारा दावा किया गया यह अंतिम अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित विशेषाधिकार का हिस्सा है, या यह न्यायालयों और सदन के बीच सम्मेलन द्वारा या

सौजन्य के सिद्धांत द्वारा, या कानूनी अनुमान के मामले के रूप में विकसित समझौते का परिणाम है? अब हमें इसी प्रश्न की ओर मुड़ना चाहिए।

इस संकीर्ण प्रश्न के निस्तारण के दौरान भी हमें लगता है कि व्यापक रूप से कुछ हद तक उस कठिन मार्ग का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में न्यायिक निर्णयों द्वारा इस प्रश्न पर कानून धीरे-धीरे विकसित हुआ है। जिस प्रकार विशेषाधिकारों के प्रश्न के निस्तारण के लिए सैद्धांतिक रूप में हमने स्वयं को मुख्य रूप से श्रीमान मे के कथनों पर आधारित किया है, उसी प्रकार इस प्रश्न के विधिक विकास से निस्तारण तक हम मुख्य रूप से इन्हीं निर्णयों पर ही निर्भर रहेंगे। श्रीमान सीरवई और श्रीमान सीतलवाड, दोनों ने हमें अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए बड़ी संख्या में अंग्रेजी निर्णयों का हवाला दिया है और निष्पक्षता के आधार पर हम सोचते हैं कि हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि निर्णयों का उल्लेख करना चाहिए ताकि यह इंगित किया जा सके कि विशेषाधिकार और इसके साथ जुड़े सिद्धांतों का इंग्लैंड में धीरे-धीरे विकास कैसे हुआ।

हमारे उद्देश्य के लिए, कहा जा सकता है कि कहानी वर्ष 1677 में प्रारम्भ होती है जब किंग्स बेंच की अदालत को द अल ऑफ शैप्ट्सबरी मामले में इस समस्या के एक भाग के लिए विचार करने का अवसर मिला था; यह समय-समय पर विकसित होता है जब संसदीय विशेषाधिकारों की इस समस्या का कोई न कोई पहलू वेस्टमिंस्टर की अदालतों के सामने आता है जब तक कि हम 1884 तक नहीं पहुँच जाते जब ब्रैडलाफ बनाम गॉसेट का मामला निर्णीत हुआ।

शैप्ट्सबरी के मामले से आइए प्रारम्भ करते हैं। इस मामले में अल ऑफ शैप्ट्सबरी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक आदेश के अन्तर्गत टॉवर ऑफ लंदन को सौंप दिया गया था, जिसमें टॉवर ऑफ लंदन के आरक्षियों को उसे प्राप्त करने और उसे सदन की इच्छा के अनुसार अपने अधिकार में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था "इस सदन के विरुद्ध किए गए उच्च अवमानना के लिए यह उस ओर से एक पर्याप्त वारंट होगा।" अल ऑफ शैप्ट्सबरी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पर किंग्स बेंच के न्यायालय के समक्ष मामला उठाया और आग्रह किया कि अल को सौंपना कानूनन अनुचित था, क्योंकि "उच्च अवमानना" के सामान्य आरोप को बरकरार रखना न्यायालय के लिए अनिश्चित था। उनकी ओर से यह भी तर्क दिया गया कि लॉर्ड्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार के संबंध में उक्त क्षेत्राधिकार की सीमाएं सामान्य कानून द्वारा सीमित थीं और इसका प्रयोग न्यायालयों में जांच योग्य था। इस दलील को न्यायालय ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया, जिसने कहा कि न्यायालय एक उच्च न्यायालय के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता। मुख्य न्यायाधीश रेनफोर्ड ने कहा कि "इस न्यायालय के पास मामले का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, और इसलिए, रिटर्न का रूप विचारणीय नहीं है।" विद्वान मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, आक्षेपित दण्ड लॉर्ड्स द्वारा अवमानना के लिए दिए गए निर्णय के निष्पादन में था; और इसलिए, यदि अल को जमानत दी जाती है, तो उसे निष्पादन से मुक्त कर दिया जाएगा; क्योंकि अवमानना के लिए, निष्पादन के लिए कोई अन्य निर्णय नहीं है। इसलिए, इस मामले ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास अवमानना के लिए वारंट जारी करने का अधिकार था और चूंकि इस तरह से दण्डित व्यक्ति का दण्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिए गए निर्णय के निष्पादन में था, इसलिए उस ओर से जारी सामान्य वारंट किंग्स बेंच डिवीजन द्वारा जांच योग्य नहीं था।

इसके पाँच साल बाद, जय ने गिरफ्तारी से रिहाई के लिए किंग्स बेंच डिवीजन में याचिका दायर की और टोपहम, सार्जेंट ऑफ आर्म्स के खिलाफ उसे गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के लिए मुकदमा दायर किया। टोपहम ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हवाला दिया, लेकिन न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और जय के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके सात साल बाद, हाउस ऑफ कॉमन्स ने घोषणा की कि उक्त फैसला "अवैध, संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाला और संसद के अधिकारों के लिए हानिकारक" था। इस दृष्टिकोण पर कार्य करते हुए दोनों न्यायाधीशों को सदन के बार में बुलाया गया और उनके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने

को कहा गया। बार के समक्ष उपस्थित होकर, सर फ्रांसिस पेम्बर्टन ने सदन को बताया कि वे छह साल से अधिक समय से न्यायालय से बाहर हैं और उन्हें ठीक से याद नहीं है कि उस मामले में क्या हुआ था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें बिना पर्याप्त सूचना दिए बार में बुलाया गया कि उनके विरुद्ध क्या आरोप है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि यदि प्रतिवादी यह दलील दे कि उसे इस सदन के आदेश से गिरफ्तार किया गया है और उसे किंग्स बेंच के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दलील देनी चाहिए, तो वह सदन को संतुष्ट कर देंगे कि इस तरह की दलील को स्वारिज कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी आगे की दलीलें पेश करने के लिए न्यायालय के अभिलेखों को देखने के लिए समय मांगा। अंततः, दोनों न्यायाधीशों को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। इस घटना की इंग्लैंड में संवैधानिक कानून के सभी प्रमुख लेखकों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है और यह कहना काफी उपयुक्त होगा कि इसे हाउस ऑफ कॉमन्स के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक प्रकरण माना गया है। यह कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है कि 1689 में जो कुछ हुआ था, उसे सदन द्वारा वर्तमान कार्यवाही में करने का प्रयास 14 साल बाद किया जा रहा है, जब यह देश एक लिखित संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक जीवन शैली का आदी हो चुका है।

हालांकि, इस मामले के समापन से पूर्व, यह संक्षेप में इंगित करना महत्वपूर्ण होगा कि बाद के न्यायाधीशों ने हाउस ऑफ कॉमन्स के इस आचरण को कैसे देखा है। सर फ्रांसिस बर्डेट बनाम एबॉट के मामले में, मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलनबरो ने कहा: "उस मामले के अभिलेख को देखने पर यह आश्चर्यजनक है कि कैसे एक न्यायाधीश से पूछताछ की गई, तथा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा उसे जेल भेजा गया, क्योंकि उसने ऐसा निर्णय दिया था, जिससे इस स्थान पर बैठा कोई भी न्यायाधीश असहमत नहीं हो सकता था", और उन्होंने आगे कहा कि बर्डेट में उपस्थित अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया था कि संभवतः उस समय मामले को इतनी अच्छी तरह से समझा नहीं गया था, जिसके बाद लॉर्ड एलनबरो ने टिप्पणी की कि यह क्रांति के बाद की बात है, जो इस तरह के कारण के लिए ऐसे दण्ड को थोड़ा चौंकाने वाला बनाता है; और उन्होंने बताया कि यह याद रखना चाहिए कि लॉर्ड पेम्बर्टन उस समय नुकसान में थे, क्योंकि वे लॉर्ड रसेल के मुकदमे में बैठने वाले न्यायाधीशों में से एक थे, और इसलिए क्रांति के बाद उनकी लोकप्रियता अधिक नहीं थी, जब उनके मामले में निर्णय और अटैडर को हाल ही में संसद द्वारा उलट दिया गया था।

इसी तरह, स्टॉकडेल बनाम हैसर्ड के मामले में, इस घटना का उल्लेख करते हुए, मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड डेनमैन ने घोषणा की: "कन्वेंशन संसद के प्रति हमारा सम्मान और कृतज्ञता के कारण हमें इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि कारावास की यह सजा उतनी ही अन्यायपूर्ण और अत्याचारी थी जितनी कि मनमानी शक्ति के वे कार्य जिनके लिए उन्होंने राजा जेम्स को उनके ताज से वंचित किया था।"

अगला मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह एशबी बनाम व्हाइट का मामला है। उस मामले में, वादी आइल्सबरी का एक बर्जिस था, और इस तरह संसद के दो सदस्यों के लिए वोट देने का हकदार था। चुनाव के दिन उसने प्रतिवादियों से, जो नगर के रिटर्निंग ऑफिसर थे, अपना वोट प्राप्त करने का अनुरोध किया। प्रतिवादियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और वादी को वोट देने की अनुमति नहीं दी गई। इसके कारण रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ धोखाधड़ी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसका वोट देने से इनकार करने का मुकदमा चला, और इसका अंत जूरी द्वारा हजने के लिए एक पंचाट के साथ हुआ। गिरफ्तारी के निर्णय के सम्बन्ध में क्वींस बेंच के समक्ष दायर एक मुकदमे में यह तर्क किया गया कि वादी द्वारा किया गया दावा पोषणीय नहीं था। यह मुकदमा बहुमत के फैसले के अनुसार सफल हुआ, मुख्य न्यायाधीश होल्ट ने असहमति जताई। न्यायमूर्ति गोल्ड ने माना कि उनका मत है कि प्रतिवादियों के विरुद्ध लाया गया मुकदमा स्वीकार्य नहीं है, और अपने निष्कर्ष के समर्थन में उन्होंने चार कारण दिए: पहला, क्योंकि प्रतिवादी न्यायाधीश है, और इसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं; दूसरा, क्योंकि यह एक संसदीय मामला है, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है; तीसरा, वादी के मतदान का विशेषाधिकार संपत्ति या लाभ का मामला नहीं है, इसलिए इसमें बाधा डालना केवल हानिकारक है; और चौथा, यह जनता से संबंधित है, और यह एक प्रचलित अपराध है।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश होल्ट ने बहुमत की राय से असहमति जताई और कुछ

हद तक सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। अपने सहयोगियों द्वारा व्यक्त की गई राय का जिक्र करते हुए कि न्यायालय इस मामले पर फैसला नहीं कर सकता क्योंकि यह एक संसदीय मामला था, उन्होंने कहा: "ओ! हर तरह से उस के प्रति बहुत कोमल हो जाओ। इसके अतिरिक्त, यह जटिल है, और राय में विरोधाभासी हो सकता है। लेकिन यह मामला संसद में कभी भी सवाल नहीं उठ सकता; क्योंकि इस पर सहमति है कि जिन लोगों के लिए वादी ने मतदान किया था, वे निर्वाचित थे; इसलिए उनके वोट से वंचित होने के लिए कार्रवाई की जाती है।" उन्होंने स्वीकार किया कि न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण या विस्तार नहीं करना चाहिए; लेकिन उनका मानना था कि न्यायालय को राजा द्वारा दिए गए चार्टर या किसी प्रथा या प्रिस्क्रिप्शन के मामले पर संसद पर अतिक्रमण किए बिना निर्णय लेना चाहिए। उनका निष्कर्ष यह था कि यदि यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मामला है, तो "हम अपनी शपथ से इस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं"। हालाँकि, इस निर्णय का अवमानना के प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है।

हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना के प्रश्न से संबंधित अगला मामला आर. बनाम पैटी का है। उस मामले में, पैटी और चार अन्य को सदन के अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट द्वारा न्यूगेट को सौंप दिया गया था। वारंट आख्यापक वारंट था और यह दर्शाता था कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों ने सदन के अधिकारक्षेत्र की अवमानना की थी और इसके ज्ञात विशेषाधिकारों का खुला उल्लंघन किया था। इस वारंट की वैधता को उक्त व्यक्तियों ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसमें कई कमियाँ थीं। हालाँकि, मामले में बहुमत का निर्णय यह था कि कथित कमियों के लिए वारंट को उलटा नहीं किया जा सकता था और न्यायालय के पास इस मामले का निस्तारण करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स अपने स्वयं के विशेषाधिकारों के उचित न्यायाधीश था। न्यायमूर्ति पॉविस ने अल ऑफ शैपट्सबरी के मामले में पहले के निर्णय का हवाला दिया और कहा: "यदि अवमानना के लिए सभी दण्डों, यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए दण्डों की भी जांच की जाए, तो उनका आधार नहीं होगा। ऐसे मामलों में हमारे वारंट छोटे होते हैं, जैसे अवमानना के लिए, या ऐसे किसी मामले में अवमानना के लिए है। इसलिए चांसरी में अवमानना के लिए दण्ड पूरी तरह से जवाब न देने आदि में अवमानना के लिए होते हैं, और क्या यह दण्ड पर्याप्त नहीं होगा?" उन्होंने कहा कि "हाउस ऑफ कॉमन्स एक महान न्यायालय है, और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को सही तरीके से किया जाना चाहिए, और इस मामले को उनके वारंट में विशेष रूप से वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है; उसी कारण से जैसे हम लोगों को दो श्रेणियों के न्यायालय के नियम द्वारा दण्डित करते हैं, और ऐसे दण्ड उचित माने जाते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि हम जो करते हैं उसे समझें।" इस प्रकार यह देखा जाएगा कि उस मामले में बहुमत का निर्णय इस आधार पर हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय था और वेस्टमिंस्टर में उच्च न्यायालयों की तरह, यह अपने अवमानना के लिए लोगों को दण्डित करने के लिए एक छोटा सामान्य वारंट जारी करने का हकदार था। यदि ऐसा सामान्य वारंट जारी किया गया था और इसे वेस्टमिंस्टर में न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो इसे उसी सम्मान के साथ माना जाना चाहिए जैसा कि उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए समान वारंटों को दिया जाता है। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश होल्ट इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए राजी नहीं थे कि आरोपित कारावास ऐसा था जिससे इंग्लैंड के स्वतंत्र व्यक्ति को बाध्य होना चाहिए"; और उन्होंने आगे कहा, "क्योंकि यह, जो केवल एक कानूनी कार्य था, हाउस ऑफ कॉमन्स के वोट से अवैध नहीं बनाया जा सकता था; क्योंकि न तो संसद का सदन, और न ही दोनों सदन संयुक्त रूप से, विषय की स्वतंत्रता या संपत्ति का निस्तारण कर सकते थे; इस उद्देश्य के लिए महारानी को शामिल होना चाहिए और यह कि ऐसे कार्यों के लिए उनकी कई सहमतियों की आवश्यकता थी, जिसमें विषय की स्वतंत्रता की महान सुरक्षा निहित थी।" (पृष्ठ 236)। इसलिए, इस मामले से यह पता चलता है कि वेस्टमिंस्टर की अदालतों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट की वैधता की जांच करना अनुचित होगा।

यह हमें 1750 के मर्रे के मामले में लिए गए निर्णय की ओर ले जाता है। जब मर्रे को सदन के बार में लाया गया, तो घुटने टेकने से इनकार करने के कारण हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया था। सदन द्वारा यह घोषित किया गया था कि मर्रे द्वारा घुटने टेकने से इनकार करना "विशेषाधिकार की सबसे खतरनाक अवमानना" थी। जब

न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका पेश की गई, तो इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि "हाउस ऑफ कॉमन्स निस्संदेह एक उच्च न्यायालय है और सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का न्याय करने का अधिकार है, और हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अवमानना क्या थी, क्योंकि यदि ऐसा प्रतीत होता है, तो हम उसका न्याय नहीं कर सकते।" यही विचार न्यायमूर्ति राइट द्वारा व्यक्त किया गया है। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स उनके अपने न्यायालय से श्रेष्ठ है, और उनका न्यायालय वेस्टमिंस्टर हॉल में किसी अन्य न्यायालय में अवमानना के लिए दण्डित व्यक्ति को जमानत देने की अनुमति नहीं दे सकता। न्यायमूर्ति डेनिसन ने सहमति व्यक्त की और अपनी राय व्यक्त की कि वेस्टमिंस्टर हॉल में न्यायालय उनके विशेषाधिकारों और उनके विरुद्ध अवमाननाओं का न्याय करने के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स से निम्न था। यह मामला फिर से इस आधार पर आगे बढ़ता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय है, और इस तरह इसके वारंट की जांच नहीं की जा सकती।

समसामयिक बिन्दु के संदर्भ में अगला प्रासंगिक मामला ब्रास क्रॉस्बी का है। ब्रास क्रॉस्बी लंदन के लॉर्ड मेयर और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, और मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने की अनुमति दी थी, जिसे सदन के अध्यक्ष द्वारा सदन के आदेश के द्वारा जारी वारंट के अंतर्गत जेल भेजा गया था। सदन ने धारित किया कि लॉर्ड मेयर सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी था, और इस तरह उसे टॉवर ऑफ लंदन के लिए दण्डित किया गया था। इस आदेश की वैधता को ब्रास क्रॉस्बी ने चुनौती दी थी। हालाँकि, यह चुनौती इस आधार पर विफल हो गई कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स किसी चीज़ को अवमानना या विशेषाधिकार का उल्लंघन मानता है, तो उनका निर्णय एक दोषसिद्धि होती है, और परिणामस्वरूप उनका दण्ड निष्पादन में रहता है। जैसा कि मुख्य न्यायमूर्ति लॉर्ड डे ब्रे ने कहा, "कोई भी अदालत किसी ऐसे व्यक्ति को बरी या जमानत नहीं दे सकती जो किसी अन्य अदालत के फैसले से निष्पादन में है," और इसलिए, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि "हाउस ऑफ कॉमन्स के पास दण्डित करने का अधिकार है, और वह दण्ड एक निष्पादन होता है, सवाल यह है कि यह न्यायालय क्या कर सकता है? उन्होंने इस टिप्पणी के साथ उत्तर दिया कि "यह कुछ नहीं कर सकता है जब कोई व्यक्ति सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के फैसले से निष्पादन में है; ऐसे मामले में, यह न्यायालय अपील का न्यायालय नहीं होता है।" इस दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए, न्यायमूर्ति ब्लैकस्टोन ने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय है और वह इस तर्क से प्रभावित हुए कि "यह अत्यंत भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, यदि इस हॉल के प्रत्येक न्यायालय को अवमानना के लिए हॉल के अन्य न्यायालयों के दण्डों की जांच करने का अधिकार हो; इसलिए अवमानना के मामले में प्रत्येक संबंधित न्यायालय का निर्णय और दण्ड अंतिम और बिना किसी नियंत्रण के होनी चाहिए।" इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह निर्णय उसी आधार पर आगे बढ़ा, जिसे तब तक मान्यता मिल चुकी थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय है और इस तरह से अवमानना का दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दंडित करने का क्षेत्राधिकार है। इस तरह की अवमानना के संबंध में सदन द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट को वेस्टमिंस्टर हॉल में अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए समान वारंट के समान दर्जा दिया गया था।

इस मामले के समापन से पहले, हम संयोगवश इस निर्णय पर मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड डेनमैन द्वारा की गई टिप्पणी पर ध्यान दे सकते हैं। लॉर्ड डेनमैन ने कहा: "अब हम इतिहास के तौर पर जानते हैं कि उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स क्राउन के साथ मिलकर लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों पर हमला करने में लगा हुआ था। फिर भी उस विद्वान न्यायाधीश [न्यायमूर्ति ब्लैकस्टोन] ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बनाए रखने के लिए अपने बिना शर्त संकल्प की घोषणा की, भले ही इससे उसकी शक्ति का दुरुपयोग होता।"

इस विषय पर अगला महत्वपूर्ण निर्णय सर फ्रांसिस बर्डेट का मामला है। यह मामला सर फ्रांसिस बर्डेट द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के खिलाफ उनके घर में घुसने और उन्हें टॉवर में कैद करने के लिए प्रारम्भ किए गए अतिक्रमण के मुकदमे से उत्पन्न हुआ था। बचाव में उठाया गया तर्क यह था कि प्रतिवादी का आचरण सदन के आदेश द्वारा उचित ठहराया गया था, जिसके बाद सदन ने फैसला सुनाया था कि वह सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर विचार करने वाले

एक अपमानजनक और निंदनीय पत्र को प्रकाशित करके सदन की अवमानना का दोषी है। इस मामले पर विस्तार से बहस की गई और जैसा कि मे ने बताया: "यह मामला कॉमन्स की शक्ति (जैसा कि लॉर्ड शैप्ट्सबरी का मामला लॉर्ड्स के लिए करता है) के अंतर्गत अवमानना के लिए दण्डित करने के लिए प्रमुख प्राधिकारियों द्वारा प्रदान करता है।" इस मामले में वारंट एक आख्यापक वारंट था और अवमानना हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना थी। बर्टेन द्वारा की गई दलील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन दलील को खारिज करने के लिए दिए गए कारण महत्वपूर्ण हैं। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलेनबरो ने इस प्रश्न पर गहनता से विचार किया है। उन्होंने कहा कि संसद में पूर्व दृष्टांतों के आधार पर एवं कानून द्वारा मान्यता के आधार पर तथा सभी न्यायाधीशों की निरंतर मान्यता के आधार पर उन्हें यह सोचना चाहिए था कि इस प्रश्न को समाप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राधिकार था, अर्थात्, क्या कॉमन्स द्वारा सदन के पास अपने विशेषाधिकारों की अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति है? सदन के पास निस्संदेह वह शक्ति थी। इस आधार पर मामले का निस्ताराण करने के लिए आगे बढ़ते हुए, लॉर्ड एलेनबरो ने धारित किया कि सदन तथ्य और प्रकाशन के प्रभाव दोनों के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम था, जिसे उसके द्वारा मानहानिपूर्ण माना गया था, और उन्होंने कहा कि विधिक न्यायालय के निर्णय के अनुरूप (और संसद के किसी भी सदन के निर्णयों को सामान्य कानून के न्यायालयों की तुलना में कम आधिकारिक आधार पर नहीं रखा जा सकता है), सदन को दोनों का निर्णय लेने के रूप में धारित किया जाना चाहिए, जहां तक किसी भी प्रश्न का संबंध है जो अन्य न्यायालयों में उठ सकता है।

अगला सवाल जिस पर लॉर्ड एलेनबरो ने विचार किया, वह यह था कि यदि वारंट में ही दण्डित करने के लिए पर्याप्त आधार का खुलासा किया गया है, और सदन के अधिकारियों को इसे निष्पादित करने का आदेश दिया गया है, तो इसके अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए औचित्य सिद्ध होता है, "जब तक कि वारंट को निष्पादित करने के लिए बाद में कोई उचित साधन इस्तेमाल नहीं किया गया हो।" ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि यदि जारी किया गया वारंट पहली नज़र में अनुचित, अवैध या असाधारण प्रतीत होता है, तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए याचिका पर विचार करने और याचिकाकर्ता को राहत देने का हकदार होगा। लॉर्ड एलेनबरो ने इस तर्क पर विचार किया और राय व्यक्त की कि यदि दण्ड आम तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना के लिए प्रतीत होता हो, तो वह न तो उस न्यायालय के मामले में, न ही किसी अन्य उच्चतर न्यायालय के मामले में, आगे की जांच करेंगे; लेकिन अगर यह अवमानना के लिए दण्ड होने का दावा नहीं करता है, लेकिन रिटर्न में दिखाई देने वाले किसी मामले के लिए जिसे किसी भी उचित इशारे से न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता है, लेकिन दण्ड का आधार स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से मनमाना, अन्यायपूर्ण और सकारात्मक कानून या राष्ट्रीय न्याय के हर सिद्धांत के विपरीत है, ऐसे मामले में न्यायालय को इसे देखना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए जैसा कि न्याय उस न्यायालय से अपेक्षित कर सकता है जिसे उसने आगे बढ़ाने का दावा किया हो (पृष्ठ 558-60)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह स्वीकार करते हुए भी कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट की जांच करना अनुपयुक्त या अनुचित होगा, लॉर्ड एलेनबरो ने यह स्पष्ट किया कि यह सम्मेलन इस अपवाद के अधीन होगा कि जहां भी रिटर्न से या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि दण्ड स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण था, न्यायालय पक्ष को राहत देने के लिए शक्तिहीन नहीं होगा।

यह मामला राजकोष न्यायालय के समक्ष अपील में चला गया और अपील के अंतर्गत निर्णय की पुष्टि की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय निर्णय सुनाए जाने से पहले, लॉर्ड एल्डन ने माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा कि प्रतिवादियों के अधिवक्ता की बात तब तक नहीं सुनी जानी चाहिए जब तक कि उन्हें उनके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर न्यायाधीशों की सलाह नहीं मिल जाती। यह प्रश्न था: "क्या, यदि कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज ने किसी कृत्य को न्यायालय की अवमानना के रूप में घोषित किया है, तो अवमानना के लिए वारंट के अंतर्गत दण्डित किया गया था। विशेष परिस्थितियों के बिना इस तरह के निर्णय को सामान्य रूप से बताते हुए मामला किंग्स बेंच के न्यायालय के समक्ष लाया गया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा वारंट का निर्धारण करते हुए, अवमानना के ऐसे निर्णय को सामान्य रूप से बताते हुए; क्या उस मामले में किंग्स बेंच का न्यायालय कैदी को मुक्त कर देगा, क्योंकि

विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ, जिनसे अवमानना उत्पन्न हुई, वारंट में निर्धारित नहीं थी।" इस प्रश्न को न्यायाधीशों को सौंपे जाने के बाद और उन्होंने कुछ मिनटों के लिए आपस में परामर्श किया, लॉर्ड सीएच. बैरन रिचर्ड्स ने अपनी सर्वसम्मति राय दी कि ऐसे मामले में किंग्स बेंच का न्यायालय मुक्त नहीं करेगा। इस राय को स्वीकार कर लिया गया और बर्डेट की अपील को प्रतिवादी को बुलाए बिना खारिज कर दिया गया। इस मामले में, लॉर्ड एस्किन ने कहा कि "हाउस ऑफ कॉमन्स, चाहे वह न्यायालय हो या न हो, हर दूसरे न्यायाधिकरण की तरह, स्वयं को अवरोध और अपमान से बचाने और अपनी गरिमा और चरित्र को बनाए रखने की शक्ति रखता है। यदि कानून की गरिमा को बनाए नहीं रखा जाता है, तो इसकी ख्याति नष्ट हो जायेगी और पुनः कभी नहीं वापस लौटेगी। कानून की गरिमा के लिए दृढ़ता से महसूस करते हुए, मैंने इतना कहना जरूरी समझा; और केवल इतना जोड़ना है कि मैं न्यायाधीशों द्वारा दी गई राय से पूरी तरह सहमत हूँ।" यह मामला इस स्थिति को स्थापित करता प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए वारंट को एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के रूप में किया जाता था और इस तरह, वेस्टमिंस्टर हॉल की अदालतें इसकी अवमानना नहीं कर सकती।

1836-37 में जॉन जोसेफ स्टॉकडेल से जुड़े मामलों की एक श्रृंखला प्रारम्भ हुई। इन मामलों की श्रृंखला ने अंततः मिडिलसेक्स के शेरिफ की गिरफ्तारी और कारावास का कारण बना। ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ कामन्स के आदेश के अंतर्गत जेलों के निरीक्षकों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में से एक में स्टॉकडेल का वर्णन अपमानजनक तरीके से किया गया था, और इसलिए, उन्होंने 1836 में मेसर्स हैसर्ड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। बचाव में, हैसर्ड ने विशेषाधिकार का हवाला दिया और आग्रह किया कि विचाराधीन रिपोर्ट हाउस के आदेश के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी। न्यायालय ने धारित किया कि हाउस के आदेश ने कार्रवाई के लिए कोई बचाव प्रदान नहीं किया। फिर भी, जूरी का फैसला स्टॉकडेल के खिलाफ चला गया, जूरी ने स्पष्ट रूप से माना कि स्टॉकडेल का कथित अपमानजनक वर्णन उपयुक्त था। जिस समय इस मामले की सुनवाई हुई, लॉर्ड चीफ जस्टिस डेनमैन ने कुछ टिप्पणियाँ की जो हैसर्ड द्वारा दावा किए गए हाउस के विशेषाधिकारों के प्रतिकूल थीं। उन्होंने कहा कि "यह तथ्य कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने मेसर्स हैसर्ड को अपनी सभी संसदीय रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, उनके लिए या किसी भी पुस्तक विक्रेता के लिए कोई औचित्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि वाली संसदीय रिपोर्ट प्रकाशित करता है।" संयोग से, इस विवाद के परिणामस्वरूप यह जोड़ा जा सकता है कि, संसद ने अंततः संसदीय पत्र अधिनियम, 1840 पारित किया, जिसने इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया।

मामले के मेरिट पर जूरी के प्रतिकूल फैसले से विचलित हुए बिना, स्टॉकडेल ने एक और कार्रवाई प्रारम्भ की। इस कार्रवाई के प्रारम्भ होने से पहले, हाउस ऑफ कॉमन्स ने 1837 में अपने विशेषाधिकारों की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, और अपना जानबूझकर दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि किसी भी अदालत के लिए संसद के किसी भी सदन के निर्धारण के साथ असंगत विशेषाधिकार के मामलों पर निर्णय लेने का अनुमान लगाना संसद के कानून के विपरीत था। फिर भी, स्टॉकडेल द्वारा लाई गई इस दूसरी कार्रवाई में, सदन ने विशेषाधिकार का बचाव करने का फैसला किया। इस बचाव को खारिज कर दिया गया और नुकसान और लागत के भुगतान के लिए एक डिक्री पारित की गई। फिर भी, हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की और स्टॉकडेल और उनके विधिक सलाहकारों को मामले को कानून की अदालत में ले जाने के लिए दंडित करने से परहेज किया; इसके बजाय, इन्होंने फैसला किया कि मामले की विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत हर्जाना और लागत का भुगतान किया जाए।

इस परिणाम से उत्साहित स्टॉकडेल ने उक्त रिपोर्ट के एक और प्रकाशन के लिए तीसरी कार्रवाई की। इस बार श्रीमान हैसर्ड ने दलील नहीं दी; परिणामस्वरूप, निर्णय उनके खिलाफ गया, और शेरिफ की अदालत में जूरी द्वारा हर्जाने का आकलन 600 यूरो किया गया। मिडिलसेक्स के शेरिफ ने उस राशि के लिए शुल्क लगाया, लेकिन उन्हें सदन द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतियाँ दी गईं; और इसने स्वाभाविक रूप से उन्हें मामले में सतर्क कर दिया।

इसलिए, उन्होंने स्टॉकडेल को पैसे का भुगतान यथासंभव लंबे समय तक टाल दिया, लेकिन अंततः उन्होंने स्टॉकडेल को एक कुर्की के अंतर्गत पैसे का भुगतान किया। इस स्तर पर, हाउस ऑफ कॉमन्स ने अखाड़े में प्रवेश किया और स्टॉकडेल को सार्जेंट की हिरासत में सौंप दिया।

इसने शेरिफों को पैसे वापस करने को कहा और उनके इनकार करने पर, उन्हें

अवमानना के लिए भी दण्डित किया गया। इसके कारण शेरिफों द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पर उनकी रिहाई के लिए कार्यवाही की गई। हालाँकि, ये कार्यवाही विफल रही और यह मिडलसेक्स के शेरिफ के मामले में निर्णय का प्रभाव है।

स्वाभाविक रूप से, श्रीमान सीरवर्ड ने इस निर्णय पर काफी जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि न्यायालय ने स्वयं को मिडलसेक्स के शेरिफों को उनके कारावास के खिलाफ सुरक्षा देने में शक्तिहीन पाया, हालाँकि जिस आवरण ने सदन की अवमानना को जन्म दिया, वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिणाम था। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड डेनमैन, जिन्होंने स्वयं इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की थी और स्टॉकडेल बनाम हैसर्ड के मामले में अपने विशेषाधिकारों के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किए गए दावे की वैधता पर विवाद किया था फिर भी, शेरिफ द्वारा उठाए गए तर्क का उनके खिलाफ जवाब दिया जाना था, क्योंकि उनका दण्ड एक कानूनी वारंट द्वारा कायम था। लॉर्ड डेनमैन ने तब उन तीन आधारों की जांच की, जिन पर वारंट की वैधता पर सवाल उठाया गया था और उन्होंने पाया कि उन तर्कों में कोई सार नहीं था। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर पिछले निर्णयों पर विचार किया और देखा कि बर्डेट बनाम एबॉट के मामले में लॉर्ड एल्डन द्वारा निर्धारित परीक्षण प्रासंगिक था; और यह परीक्षण, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए दण्ड के सामान्य वारंट की तरह, अवमानना के आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट की बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही में जांच नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति लिटिलडेल ने मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड डेनमैन के साथ सहमति जताते हुए कहा: "यदि वारंट न्यायनिर्णयन के आधारों की घोषणा करता है, तो यह न्यायालय, कई मामलों में, उनकी वैधता की जांच करेगा; लेकिन, यदि ऐसा नहीं होता है, तो हम ऐसी जांच नहीं कर सकते। यहां हमें यह मानना होगा कि सदन ने पर्याप्त कारणों से निर्णय लिया; और वे न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति विलियम्स, जो लॉर्ड डेनमैन से भी सहमत थे, ने यह जोड़ना आवश्यक समझा कि "यदि रिटर्न, इस तरह के मामले में, किसी विशेष पोशाक को पहनने के लिए दण्ड का एक तुच्छ कारण दिखाता है, तो मुझे लॉर्ड एलेनबोरो द्वारा बर्डेट बनाम एबॉट के मामले में व्यक्त की गई राय से सहमत होना चाहिए, जहां उन्होंने आम तौर पर अवमानना का उल्लेख करने वाले दण्ड और रिटर्न द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और बेतुके आधार पर दिए जाने वाले दण्ड के बीच अंतर किया है। न्यायमूर्ति कोलरिज ने इस आधार पर अपना निष्कर्ष दिया कि "[हाउस ऑफ कॉमन्स का] अवमानना के मामलों में इस सामान्य रूप में निर्णय लेने का अधिकार विशेषाधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्हीं आधारों पर आधारित है जिस पर यह न्यायालय या कॉमन कॉज न्यायालय दण्ड में कोई कारण बताए बिना अवमानना के लिए दण्डित कर सकता है।" यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति कोलरिज ने यह स्पष्ट करना आवश्यक समझा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में किसी सामान्य वारंट की वैधता को चुनौती दिए जाने पर उसका सम्मान करने की मांग करने का अधिकार अब विशेषाधिकार का ही एक हिस्सा है; यह उस परंपरा का परिणाम है जिसके अनुसार रिकॉर्ड की उच्चतर अदालतों द्वारा जारी किए गए ऐसे वारंटों का आमतौर पर सम्मान किया जाता है। यह निर्णय 1840 में सुनाया गया था, और इसे इस विषय पर कानून के विकास में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस प्रकार, यह निर्णय श्रीमान सीरवर्ड की इस दलील में भी सहायता नहीं करता है कि यह सदन के विशेषाधिकार का एक हिस्सा है कि वह इस बात पर जोर दे कि उसके द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट को निर्णायक माना जाना चाहिए और कानून की अदालतों में इसकी जांच नहीं की जा सकती।

अगला मामला हॉवर्ड बनाम सर विलियम गोसेट का है। उस मामले में, बहुमत के फैसले से सदन के अध्यक्ष द्वारा हॉवर्ड के खिलाफ जारी किए गए वारंट को वारंट में पाई गई कुछ कमियों के परिणामस्वरूप अमान्य माना गया था। न्यायमूर्ति विलियम्स ने अकेले असहमति जताई। इस मामले में वारंट एक सामान्य वारंट था और न्यायमूर्ति विलियम्स ने माना कि वारंट की वैधता के खिलाफ उठाई गई तकनीकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सामान्य वारंट को इस तथ्य के निर्णायक के रूप में धारित किया जाना चाहिए कि जिस पक्ष के खिलाफ वारंट जारी किया गया था, उसे उचित रूप से अवमानना का दोषी ठहराया गया था। चूंकि निर्णय वादी हॉवर्ड के पक्ष में सुनाया गया था, इसलिए मामले को अपील में ले जाया गया, और बहुमत के फैसले को राजकोष न्यायालय द्वारा उलट

दिया गया। श्रीमान पार्क बी. ने वारंट की वैधता के खिलाफ लगाए गए कई तर्कों पर विचार किया और उन्हें खारिज कर दिया। राजकोष न्यायालय के निर्णय के लिए सामान्य आधार इन शब्दों में व्यक्त किया गया था: "हम स्पष्ट रूप से इस मत के हैं कि सदन के इन आदेशों के प्रति कम से कम उतना ही सम्मान दिखाया जाना चाहिए, तथा उतना ही अधिकार दिया जाना चाहिए जितना देश के सर्वोच्च न्यायालयों के प्रति; तथा, यदि साधारण न्यायालयों के अधिकारी उन्हें सौंपी गई प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य हैं, तथा इसलिए इसके द्वारा संरक्षित हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकारी भी उतने ही बाध्य तथा समान रूप से संरक्षित हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स संसद के उच्च न्यायालय का एक भाग है, जो बिना किसी संदेह के न केवल उच्च है, बल्कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तथा सामान्य विधिक न्यायालयों से उच्चतर है"।

इस प्रकार, इस निर्णय का परिणाम यह है कि संसद के उच्च न्यायालय का हिस्सा होने के नाते हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय है और इसके द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंटों की बारीकी से जांच नहीं की जा सकती है, जैसे कि अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए समान वारंटों को ऐसी जांच से मुक्त माना जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राजकोष न्यायालय ने इस मामले में देखा है कि संसद के उच्च न्यायालय के हिस्से के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स इस देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है और कानून की सामान्य अदालतों से ऊंचा है: और यह अपने शुरुआती करियर में संसद के सदन के मूल न्यायिक चरित्र को याद दिलाता है और इस तथ्य पर जोर देता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद के सदन का एक हिस्सा है, अभी भी इंग्लैंड में कानून का सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है।

इस श्रृंखला का अंतिम मामला जिसका हमें संदर्भ देना चाहिए वह ब्रैडलाफ बनाम गॉसेट का मामला है जिसमें क्वीन्स बेंच डिवीजन द्वारा निर्णय दिया गया है। यह निर्णय सीधे तौर पर प्रासंगिक या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि न्यायमूर्ति श्रीमान सरवर्ड स्टीफन द्वारा बताए गए कानून के कुछ कथनों पर अवलंब लेते हुए प्रदर्शित हुए, इसलिए हमें लगता है कि इसे बहुत संक्षेप में संदर्भित करना आवश्यक है। ब्रैडलाफ के मामले में न्यायालय को यह विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या सदन के एक प्रस्ताव के पालन में सदन से एक सदस्य को बाहर करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के सार्जेंट-आर्म्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है; और उत्तर नकारात्मक था। ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कानून के विपरीत होने के कारण चुनौती दी गई थी, और वास्तव में क्वीन्स बेंच डिवीजन ने ब्रैडलाफ के दावे पर इस आधार पर विचार करना प्रारम्भ किया कि उक्त प्रस्ताव कानून के प्रासंगिक प्रावधान के वास्तविक प्रभाव के अनुरूप नहीं हो सकता है; और फिर भी यह माना गया कि विवादित मामला हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित है, और इसलिए, क्वीन्स बेंच के न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के समक्ष यह जोर दिया गया कि प्रस्ताव कानून के प्रासंगिक प्रावधान के स्पष्ट रूप से विपरीत था। इस तर्क की वैधता को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति स्टीफन ने कहा कि अपने आंतरिक प्रबंधन से संबंधित अधिकारों और संकल्पों के संबंध में, सदन का ठीक वैसा ही संबंध है "जैसा कि हम इस न्यायालय के न्यायाधीश उन कानूनों के संबंध में हैं जो उन अधिकारों को विनियमित करते हैं जिनके हम संरक्षक हैं, और उन निर्णयों के संबंध में जो उन्हें विशेष मामलों पर लागू करते हैं; अर्थात्, वे सबसे गंभीर दायित्वों से बंधे हैं जो लोगों को किसी भी आचरण के लिए बाध्य कर सकते हैं, उनके आचरण को कानून के अनुसार निर्देशित करना जैसा कि वे समझते हैं"। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा "यदि वे इसे गलत समझते हैं, या (मैं अनुमान के लिए क्षमा चाहता हूँ) जानबूझकर इसकी अवहेलना करते हैं, तो वे गलत या अन्यायी न्यायाधीशों की तरह हैं; लेकिन किसी भी मामले में, मेरे विचार में उनके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं है। देश का कानून ऐसी कोई अपील नहीं करता है; ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसे पेश नहीं किया जा सकता है जिसमें किसी भी न्यायालय ने संसद के किसी भी सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया हो, हालांकि ऐसे मामले निरसंदेह कई हैं जिनमें न्यायालयों ने अपने संबंधित सदन के बाहर अपनी शक्तियों की सीमाएँ घोषित की हैं"। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यह उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था। श्रीमान सीरवर्ड का तर्क था कि यद्यपि प्रस्ताव संसदीय शपथ अधिनियम का उल्लंघन प्रतीत होता है, न्यायालय ने ब्रैडलाफ को कोई राहत देने से इनकार कर

दिया, और उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे समक्ष वर्तमान विवाद पर विचार करने में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस तर्क का स्पष्ट उत्तर यह है कि हम वर्तमान कार्यवाही में सदन के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित किसी मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम सदन की शक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, जो सदन की वारंटीवारी के बाहर कथित रूप से अवमानना के लिए नागरिकों को दंडित करने की है, और यह अनिवार्य रूप से विभिन्न विचारों को जन्म देता है।

इस मुद्दे से संबंधित प्रासंगिक निर्णयों की जांच करने के बाद, हम सोचते हैं कि यह देखना गलत नहीं होगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में अपने सामान्य वारंट की जांच न करने के अधिकार का दावा इस विचार पर अधिक आधारित है कि हाउस ऑफ कॉमन्स रिकॉर्ड के एक उच्च न्यायालय की स्थिति में है और अवमानना के दोषी पाए गए व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए सामान्य वारंट जारी करने का अधिकार अन्य उच्च न्यायालयों की तरह है। इस तरह की अवमानना के संबंध में रिकॉर्ड की उच्चतर अदालतों द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट की तरह, समान परिस्थितियों में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंटों को भी इसी तरह से माना जाना चाहिए। यह इस आधार पर है कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंटों को बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में अदालतों की जांच से परे माना जाता था। इस संबंध में, हमें यह जोड़ना चाहिए कि ऐसे सामान्य वारंटों की वैधता को मान्यता देते हुए भी, न्यायाधीशों ने अक्सर यह टिप्पणी की है कि यदि वे रिटर्न पर संतुष्ट थे कि ऐसे सामान्य वारंट तुच्छ या असाधारण कारणों से जारी किए गए थे, तो उनके लिए उनकी वैधता की जांच करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

यह महसूस करते हुए कि हमारे द्वारा अब तक जांचे गए निर्णयों द्वारा उजागर की गई स्थिति उनके द्वारा किए गए दावे के अनुकूल नहीं थी कि सामान्य वारंट का निर्णायक चरित्र अपने आप में विशेषाधिकार का एक हिस्सा है, श्रीमान सीरवई ने प्रिवी काउंसिल के निर्णयों पर बहुत दृढ़ता से अवलंब लिया है जो उनके दावे का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, और इसलिए, अब इन निर्णयों की ओर मुड़ना आवश्यक है। इस श्रृंखला में पहला निर्णय द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेम्बली ऑफ विक्टोरिया बनाम ह्यू ग्लास के मामले में है। उस मामले में विक्टोरिया कॉलोनी के संविधान अधिनियम द्वारा विक्टोरिया विधान सभा को उस विधानसभा की अवमानना और विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए एक सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति दी गई थी। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, ग्लास को सदन द्वारा अवमानना करने वाला घोषित किया गया और अध्यक्ष के वारंट के द्वारा, जो सामान्य शब्दों में था, उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद उनकी ओर से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई और इस याचिका को कॉलोनी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस आधार पर अनुमति दे दी कि संविधान कानून और औपनिवेशिक अधिनियम विधान सभा को वही शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करते जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थे। विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा अपील किए जाने पर, कॉलोनी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया गया और यह धारित किया गया कि संबंधित कानून और अधिनियम विधान सभा को वही शक्तियाँ और विशेषाधिकार देते हैं जो उक्त अधिनियमों के पारित होने के समय हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थे।

यह मानते हुए कि विधान सभा के पास हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही शक्तियाँ हैं, प्रिवी काउंसिल ने इन शक्तियों की प्रकृति और सीमा पर विचार करना प्रारम्भ किया। प्रिवी काउंसिल का निर्णय सुनाने वाले लॉर्ड कैरेंस ने कहा कि "बिना किसी संदेह के, विशेषाधिकारों में से एक और हाउस ऑफ कॉमन्स का सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार – अवमानना के लिए दण्ड देने का विशेषाधिकार है; और उस विशेषाधिकार के साथ-साथ, यह इस देश में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को स्वयं ही यह तय करने का अधिकार है कि अवमानना क्या है, और उस अवमानना के लिए वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार है, जिसमें यह कहा गया है कि दण्ड आम तौर पर सदन की अवमानना के लिए होता है, बिना यह निर्दिष्ट किए कि अवमानना की प्रकृति क्या है।" फिर उन्होंने इस तर्क के गुण-दोष पर विचार किया कि संबंधित संविधान अधिनियम विक्टोरिया की विधान सभा को सामान्य वारंट जारी करने की आकस्मिक शक्ति प्रदान नहीं करता है और इसे अस्वीकार कर

दिया। "[माननीय न्यायमूर्ति] मानते हैं एवं लॉर्ड कैरन्स ने कहा कि अवमानना के लिए दण्डित करने के विशेषाधिकार के बीच एक आवश्यक अंतर है, जैसा कि एक अवर न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जाएगा, अर्थात्, पहले स्वयं के लिए यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार कि अवमानना क्या है, फिर वारंट पर अवमानना की प्रकृति को बताना और फिर उस वारंट को किसी उच्च न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा के अधीन करना और यह मौका देना कि क्या उच्च न्यायाधिकरण अवर न्यायालय के निर्धारण से सहमत होगा या असहमत होगा, और एक निकाय का विशेषाधिकार जो बिना समीक्षा के खुद के लिए निर्धारित करता है कि अवमानना क्या है, और निर्धारण पर कार्य करते हुए, वारंट पर अवमानना की प्रकृति को निर्दिष्ट किए बिना उस अवमानना के लिए दण्डित करता है।" लॉर्ड कैरन्स के अनुसार, दो विशेषाधिकारों में से उत्तरार्द्ध पहले वाले की तुलना में अधिक उच्च और महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि यह वास्तव में अजीब होगा यदि, हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकारों और शक्तियों को हस्तांतरित करने की शक्ति के अंतर्गत, वह जो केवल एक हिस्सा होगा, और तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हिस्सा होगा, इस विशेषाधिकार और शक्ति को हस्तांतरित किया गया।

दूसरे शब्दों में, यह निर्णय दर्शाता है कि प्रिवी काउंसिल ने यह विचार किया कि सामान्य वारंट जारी करने और उक्त वारंट के निर्णायक चरित्र पर जोर देने की शक्ति स्वयं सदन की शक्ति और विशेषाधिकार का एक हिस्सा है। फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि एक अवर न्यायालय की शक्ति और विशेषाधिकार तथा एक उच्च न्यायालय की शक्ति और विशेषाधिकार के बीच अंतर किया गया है; और इसलिए, संविधान अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा बड़ी शक्ति प्रदान करने का इरादा माना जाता है, क्योंकि रानी विक्टोरिया की विधान सभा को प्रदान की जाने वाली स्थिति उच्च न्यायालय के समक्ष थी। दूसरे शब्दों में, विधान सभा को एक उच्च न्यायालय के रूप में माना गया और उसे प्रदान की गई शक्ति और विशेषाधिकार को शक्ति के दोनों पहलुओं को शामिल करने वाला माना गया। संयोग से, इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि इस प्रश्न पर विचार करते समय, लॉर्ड कैरन्स ने स्पष्ट रूप से पहले के अंग्रेजी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा, जिसमें इस शक्ति की सीमा और इसकी प्रकृति के बारे में समय-समय पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था।

अगला प्रिवी काउंसिल का निर्णय जिस पर श्रीमान सीरवर्ड ने अवलम्ब लिया वह फील्डिंग और अन्य बनाम थॉमस है। इस मामले में, नोवा स्कोटिया हाउस ऑफ असेंबली को दी गई शक्ति की सीमा के बारे में प्रश्न पर विचार किया जाना था, और प्रिवी काउंसिल द्वारा यह धारित किया गया कि उक्त असेंबली के पास यह निर्णय लेने की वैधानिक शक्ति थी कि उसके सदस्यों पर पड़ने वाले मानहानि के संदर्भ में उपस्थित होने के लिए उनके आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना विशेषाधिकार और अवमानना का उल्लंघन है, और उस उल्लंघन को कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए, उस कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिस पर तर्क आगे बढ़ा, या उन तथ्यों को जो कार्रवाई को जन्म देते हैं। यह केवल लॉर्ड हेल्सबरी द्वारा की गई एक टिप्पणी है जिसे उद्धृत किया जाना चाहिए। उस मामले में लॉर्ड हेल्सबरी ने कहा: "बर्देट बनाम एबॉट के मामले में संक्षेप में प्रस्तुत किए गए अधिकारी, और मिडिलसेक्स के शेरिफ के मामले में अनुसरण किए गए विवाद की सभी संभावनाओं से परे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार को स्थापित करते हैं कि वह बिना किसी सामान्य न्यायालय में अपील किए और बिना उन न्यायालयों द्वारा अपनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किए बिना अपनी प्रक्रिया द्वारा अपमान और हिंसा से स्वयं को बचा सकता है।" यह इस अवलोकन का अंतिम भाग है जो श्रीमान सीरवर्ड के मामले को कुछ हद तक समर्थन देता है। इस अवलोकन के बारे में हमें बस इतना ही कहना है कि यह दो पुराने निर्णयों पर आधारित है, जिनकी हम पहले ही जांच कर चुके हैं, और यह उन कुछ न्यायाधीशों द्वारा की गई आपत्तियों के साथ आसानी से मेल नहीं खाता है, जिन्हें याचिकाकर्ता के कारावास की वैधता की जांच करने के अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में इस बिंदु पर विचार करने का अवसर मिला था, जहां ऐसा प्रतीत हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी वारंट हाउस द्वारा किए गए रिटर्न पर स्पष्ट रूप से तुच्छ या असाधारण या काल्पनिक कारणों पर आधारित प्रतीत होता है।

अंतिम निर्णय जिस पर श्रीमान सीरवर्ड अवलम्ब लेते हैं, वह द वीन बनाम रिवर्स

का मामला है। उस मामले में, ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय को धारा 49 के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कहा गया था जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 194(3) के प्रावधानों के समान है। धारा 49 में इस प्रकार है:-

"सीनेट और प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जैसी संसद द्वारा घोषित की जाएँगी, और घोषित होने तक वे यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स की होंगी, तथा राष्ट्रमंडल की स्थापना के समय उसके सदस्यों और समितियों की होंगी।"

विचारणीय बिंदुओं में से एक यह था कि संविधान की धारा 49 द्वारा ऑस्ट्रेलिया में सीनेट और प्रतिनिधि सभा को प्रदान की गई शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की प्रकृति और सीमा क्या थी? ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में फिट्जपैट्रिक और ब्राउन को राष्ट्रमंडल की संसद के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट के अनुसरण में एडवर्ड रिवर्स द्वारा हिरासत में लिया गया था। ये वारंट सामान्य प्रकृति के थे और इनमें रिवर्स को उक्त दोनों व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। 10 जून, 1955 को, अभियोजकों के रूप में फिट्जपैट्रिक और ब्राउन के आवेदन पर, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति सिम्पसन) ने उक्त एडवर्ड रिवर्स को निर्देशित बंदी प्रत्यक्षीकरण के दो रिटों के लिए एक आदेश दिया। 15 जून, 1955 को, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कार्य करते हुए न्यायमूर्ति सिम्पसन ने निर्देश दिया कि मामले को ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के समक्ष बहस की जाए। इस तरह मामला उक्त उच्च न्यायालय के समक्ष चला।

उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 49 धारा 50 से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है और संविधान की सामान्य संरचना और उसके अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण से प्राप्त निहितार्थों के आधार पर इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। धारा 49 को धारा 50 से स्वतंत्र रूप से व्याख्यायित करते हुए, उच्च न्यायालय ने धारित किया कि राष्ट्रमंडल की स्थापना के समय हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा संसद को प्रदान की गई थी और चूँकि संसद ने उक्त धारा के अर्थ में कोई घोषणा नहीं की थी, इसलिए इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि संसद द्वारा सामान्य वारंट जारी किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करना आवश्यक था कि प्रासंगिक समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ क्या थी, और उच्च न्यायालय ने धारित किया कि धारा 49 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई संसद अवमानना का निर्णय करने और उसके लिए दण्डित करने के विशेषाधिकार का दावा कर सकती है। यह भी धारित किया गया कि यदि अध्यक्ष का वारंट किसी स्वीकृत विशेषाधिकार के उल्लंघन के अनुरूप है, तो यह निर्णायक है, भले ही विशेषाधिकार के उल्लंघन को सामान्य शब्दों में कहा गया हो। दूसरे शब्दों में, यह निर्णय निरसंदेह श्रीमान सीरवर्ड के इस तर्क का समर्थन करता है कि वर्तमान मामले में सदन द्वारा जारी एक सामान्य वारंट उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य नहीं है।

इस निर्णय के प्रभाव का अवलोकन करते हुए यह इंगित करना आवश्यक है कि जहां तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, इस मुद्दे का मुद्दा पहले से ही डिल बनाम मर्फी के साथ-साथ ह्यूग ग्लास में प्रिवी काउंसिल के निर्णयों द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था। वास्तव में, मुख्य न्यायाधीश डिवसन ने मामले के इस पहलू को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया है। स्वाभाविक रूप से, उन्होंने ह्यूग ग्लास में लॉर्ड कैरेस द्वारा की गई टिप्पणियों पर अवलंब लिया है और ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए बिंदु का फैसला करने में उक्त टिप्पणियों का पालन किया है। यही वह आधार है जिसे मुख्य न्यायाधीश डिवसन ने इस प्रश्न का निस्तारण करने में अपनाया था। इस दृष्टिकोण को अपनाने के बाद, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इंग्लैंड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति क्या थी, यह ह्यूग ग्लास में लॉर्ड कैरेस द्वारा की गई टिप्पणियों द्वारा ऑस्ट्रेलियाई अदालतों के मार्गदर्शन के लिए निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया था। फिर भी, उन्होंने टिप्पणी की है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में प्रश्न ऐसा है जिसे इंग्लैंड की कानून की अदालतों ने अपने निर्णय के लिए धारित किया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि "इंग्लैंड की अदालतें

न्यायिक निर्णय की एक लंबी प्रक्रिया के बाद उस स्थिति पर पहुंची है, जिसमें राजनीतिक विवाद भी शामिल था। इंग्लैंड में कानून का अंततः 1840 के आसपास निस्तारण हुआ।" यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से केस ऑफ द शेरिफ ऑफ मिडिलसेक्स को संदर्भित करती है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश के शब्दों को उद्धृत करते हुए "संक्षेप में कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन में विशेषाधिकार के अस्तित्व का निर्णय करना न्यायालय का काम है, लेकिन, एक निरसंदेह विशेषाधिकार को देखते हुए, अवसर और उसके प्रयोग के तरीके का निर्णय करना सदन का काम है। सदन का निर्णय उसके संकल्प और अध्यक्ष के वारंट द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि वारंट में दण्ड का आधार निर्दिष्ट किया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि क्या यह विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए कानून में पर्याप्त आधार है, लेकिन यदि वारंट स्पष्ट रूप से किसी स्वीकृत विशेषाधिकार के उल्लंघन के अनुरूप है तो यह निर्णायक है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि विशेषाधिकार के उल्लंघन को सामान्य शब्दों में कहा जाए। कानून का यह कथन उन मामलों, अर्थात् द केस ऑफ द शेरिफ ऑफ मिडिलसेक्स के अनुरूप प्रतीत होता है जिनके द्वारा इसे अंततः स्थापित किया गया था।" इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश डिवसन के अनुसार भी, विशेषाधिकार का अस्तित्व और सीमा एक न्यायोचित मामला है और इस पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। यदि वारंट एक आख्यापक वारंट है, तो न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि क्या यह विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए कानून के रूप में पर्याप्त आधार है, हालांकि, यदि वारंट अव्यक्त या सामान्य है, तो न्यायालय द्वारा विचार करना आवश्यक हो जाता है। हमारी राय में, इस निर्णय को सदन द्वारा किए गए दावे का समर्थन करने के रूप में मानना उचित नहीं होगा कि इसके सामान्य वारंट का निर्णायक चरित्र इसके विशेषाधिकार का अभिन्न अंग है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने वास्तव में स्वयं के लिए योग्यता के आधार पर के प्रश्न पर विचार नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि वे लॉर्ड कैरेस द्वारा की गई टिप्पणियों से वे बंधे थे और उन्होंने केवल यह बताने का दावा किया है कि उनकी राय में मिडिलसेक्स के शेरिफ के मामले में निर्णय का क्या प्रभाव है।

इसके अतिरिक्त, इस मामले का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश डिवसन ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 49 के निर्माण के बारे में विचार कर रहे थे, और जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ग्वेयर ने मध्य प्रांत और बरार अधिनियम संख्या ग्ट/1938(3) के संबंध में अवधारित किया है कि "ऐसे बहुत कम विषय हैं जिन पर अन्य न्यायालयों के निर्णयों को संघीय और प्रांतीय शक्तियों की तुलना में अधिक सावधानी से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम विश्लेषण में निर्णय संविधान के उन शब्दों पर निर्भर होना चाहिए जिनकी व्याख्या न्यायालय कर रहा है; और चूंकि दो संविधान एक जैसे नहीं होते, इसलिए यह मान लेना अत्यंत असुरक्षित है कि उनमें से किसी एक पर लिए गए निर्णय को बिना किसी मेरिट के दूसरे पर लागू किया जा सकता है।" विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण रूप से यह भी जोड़ा है कि ऐसा तब भी हो सकता है जब दोनों मामलों में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियाँ समान हों, क्योंकि कोई शब्द या वाक्यांश अपने संदर्भ से अलग हो सकता है और तदनुसार अलग-अलग अर्थ रख सकता है (पृष्ठ 38)।

ये टिप्पणियाँ उस बिंदु के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक और उचित हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 49 में प्रयुक्त शब्द अनुच्छेद 194(3) में प्रयुक्त शब्दों से काफी हद तक मिलते-जुलते हैं, फिर भी ऐसे स्पष्ट बिंदु हैं जिन पर हमारे संविधान के प्रासंगिक प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रावधानों से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 का संदर्भ लीजिए। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, अनुच्छेद 32 भारत के नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस न्यायालय में जाने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इस प्रावधान के साथ-साथ अनुच्छेद 226 में निहित प्रावधानों का अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग के निर्माण के प्रभाव की हम पहले ही जांच कर चुके हैं, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान

हों जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सुरक्षित कुछ अधिकारों को शामिल कर सकते हैं।

अनुच्छेद 32 का ऑस्ट्रेलियाई संविधान में कोई प्रतिरूप नहीं है। इसी तरह, हमारे अनुच्छेद 211 के अनुरूप ऑस्ट्रेलियाई संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और इन विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति दो संबंधित प्रावधानों, अर्थात् ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 49 और

हमारा अनुच्छेद 194(3) में प्रयोग किए गए समान शब्दों के अर्थ में पर्याप्त अंतर लाने में योगदान देती है। इसके अतिरिक्त, जिस घोषणा का उल्लेख धारा 49 में किया गया है, वह आवश्यक रूप से उसी परिसीमा के समान नहीं हो सकती है जो अनुच्छेद 194(3) के पहले भाग के अंतर्गत भारतीय विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने पर कानून को नियंत्रित करेगी। हमारे संविधान के प्रासंगिक और भौतिक प्रावधानों की ये विशिष्ट विशेषताएं, मुख्य न्यायाधीश ग्वायेर द्वारा वर्ष 1938 में कही गई सावधानी और चेतावनी को ध्यान में रखना आवश्यक बनाती है। इसलिए, हमारे विचार में रिवर्स के मामले में विशेषाधिकारों के प्रश्न पर विचार करते समय मुख्य न्यायाधीश डिवसन द्वारा की गई टिप्पणियों पर बहुत अधिक अवलम्ब लेना सुरक्षित या उचित नहीं होगा।

हालांकि, इस विषय के समापन से पूर्व, हम प्रसंगवश यह बता सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड पार्कर द्वारा हंट के मामले के सम्बन्ध में की गई हाल की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि उच्चतम अभिलेखीय अदालत द्वारा अवमानना के लिए दण्ड के संबंध में भी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दायर याचिका पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय उक्त अवमानना की वैधता पर विचार करने के लिए सक्षम होगा, भले ही दण्ड का वारंट सामान्य या अव्यक्त हो। केनेथ डगलस हंट द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में, जिन्हें न्यायमूर्ति वीनपैरी द्वारा अवमानना के लिए दण्डित किया गया था, मुख्य न्यायाधीश पार्कर ने टिप्पणी की कि: "यह हो सकता है कि सही दृष्टिकोण यह है और मुझे लगता है कि उक्त मामले इसका समर्थन करते हैं, कि हालांकि इस न्यायालय के पास हमेशा दण्ड की वैधता की जांच करने की शक्ति होती है, लेकिन यह ये नहीं पूछेगा कि शक्ति का उचित रूप से प्रयोग किया गया है या नहीं।" हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके समक्ष प्रस्तुत मामले में वे पूरी तरह से संतुष्ट थे कि आवेदन को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। ये टिप्पणियां यह दिखाती हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, वेस्टमिंस्टर की एक अदालत के पास दण्ड की वैधता की जांच करने का अधिकार है, भले ही दण्ड का आदेश किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो। यदि यह सही स्थिति है, तो यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि वेस्टमिंस्टर की अदालतें आज हाउस ऑफ कॉमन्स को यह दावा करने का अधिकार देंगी कि उनके सामान्य वारंट उनके द्वारा जांचे नहीं जा सकते। फिर भी, आइए हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया प्रासंगिक अधिकार या तो इस आधार पर आधारित है कि संसद के उच्च न्यायालय के एक भाग के रूप में, हाउस ऑफ कॉमन्स अभिलेख का एक उच्च न्यायालय माना है और इस तरह, अवमानना के लिए इसके द्वारा जारी किए गए दण्ड के सामान्य वारंट को वेस्टमिंस्टर हॉल में अदालतों द्वारा निर्णायक माना जाता है, या समय के साथ इस तरह के सामान्य वारंट के लिए निर्णायक चरित्र का दावा करने का अधिकार विशेषाधिकार का एक आकस्मिक और अभिन्न अंग बन गया। जो प्रश्न तुरंत उठता है वह यह है: कि क्या यह अधिकार अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाही में सदन को प्रदान किया गया माना जा सकता है?

सबसे पहले हम हाउस ऑफ कॉमन्स की सुपीरियर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में स्थिति से संबंधित आधार को लें। क्या सदन अनुच्छेद 194(3) द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी कानूनी कल्पना के आधार पर ऐसी स्थिति का दावा कर सकता है? हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर हां में नहीं हो सकता। इस मामले में पिछला विधायी इतिहास इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि हमारे राज्य विधानसभाएं 1935 के संविधान अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम अभिलेखीय अदालत थीं। उक्त अधिनियम की धारा 28, जो संघीय विधायिका के विशेषाधिकारों पर प्रावधान करती है, इस बिंदु पर प्रासंगिक है। धारा 28(1) वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अनुरूप है। धारा 28(2) यह प्रावधान करती है कि अन्य मामलों में, चौबर्स के सदस्यों के विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जिन्हें समय-समय पर संघीय विधायिका के अधिनियम द्वारा परिभाषित किया जा सकता है और जब तक परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक वे ऐसे होंगे, जैसे संघ की स्थापना से ठीक पहले भारतीय विधायिका के सदस्यों को प्राप्त थे। यह विवादित नहीं है कि भारतीय विधानसभा के सदस्य 1935 के अधिनियम से पहले उच्च न्यायालय के सदस्य होने का दर्जा नहीं ले सकते थे। धारा 28(3) निर्धारित करती है कि किसी भी मौजूदा भारतीय अधिनियम में कुछ भी नहीं, और इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी भी मैम्बर या एक

साथ बैठे दोनों चैंबरों या विधानसभा की किसी समिति या अधिकारी को न्यायालय का दर्जा देने, या नियमों या स्थायी आदेशों का उल्लंघन करने वाले या अन्यथा अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को हटाने या बहिष्कृत करने की शक्ति के अतिरिक्त कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए संघीय विधानसभा को सशक्त बनाने के रूप में नहीं समझा जाएगा। धारा 28(4) हमारे उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक है। यह प्रदान करता है कि संघीय विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि पर उन व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान किया जा सकता है जो समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए विधिवत अनुरोध किए जाने पर चौबर की समिति के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये प्रावधान स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि भारतीय विधानसभा अपने विधानसभा कक्षा की चारदीवारी के बाहर की गई अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का दावा नहीं कर सकता था। इसी अधिनियम की धारा 71 प्रांतीय विधानमंडलों से संबंधित है और इसके खंड (2), (3) और (4) में समान प्रावधान हैं।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (10 और 11 जियो. VI, सी. 20) पारित होने के बाद, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में विभिन्न संशोधन आदेशों द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा इस स्थिति को बदल दिया गया। तृतीय संशोधन आदेश, 1948 सहित संशोधन आदेशों का परिणाम यह हुआ कि उक्त अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (3) और (4) को हटा दिया गया और उप-धारा (2) में संशोधन किया गया। इस संशोधन का प्रभाव यह था कि संघीय विधानसभा के सदस्य तब तक संघीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित किए जाने तक संघ की स्थापना से ठीक पहले अस्तित्व में रहे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का दावा कर सकते थे। हालाँकि, यह उल्लेखनीय है कि धारा 71 की संगत उप-धारा (3) और (4) को बरकरार रखा गया। यह प्रश्न कि क्या उप-धारा (3) और (4) को हटाने और धारा 28 के उप-धारा (2) के संशोधन का परिणाम संघीय विधानसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के समान दर्जा प्रदान करना था, वर्तमान संदर्भ में हमारे निर्णय की मांग नहीं करता है। प्रथम दृष्टया, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संघीय विधानसभा के सदस्यों को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार प्रदान करने से संघीय विधानसभा सभी उद्देश्यों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं बन सकता है; लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें वर्तमान कार्यवाही में चर्चा करने और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्रासंगिक समय पर प्रांतीय विधानमंडलों के संबंध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी कि जिस समय संविधान पारित किया गया था, उस समय प्रांतीय विधानसभा हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति का दावा कर सकते थे और इस तरह एक उच्च न्यायालय के अभिलेख का दावा कर सकते थे। प्रांतीय विधानमंडलों के संबंध में अनुच्छेद 194(3) की यही संवैधानिक पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि के आलोक में विचार करने पर, यह तर्क स्वीकार करना कठिन है कि अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध में निहित प्रावधानों का परिणाम भारत में राज्य विधानमंडलों को एक उच्च न्यायालय का दर्जा प्रदान करना था।

इस संबंध में, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को जो उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया था, वह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। यह अंग्रेजी इतिहास का एक तथ्य है कि संसद अपने प्रारंभिक कार्यकाल में न्यायिक कार्यों का निर्वहन कर रही थी। यह इंग्लैंड के ऐतिहासिक और संवैधानिक इतिहास दोनों का एक तथ्य है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यह आज भी संवैधानिक इतिहास का एक तथ्य है कि दोनों सदनों के पास महाभियोग और अभियोग की शक्तियाँ हैं। यह हमारा स्पष्ट विचार है, कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को भारत में किसी भी कानूनी कल्पना द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। उचित विधायी प्रावधान कभी-कभी कानूनी कल्पनाएँ पेश करते हैं, लेकिन ऐसी कल्पनाएँ पेश करने की कानून की शक्ति की एक सीमा होती है। कानून, कानूनी अधिकारों और दायित्वों के बारे में और उस संबंध में किए गए प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के बारे में कल्पनाएँ पेश कर सकता है; लेकिन कानूनी कल्पना शायद ही एक देश से दूसरे देश में ऐतिहासिक तथ्यों को पेश कर सके।

इसके अतिरिक्त, हाउस ऑफ कॉमन्स को दिए गए उच्चतम अभिलेखीय अदालत के दर्जे के संबंध में, अंग्रेजी इतिहास का एक और हिस्सा है जिसे स्मरण रखना आवश्यक

है। हाउस ऑफ कॉमन्स को अपने अस्तित्व के लिए राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के खिलाफ लड़ना पड़ा, और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा न्यायपालिका को राजा की निर्मिति माना जाता था और न्यायपालिका स्पष्ट रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधीन थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स की मुख्य विरोधी थी। इससे एक ओर हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरी ओर राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच भीषण संघर्ष हुआ। भारत में ऐसी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है और जिस आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को नकारने के लिए संघर्ष किया, उसका कोई ऐतिहासिक औचित्य नहीं हो सकता; यह मामले का एक और पहलू है जो इस प्रश्न पर विचार करने में प्रासंगिक है कि क्या वर्तमान मामले में सदन एक उच्च अभिलेख न्यायालय का दर्जा दावा कर सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन के पास अपने चैम्बर के बाहर की गई अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, और इस दृष्टिकोण से वह अभिलेख न्यायालय के पास मौजूद अधिकारों में से एक का दावा कर सकता है। जोविट के अंग्रेजी कानून के शब्दकोष के अनुसार, अभिलेखीय न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसके कृत्यों और न्यायिक कार्यवाहियों को सतत स्मृति और गवाही के लिए नामांकित किया जाता है, और जिसे अपने अधिकार की अवमानना के लिए जुर्माना और कारावास का अधिकार है। सदन में और वास्तव में भारत में सभी विधानसभाओं ने कभी भी कोई न्यायिक कार्य नहीं किया और उनकी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि इस दावे का समर्थन नहीं करती है कि उन्हें किसी भी अर्थ में अभिलेख न्यायालय माना जा सकता है। यदि ऐसा है, तो वह आधार जिसके आधार पर अंग्रेजी न्यायालय हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंट को इस आधार पर मानने के लिए सहमत हुए थे कि यह एक उच्चतम अभिलेखीय अदालत द्वारा जारी किया गया वारंट था, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है, और इसलिए, यह तर्क देना अनुचित होगा कि सामान्य वारंट के लिए निर्णायक चरित्र का दावा करने की प्रासंगिक शक्ति, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स, समझौते के द्वारा स्वीकृत माना जाता है जो कि हाउस में निहित है। मामले के इस दृष्टिकोण पर, हाउस द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

हालांकि, यह मानते हुए कि सदन द्वारा दावा किया गया अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है, विचार करने का सवाल यह होगा कि क्या ऐसा अधिकार अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा हाउस को प्रदान किया गया है। इस वैकल्पिक परिकल्पना पर, यह विचार करना आवश्यक है कि विशेषाधिकार का यह हिस्सा हमारे संविधान के भौतिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। हम पहले ही अनुच्छेद 32 और 226 का उल्लेख कर चुके हैं। अनुच्छेद 32 का सन्दर्भ लें क्योंकि यह भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार के महत्व को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का विधानसभा या कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वे इस न्यायालय में जा सकते हैं। अब, अनुच्छेद 32 किसी भी अतिक्रमण के संबंध में कोई अपवाद नहीं करता है, और यह तर्क देना अतार्किक प्रतीत होगा कि भले ही सदन द्वारा दावा किया गया अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, पीड़ित नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में सफलतापूर्वक नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 32 द्वारा नागरिकों को दिए गए पूर्ण संवैधानिक अधिकार के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है और संविधान द्वारा इस देश के विधानमंडलों में निहित किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार के संदर्भ में कोई अपवाद बनाने का इरादा नहीं है।

जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है कि हम उन मामलों में सभी मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता के संबंध में सामान्य चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं जहां इस देश के किसी भी व्यक्तिगत नागरिक के खिलाफ विधायी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, और हम इस मामले को इस आधार पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 19(1)(ए) लागू नहीं होता है और अनुच्छेद 21 लागू होता है। यदि कोई अवसर आता है, तो यह विचार करना आवश्यक हो सकता है कि अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग से अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन, फिलहाल, हम अनुच्छेद 20 पर विचार कर सकते हैं। यदि अनुच्छेद 21 लागू होता है, तो अनुच्छेद 20 संभवतः लागू हो सकता है, और सवाल उठ सकता है, अगर कोई नागरिक शिकायत करता है कि उसके मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लंघन किया गया है तो

क्या वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में जा सकता है या नहीं? जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे बनाने के उद्देश्य से, अनुच्छेद 21 की प्रयोज्यता ही पर्याप्त होगी। यदि कोई नागरिक इस न्यायालय में यह शिकायत करता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो स्पष्ट रूप से यह इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह उक्त तर्क के गुण-दोष की जांच करे, और इससे अनिवार्य रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया गया है। वास्तव में, इस प्रश्न पर इस न्यायालय ने पंडित शर्मा के मामले में विचार किया था। यह सब है कि उत्तर विधायिका के पक्ष में दिया गया था; लेकिन वर्तमान चर्चा के उद्देश्य के लिए यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है। यदि किसी दिए गए मामले में, नागरिक द्वारा लगाया गया आरोप यह है कि उसे कानून के अनुसार नहीं, बल्कि मनमाने या दुर्भावनापूर्ण कारणों से उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, तो इस न्यायालय को उक्त तर्क की वैधता की जांच करनी होगी, और ऐसे मामले में यह कहना कोई उत्तर नहीं होगा कि नागरिक के खिलाफ जारी वारंट एक सामान्य वारंट है और एक सामान्य वारंट को आगे की सभी न्यायिक जांच और जांच को रोक देना चाहिए। इसलिए, हमारी राय में, अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग की व्याख्या पर अनुच्छेद 32 द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक संवैधानिक अधिकार का प्रभाव इस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है कि सदन द्वारा किसी शक्ति या विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है, हालांकि यह अनुच्छेद 21 के साथ असंगत हो सकता है। इस संबंध में, यह याद रखना प्रासंगिक हो सकता है कि सदन को अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए जो नियम बनाने हैं, उन्हें अनुच्छेद 208(1) के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए।

पुनः, अनुच्छेद 211 का मामला लें और देखें कि इसका सदन के दावे पर क्या प्रभाव होगा, जिस पर हम विचार कर रहे हैं। यदि सदन का दावा बरकरार रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि सदन किसी न्यायाधीश के खिलाफ सामान्य वारंट जारी कर सकता है, और ऐसे वारंट की वैधता के संबंध में कोई न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है। यह वास्तव में अजीब होगा कि न्यायपालिका को हमारे विधानमंडलों के विधायी कृत्यों की वैधता पर विचार करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए, लेकिन नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाले विधानमंडलों की कार्यवाही की वैधता की जांच करने से रोका जाना चाहिए। यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि सामान्य वारंट को निर्णायक माना जाना चाहिए, तो, जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, न्यायिक स्वतंत्रता की मूल अवधारणा बहुत गंभीर खतरे में पड़ जाएगी; और इसलिए इस विशेष शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 194(3) की व्याख्या पर अनुच्छेद 211 का प्रभाव फिर से सदन द्वारा उठाए गए विवाद के खिलाफ निर्णायक रूप से है।

यदि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय का अधिकार किसी अपवाद के अधीन नहीं है, तो यह तर्क देना निरर्थक होगा कि कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी उच्च न्यायालयों या इस न्यायालय से अपने क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकता है। उस संबंध में न्यायिक शक्ति का अस्तित्व अनिवार्यतः और अपरिहार्य रूप से नागरिक में उस संबंध में न्यायालय में जाने के अधिकार के अस्तित्व को दर्शाता है; अन्यथा उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति वस्तुतः निरर्थक हो जाएगी। यह न भूलें कि उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को प्रदान की गई न्यायिक शक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, और इसलिए, उक्त न्यायिक शक्ति के अस्तित्व में ही नागरिक का उचित मामले में उक्त शक्ति के समक्ष अपील करने का अधिकार अनिवार्य रूप से शामिल है।

संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770 के संबंध में, प्रिवी काउंसिल से यह विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770 के विपरीत कार्य कर रहा होगा, यदि वह संसद में उसके द्वारा दिए गए भाषण या कार्यवाही के संबंध में संसद सदस्य के विरुद्ध रिट जारी करने को अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन मानता है तो उक्त प्रश्न ने कुछ संदेह को जन्म दिया था, और इसलिए, इसे प्रिवी काउंसिल को उसकी राय के लिए भेजा गया था। प्रिवी काउंसिल द्वारा व्यक्त की गई राय संसद के पक्ष में थी। उक्त सीमित प्रश्न तक अपने उत्तर को सीमित रखते हुए, प्रिवी काउंसिल ने यह कहते हुए सावधानी बरती कि "वे कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि परिचयात्मक पैराग्राफ में संदर्भित कार्यवाही संसद में कार्यवाही थी या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर उनके समक्ष

चर्चा नहीं हुई, न ही इस प्रश्न पर कि क्या किसी भी परिस्थिति में केवल रिट जारी करना विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।" इस मार्ग को अपनाते हुए", वे महारानी के विषयों के अपने गलत कामों के लिए उनके न्यायालयों का सहारा लेने के अविभाज्य अधिकार के प्रति सचेत रहे हैं और किसी भी ऐसे मामले की सुनवाई में बाधा नहीं डालेंगे जिसमें वादी ने सहत मांगी हो।" विस्काउंट सिमंड्स ने जिस अविभाज्य अधिकार का उल्लेख किया है, वह अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के प्रावधानों में निहित है, और इसका अस्तित्व सदन द्वारा दावा किए गए अधिकार के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है कि एक सामान्य वारंट को सभी न्यायालयों में निर्णायक माना जाना चाहिए; यह सदन द्वारा किए गए दावे के साथ भी समान रूप से असंगत होगा कि केशव सिंह ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अवमानना की है।

इस संबंध में, 1704 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित एक प्रस्ताव का उल्लेख करना रोचक होगा। इस प्रस्ताव द्वारा, यह घोषित किया गया था कि निर्वाचकों को कानून की सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाने से रोकना, जहाँ उन्हें मतदान के अपने अधिकार से वंचित किया जाता है, और अधिवक्ताओं, सॉलिसिटों, परामर्शदाताओं और विधि के सार्जेंट को ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने और दलील देने से डराना, उनके ऐसा करने को हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार का उल्लंघन मानकर, कानून को नियंत्रित करने, न्याय के मार्ग में बाधा डालने और अंग्रेजों की संपत्ति को हाउस ऑफ कॉमन्स के मनमाने वोटों के अधीन करने की शक्ति का स्पष्ट रूप से प्रयोग करना है। यह उसी वर्ष हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित प्रस्ताव के उत्तर में था, जिसमें संकेत दिया गया था कि सदन प्रस्ताव द्वारा उल्लिखित मामलों में उचित सहत के लिए अदालत में जाने वाले किसी भी व्यक्ति के आचरण को सदन अपनी अवमानना के रूप में मानेगा। ये प्रस्ताव और प्रति-संकल्प केवल उस भयंकर संघर्ष को दर्शाते हैं जो उन अशांत दिनों के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच चल रहा था; लेकिन इस विवाद का रोचक हिस्सा यह है कि यदि सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की हाउस ऑफ कॉमन्स की क्षमता के संबंध में कोई प्रश्न हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास गया होता, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निरसंदेह ऐसे दावे को खारिज कर दिया होता, और यही हाउस ऑफ कॉमन्स की मूल आशंका थी जो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को मान्यता देने से इनकार करने के लिए जिम्मेदार थी, जो अंतिम विश्लेषण में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधीनस्थ थे।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 30 सभी अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में, किसी न्यायाधिकरण या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष, और किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष, जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता किसी कानून द्वारा या उसके अधीन वर्तमान में लागू है, प्रयोग करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है। बार काउंसिल अधिनियम की धारा 14 एक समान अधिकार को मान्यता देती है। यदि किसी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, तो अधिवक्ता नागरिकों की सहायता करने का वैधानिक अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में सहायता करता है। इस बात पर जोर देना शायद ही आवश्यक हो कि नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में कानूनी पेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसलिए, जिस तरह अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उनके समक्ष लाए गए मामलों में विचार के लिए न्यायपालिका के अधिकार को अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों के अधीन नहीं किया जा सकता है, उसी तरह न्यायपालिका में जाने के नागरिकों के अधिकार और उस प्रक्रिया में सहायता करने के अधिवक्ताओं के अधिकार को अनुच्छेद 194(3) द्वारा अनियंत्रित रहना चाहिए। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने और इस देश में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक एकीकृत योजना है। इसलिए, हमारा निष्कर्ष यह है कि वह विशेष अधिकार, जिसके बारे में सदन अपनी शक्ति या विशेषाधिकार का अभिन्न अंग होने का दावा करता है, संविधान के भौतिक प्रावधानों के साथ असंगत है और इसे अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत शामिल नहीं माना जा सकता है।

इस संबंध में, हमें यह जोड़ना चाहिए कि श्रीमान सीरवाई द्वारा की गई

शिकायत में कोई सार नहीं है कि केशव सिंह ने लखनऊ पीठ के समक्ष उनके द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में सदन को पक्षकार बनाकर अवैध रूप से काम किया है। हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि केशव सिंह सदन में अनुचित रूप से शामिल हुए थे, क्योंकि उनके लिए सदन में शामिल होने का विकल्प इस आधार पर था कि उनका दण्ड सदन द्वारा पारित आदेश पर आधारित थी, और इस अर्थ में सदन उनके दण्ड के लिए जिम्मेदार था, और उस पर नियंत्रण रखता था (सन्दर्भ: द किंग बनाम द अल ऑफ क्रेवे, एक्स पार्ट सेकगोम और द किंग बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, एक्स पार्ट ओशब्रायन ।) इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि केशव सिंह अपनी याचिका में सदन में शामिल हुए, न्यायाधीशों, अधिवक्तागणों और पक्षकारों के विरुद्ध उनकी कथित अवमानना के लिए कार्रवाई करने की सदन की शक्ति के मुख्य प्रश्न को निर्धारित करने में कोई प्रासंगिकता या भौतिकता नहीं हो सकती है।

जैसा कि हमने इस राय के प्रारम्भ में संकेत दिया है, मामले का सार अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग का निर्माण है, और उस सहायता के प्रकाश में जिसे हमें संविधान के अन्य प्रासंगिक और भौतिक प्रावधानों से प्राप्त करना चाहिए, यह मानना आवश्यक है कि सदन द्वारा दावा की गई वह विशेष शक्ति कि उसके सामान्य वारंट को निर्णायक माना जाना चाहिए, अनुच्छेद 194(3) के उत्तरार्द्ध भाग की विषय-वस्तु नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में, हम संयोगवश यह देख सकते हैं कि यह कुछ हद तक संदिग्ध है कि सदन द्वारा दावा किया गया सामान्य अवाक वारंट जारी करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 554(2)(बी) और धारा 555 के अनुरूप है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड में अवमानना के लिए दण्ड के संबंध में सामान्य वारंट उच्चतर अभिलेख न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं, और इस बिंदु पर पूरा विवाद है, इसलिए, इस सिद्धांत पर आधारित है कि उच्चतर अभिलेख न्यायालयों के संबंध में मान्यता प्राप्त सामान्य वारंट जारी करने का अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया जाना चाहिए, क्योंकि संसद के उच्च न्यायालय के एक भाग के रूप में यह स्वयं एक उच्चतर अभिलेखीय न्यायालय है।

इस विषय के समापन से पूर्व, दो सामान्य विचार हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। श्रीमान सीरवर्ड ने हमारे सामने जोर दिया है कि अवमानना के संबंध में निर्णायक सामान्य वारंट जारी करने का सदन द्वारा दावा किया गया अधिकार स्वयं सदन के प्रभावी कामकाज के लिए एक आवश्यक अधिकार है, और उन्होंने हमें इस मामले को इसी दृष्टिकोण से देखने को कहा है। यह सच है कि यह अधिकार इंग्लैंड में अदालतों द्वारा समझौते या सम्मेलन या शिष्टाचार के विचारों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतीत होता है; लेकिन हमें लगता है कि यह कहना पूरी तरह सटीक नहीं है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक विधायिका इस तरह की शक्ति से लैस है। अमेरिकी विधायिकाओं का ही मामला लें। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 1, खंड 5 अमेरिकी विधायिका को ऐसी कोई शक्ति बिल्कुल भी नहीं देता है। यह प्रदान करता है कि प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चुनाव, निष्कासन और योग्यता का निर्णायक होगा, लेकिन एक छोटी संख्या दिन-प्रतिदिन सदन को स्थगित कर सकती है, और अनुपस्थित सदस्यों की उपस्थिति को बाध्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है, इस तरह से, और ऐसे दंड के अंतर्गत जो प्रत्येक सदन प्रदान कर सकता है। प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के नियम निर्धारित कर सकता है, अपने सदस्यों को अव्यवस्थित व्यवहार के लिए दंडित कर सकता है, और दो-तिहाई की सहमति से, किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है। किसी नागरिक द्वारा विधान कक्षा की चारदीवारी के बाहर की गयी अवमानना, जो सदन का सदस्य नहीं है, अमेरिकी विधानसभा के क्षेत्राधिकार से बाहर प्रतीत होता है। जैसा कि विलिस ने अवधारित किया है, अवमानना के लिए दंड स्पष्ट रूप से एक न्यायिक कार्य है; फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कांग्रेस अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है क्योंकि यह अपने स्वयं के सदस्यों के बीच व्यवस्था बनाए रखने, उनकी उपस्थिति को बाध्य करने, दूसरों द्वारा हमलों या गड़बड़ी से बचाने (निंदा और मानहानि को छोड़कर), चुनाव मामलों और महाभियोग के आरोपों का निर्धारण करने, और विधायी कार्य की सहायता में अन्य विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। किसी ने कभी यह सुझाव नहीं दिया है कि अमेरिकी कांग्रेस प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसे हमारे समक्ष सदन द्वारा दावा की गई विशेष शक्ति से परिपूर्ण नहीं किया गया है।

अपने तर्क के दौरान, श्री सीरवर्ड ने इस तथ्य पर काफी जोर दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में, उच्च न्यायालय को अंतरिम जमानत देने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि इंग्लैंड में यह मान्यता है कि अवमानना के आधार पर हाउस

ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित दण्ड के आदेशों के विरुद्ध प्रारम्भ की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के संबंध में, न्यायालयों द्वारा जमानत नहीं दी जाती है। स्वाभाविक रूप से, पिछली शताब्दी और उससे भी अधिक समय से ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाहियों में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा विधि के अनुसार रिटर्न दाखिल किया जाता है, परन्तु "सामान्य नियम यह है कि जो पक्षकार अवमानना के लिए दण्डित है, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।" लेकिन इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि भारत में भी इस मामले में स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। यदि अनुच्छेद 226 न्यायालय को दण्ड के आदेश की वैधता पर विचार करने का अधिकार देता है, भले ही दण्ड का आदेश सदन द्वारा दिया गया हो, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि न्यायालय को ऐसी कार्यवाही में अंतरिम आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है? जैसा कि इस न्यायालय ने उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा और अन्य के मामले में अवधारित किया है, अंतरिम राहत केवल उस मुख्य राहत की सहायता के रूप में तथा उसके सहायक के रूप में दी जा सकती है जो किसी वाद या कार्यवाही में पक्षकार को उसके अधिकारों के अंतिम निर्धारण पर उपलब्ध हो सकती है। वास्तव में, जैसा कि मैक्सवेल ने अवधारित किया है, जब कोई अधिनियम अधिकारिता प्रदान करता है, तो वह निहित रूप से ऐसे सभी कार्य करने, या ऐसे साधनों को नियोजित करने की शक्ति भी प्रदान करता है, जो उसके निष्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों और लाला जयराम दास एवं अन्य बनाम किंग एम्परर मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर आधारित तर्क कोई सहायता नहीं करता है।

हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तथा ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग के औचित्य या तर्कसंगतता से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा, सुपीरियर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के मामले में, यह विचार करना न्यायालय का कार्य है कि कोई मामला उसके क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। सीमित क्षेत्राधिकार वाली न्यायालय के विपरीत, उच्चतर न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के विषय में स्वयं ही प्रश्न तय करने का हकदार है। हेल्सबरी कहते हैं, "प्रथम दृष्टया कोई भी मामला उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं माना जाता है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से न दर्शाया जाए, जबकि कोई भी मामला अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं माना जाता है, जब तक कि कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट रूप से न दर्शाया जाए कि विशेष मामला विशेष अदालत के संज्ञान में है।" इसलिए, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते कि अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत आदेश निरर्थक और अमान्य है। इसके अलावा, आदेश की वैधता का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है कि आदेश पारित करते समय न्यायाधीशों ने सदन की अवमानना की है या नहीं।

इस मामले का एक और पहलू है जिसका हम संयोगवश उल्लेख कर सकते हैं। हम पूर्व में ही देख चुके हैं कि वर्तमान मामले में, जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 19 मार्च, 1964 को दोपहर 2 बजे लखनऊ पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, तो दोनों पक्ष अपने-अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से उपस्थित हुए और इस बात पर सहमत हुए कि आवेदन पर उसी दिन दोपहर 3 बजे सुनवाई की जानी चाहिए, और फिर भी वह सदन जिसे रिट याचिका में पक्षकार बनाया गया था और अन्य प्रत्यर्थी जिनके लिए श्री कपूर पहले चरण में उपस्थित हुए थे, उस समय अनुपस्थित थे। इसीलिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिका पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया जाए तथा याचिकाकर्ता को पहले से उल्लिखित शर्तों व नियमों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए; तथा जमानत का यह बाद का आदेश ही बाद के घटनाक्रमों का कारण बना। दूसरे शब्दों में, लखनऊ पीठ के न्यायाधीशों के विरुद्ध वारंट जारी करने की शीघ्रता वाली कार्यवाई करने से पूर्व सदन ने उस समरूप प्रथा का पालन नहीं किया जिसका पालन हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक शताब्दी से भी अधिक समय से किया है, तथा उसने अपने अधिवक्ता को न तो रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया, न ही ऐसा करने के लिए समय मांगा, तथा न ही न्यायालय से अनुरोध किया कि वह रिटर्न दाखिल होने तक अपने हाथ रोके रखे। यह विवादित नहीं है कि जब भी हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित दण्डादेशों को इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर की अदालतों के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो सदन अनिवार्यतः एक रिटर्न देता है और यदि उसके द्वारा जारी किया गया वारंट सामान्य और अव्यक्त है, तो रिटर्न में ऐसा कहा जाता है और वारंट प्रस्तुत किया

जाता है। यदि वर्तमान कार्यवाही में यह तरीका अपनाया गया होता, तो यह कहा जा सकता था कि सदन ने अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए उस स्वरूप का अनुपालन किया है, जिसका परम्परागत रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स ने पिछली शताब्दी और उससे भी अधिक समय से इंग्लैंड में सदैव पालन किया है; लेकिन ऐसा नहीं किया गया; और जैसे ही सदन को पता चला कि जमानत देने का आदेश पारित किया गया है, तो उसने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि क्या न्यायाधीश स्वयं अवमानना में नहीं थे। इन संकीर्ण तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना संभव होगा कि न्यायाधीशों द्वारा अवमानना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस तथ्य के मद्देनजर कि श्री कपूर सभी प्रत्यर्थागण की ओर से अपराह्न 2 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि मामले पर अपराह्न 3 बजे सुनवाई की जानी चाहिए, यह उनका कर्तव्य था कि वे अपराह्न 3 बजे उपस्थित होते और सदन की ओर से या तो रिटर्न दाखिल करते या ऐसा करने के लिए समय मांगते। यदि सदन ने श्री कपूर को यह कदम उठाने का निर्देश नहीं दिया था और न्यायालय को इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री कपूर क्यों उपस्थित नहीं हुए, तो याचिका पर नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए न्यायालय को दोषी ठहराना उचित नहीं है। इन कार्यवाहियों में हमारे लिए यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि श्री कपूर और सदन के बीच क्या हुआ और श्री कपूर सदन और अन्य प्रत्यर्थागण का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपराह्न 3 बजे क्यों उपस्थित नहीं हुए। श्री कपूर का अपराह्न 3 बजे न्यायालय में उपस्थित न होना, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक दुर्भाग्यपूर्ण तत्व का समावेश है तथा यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। एक तथ्य स्पष्ट है, और वह यह है कि जिस समय न्यायालय ने नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया, उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जिस वारंट के तहत याचिकाकर्ता को सजा सुनाई गई थी, वह एक सामान्य वारंट था और न्यायालय को यह सुझाव नहीं दिया गया था कि ऐसे वारंट के मामले में न्यायालय के पास जमानत का कोई आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। सदन के मामले पर विचार करने में इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करके अवमानना की है।

लेकिन हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम इस मामले के इस संकीर्ण दृष्टिकोण पर अपने उत्तरों को आधारित करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रश्न 3 और 5 काफी व्यापक हैं और उन्हें संगत रूप से व्यापक आधार पर उत्तर की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इस व्यापक पहलू से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारे समक्ष पूर्ण रूप से बहस की जा चुकी है, तथा यह स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे दें तथा किसी भी प्रासंगिक पहलू को इस आधार पर अपने विचार से बाहर न रखें कि वर्तमान कार्यवाही में अब तक घटित विशेष तथ्यों के आधार पर ये पहलू पूर्णतः उत्पन्न नहीं होंगे।

निष्कर्षतः, हम यह जोड़ना चाहेंगे कि हमारी चर्चा के दौरान हमने लगातार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मुख्य बिंदु जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह सदन का यह दावा करने का अधिकार है कि सदन की चारदीवारी के बाहर किसी नागरिक द्वारा, जो सदन का सदस्य नहीं है, कथित रूप से की गई अवमानना के संबंध में उसके द्वारा जारी किया गया सामान्य वारंट निर्णायक है, क्योंकि इसी दावे के आधार पर सदन ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि न्यायाधीशों, अधिवक्ता और पक्षकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने आवरण के संदर्भ में अवमानना की है। चूंकि हमने माना है कि वर्तमान मामले में क्रमशः न्यायाधीशों, या अधिवक्ता, या पक्षकार द्वारा कोई अवमानना नहीं की गई थी, यह इस प्रकार है कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए स्वतंत्र था, और वास्तव में यह उसका कर्तव्य था, कि वह दो न्यायाधीशों और अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष दायर याचिकाओं पर विचार करे, और सदन द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेशों के आगे निष्पादन पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश पारित करना उसके क्षेत्राधिकार में था।

इस विषय के समापन होने से पूर्व, हम अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के प्रयोग से संबंधित प्रश्न के एक पहलू का उल्लेख करना चाहेंगे। जहाँ तक न्यायालयों का प्रश्न है, न्यायाधीश हमेशा लॉर्ड एटकिन द्वारा आंद्रे पॉल बनाम अटॉर्नी-जनरल ऑफ़ त्रिनिदाद मामले में उन्हें दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हैं। लॉर्ड एटकिन ने कहा था, "न्याय कोई एकांत

सद्गुण नहीं है, उसे सामान्य लोगों की जांच और सम्मानजनक टिप्पणियों का सामना करने की अनुमति दी जानी चाहिए।" हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका प्रयोग हमेशा सतर्कतापूर्वक, बुद्धिमत्ता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इस शक्ति का क्रोध या आवेग में बार-बार या अविवेकपूर्ण प्रयोग न्यायालय की गरिमा या स्थिति को बनाए रखने में सहायता नहीं करेगा, बल्कि कभी-कभी इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश कभी नहीं भूलते कि उनके पद की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका उनके निर्णयों की गुणवत्ता, उनके दृष्टिकोण की निडरता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता और उनके न्यायिक आचरण में उनके द्वारा बरता जाने वाला संयम, गरिमा और शिष्टाचार के द्वारा आम जनता से अर्जित सम्मान है। हम यह सोचते हैं कि न्यायपालिका के विषय में जो सत्य है, विधानमंडलों के विषय में भी उतना ही सत्य है।

इस प्रकार हमारे समक्ष प्रस्तुत सभी प्रासंगिक बिंदुओं पर चर्चा करने तथा उन पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने के पश्चात, अब हम राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए पांच प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में हैं। हमारे उत्तर निम्नवत हैं:-

(1) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एन.यू. बेग और जी.डी. सहगल शामिल हैं, केशव सिंह की याचिका को स्वीकार करने और उस पर विचार करने के लिए सक्षम थी, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उसकी अवमानना और उसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उस पर अधिरोपित कारावास की सजा की वैधता को चुनौती दी गई थी और केशव सिंह को उनकी उक्त याचिका के निस्तारण तक जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया था।

(2) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, केशव सिंह ने अपनी ओर से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में उक्त याचिका प्रस्तुत करवाकर, अधिवक्ता श्री बी. सोलोमन ने उक्त याचिका प्रस्तुत करके, तथा उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों ने उक्त याचिका पर विचार तथा उस पर कार्यवाही करके तथा उक्त याचिका के निस्तारण तक केशव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की अवमानना नहीं की है।

(3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों और अधिवक्ता श्री बी. सोलोमन को हिरासत में अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने या अपनी अवमानना के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए सक्षम नहीं थी।

(4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों और अधिवक्ता श्री बी. सोलोमन की याचिकाओं को स्वीकार करने और उस पर विचार करने तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और उक्त याचिकाओं के अन्य प्रत्यर्थांगण को उक्त विधान सभा के उपरोक्त निर्देश को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने में सक्षम थी ; तथा

(5) इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, जो कि बहुत ही व्यापक रूप से लिखा गया है, हमें अपने उत्तर की प्रस्तावना में यह टिप्पणी करनी चाहिए कि यह उत्तर ऐसे मामलों तक ही सीमित है, जिनमें अवमानना का आरोप ऐसे नागरिक पर लगाया गया है, जो विधान सभा की चारदीवारी के बाहर सदन का सदस्य नहीं है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जो विधान सभा के किसी आदेश या निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करता है, जिसमें याचिकाकर्ता पर कोई दंड अधिरोपित किया गया है या याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी अवमानना अथवा उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अतिक्रमण के लिए कोई आदेश जारी किया गया है, या जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, वह उक्त विधान सभा की अवमानना नहीं करता है; और उक्त विधान सभा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग और प्रवर्तन में ऐसे न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। इस उत्तर में, हमने सदन के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन का उल्लेख विचारपूर्वक छोड़ दिया

है, जिसमें उन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अतिरिक्त अन्य विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भी शामिल हो सकती हैं, जिनका हम वर्तमान संदर्भ में उल्लेख कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति सरकार, यह मामला संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर हमारे पास आया है। संदर्भ का अवसर उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा, इसके पश्चात विधानसभा के रूप में सन्दर्भित, और उस राज्य के उच्च न्यायालय के बीच उत्पन्न हुआ तीव्र संघर्ष था जो अभी भी अस्तित्व में है। यह विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था जिसे विधानसभा ने अवमानना के लिए जेल में डाल दिया था। विधानसभा ने अवधारित किया कि आदेश देने वाले न्यायाधीशों और संबंधित अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की कार्रवाई अवमानना के समान थी और इस आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ हुई और इसके पश्चात उच्च न्यायालय ने विधानसभा और उसके अधिकारियों को इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में कदम उठाने से रोक दिया कि न्यायाधीशों और अधिवक्ता तथा जिस व्यक्ति की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, की कार्रवाई अवमानना के समान थी।

इस संदर्भ में बहुत बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित हुए और यह स्वाभाविक ही था क्योंकि इसमें शामिल प्रश्न का सार्वजनिक महत्व था। ये पक्षकार दो व्यापक समूहों में विभाजित थे, एक विधानसभा का समर्थन कर रहा था और दूसरा उच्च न्यायालय का।

अब मैं उन वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करूंगा जिनके कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ। सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि केशव सिंह नामक व्यक्ति को फटकार लगाई जाए क्योंकि उसने सभा के एक सदस्य के विरुद्ध एक पर्चा प्रकाशित करके सदन की अवमानना की है। इस मामले में इस प्रस्ताव की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं उठा और हम केवल इस बात से विवक्षित हैं कि इसके बाद क्या हुआ। गोरखपुर निवासी केशव सिंह को बार-बार ऐसा करने के लिए कहने के बावजूद, वे विधानसभा में उपस्थित नहीं हुए, जिसकी बैठक लखनऊ में हुई, तथा उन पर रेलवे यात्रा के लिए आवश्यक किराया देने हेतु धन जुटाने में असमर्थ होने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई गई। इसके बाद उन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट के निष्पादन के लिए विधानसभा के मार्शल की हिरासत में लाया गया और 14 मार्च, 1964 को सदन के बार में पेश किया गया। अध्यक्ष ने उनसे बार-बार उनका नाम पूछा, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वे अध्यक्ष की ओर पीठ करके खड़े रहे और सदन के प्रति अपमान का प्रदर्शन किया और अध्यक्ष के सामने देखने के लिए कहने पर भी नहीं मुड़े। फटकार दिए जाने के बाद अध्यक्ष ने विधानसभा के ध्यान में केशव सिंह द्वारा 11 मार्च, 1964 को लिखा गया एक पत्र लाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे फटकार की सजा का विरोध करते हैं और एक भ्रष्ट व्यक्ति को भ्रष्ट कहने में उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं है, उन्होंने आगे कहा कि उनके पत्र की विषय-वस्तु सही थी और उन पर "नादिरशाही फरमान" (वारंट) जारी करके लोकतंत्र पर क्रूर हमला किया गया था। केशव सिंह ने उस पत्र को लिखने की बात स्वीकार की। इसके बाद विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि "केशव सिंह को सदन की अवमानना करने वाली भाषा में पत्र लिखने और सदन के प्रति उनके दुर्व्यवहार के लिए सात दिन के कारावास की सजा दी जाए।" सदन के मार्शल और जिला जेल, लखनऊ के अधीक्षक के नाम एक सामान्य वारंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया था, "चूंकि... विधानसभा ने निर्णय लिया है... कि श्री केशव सिंह को विधानसभा की अवमानना का अपराध करने के लिए सात दिनों के साधारण कारावास की सजा दी जाए, तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि केशव सिंह को सात दिनों की अवधि के लिए जिला जेल, लखनऊ में निरुद्ध रखा जाए।" वारंट में वे तथ्य नहीं बताए गए थे जिनसे अवमानना का मामला बनता हो। इसके बाद केशव सिंह को उसी दिन जेल ले जाया गया और वही निरुद्ध रखा गया। दिनांक 19 मार्च, 1964

को, बी. सोलोमन नामक एक अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ स्थित पीठ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की, जिसका गठन तत्कालीन न्यायाधीश बेग और सहगल ने किया था। केशव सिंह की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया है और यह निरुद्धि दुर्भावनापूर्ण थी। इस पीठ को लखनऊ पीठ कहा गया है। इस याचिका

को संविधान के अनुच्छेद 226 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के अंतर्गत दायर याचिका माना गया। उसी दिन विद्वान न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि केशव सिंह को जमानत पर रिहा किया जाए और याचिका स्वीकार की जाए तथा इसमें नामित प्रत्यर्धीगण को नोटिस जारी किया जाए। केशव सिंह को तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस आदेश ने सदन द्वारा पारित कारावास की सजा में हस्तक्षेप करते हुए केशव सिंह को उसकी सजा की पूरी अवधि पूरी करने से पहले ही रिहा करने की अनुमति दे दी। दिनांक 21 मार्च, 1964 को विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति बेग, न्यायमूर्ति सहगल, बी. सोलोमन और केशव सिंह ने सदन की अवमानना की है और केशव सिंह को तुरंत हिरासत में ले लिया जाना चाहिए और उनके कारावास की शेष अवधि के लिए जिला जेल में बंद रखा जाना चाहिए और न्यायमूर्ति बेग, न्यायमूर्ति सहगल और बी. सोलोमन को हिरासत में सदन के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और यह भी कि केशव सिंह को उनकी सजा की शेष अवधि पूरी करने के बाद सदन के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। प्रस्ताव की शर्तों को लागू करने के लिए दिनांक 23 मार्च 1964 को सदन के मार्शल और लखनऊ के कमिश्नर को वारंट जारी किये गये। उसी दिन, न्यायमूर्ति सहगल ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक याचिका दायर की, जिसमें 21 मार्च, 1964 के विधानसभा के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए एक रिट जारी करने और विधानसभा के अध्यक्ष और मार्शल तथा राज्य सरकार को उस प्रस्ताव को लागू करने और प्रस्ताव के अनुसरण में जारी आदेशों के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए अन्य आवश्यक रिट जारी करने की मांग की गई। हालांकि याचिका में यह उल्लेख नहीं किया गया कि वारंट जारी किए गए थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वारंट याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी किए गए थे, या वारंट जारी किए जाने के बारे में याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं थी। इस याचिका पर न्यायमूर्ति सहगल और न्यायमूर्ति बेग को छोड़कर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने सुनवाई की और उसी दिन एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। इसी तरह की याचिकाएं बी. सोलोमन और न्यायमूर्ति बेग और अवध बार एसोसिएशन सहित अन्य पक्षकारों द्वारा भी प्रस्तुत की गईं और उनमें से कुछ पर न्यायमूर्ति सहगल की याचिका के समान ही आदेश दिए गए प्रतीत होते हैं। दिनांक 25 मार्च, 1964 को सदन ने यह टिप्पणी दर्ज की कि 21 मार्च, 1964 के अपने प्रस्ताव द्वारा उसका यह इरादा नहीं था कि वह यह निर्णय ले कि न्यायमूर्ति बेग, न्यायमूर्ति सहगल, बी. सोलोमन और केशव सिंह ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना सदन की अवमानना की है, बल्कि सदन के समक्ष उनकी उपस्थिति की अपेक्षा की गई थी ताकि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जा सके और उसने संकल्प लिया कि नियमों के अनुसार उपर्युक्त व्यक्तियों को उनके आवरण को स्पष्ट करने का अवसर देने के बाद ही इस प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रस्ताव के अनुसरण में, 26 मार्च 1964 को न्यायमूर्ति बेग, न्यायमूर्ति सहगल और बी. सोलोमन को नोटिस जारी कर सूचित किया गया कि "वे 6 अप्रैल 1964 को प्रातः 10 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।" दिनांक 23 मार्च, 1964 को जारी किए गए वारंट, जिन पर कभी अमल नहीं हुआ था, इन नोटिसों के मद्देनजर वापस ले लिए गए। वर्तमान संदर्भ 26 मार्च, 1964 को किया गया था और उसके बाद विधानसभा ने 26 मार्च, 1964 के नोटिस वापस ले लिए थे, जिसमें कहा गया था कि संदर्भ के मद्देनजर दो न्यायाधीशों और सोलोमन और केशव सिंह को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तथ्य संदर्भ आदेश में निहित विवरणों में दिए गए हैं। हालांकि, विवरणों में तथ्यों के कथन के बारे में एक विवाद है। इसमें कहा गया है कि 21 मार्च 1964 को सदन ने संकल्प लिया कि दो न्यायाधीशों, सोलोमन और केशव सिंह ने "अपने उपरोक्त कार्यों से सदन की अवमानना की है।" "पूर्वोक्त कार्यवाही" शब्द केशव सिंह की दिनांक 19 मार्च, 1964 की याचिका की प्रस्तुति और उस पर दिए गए आदेश को संदर्भित करते हैं। विधानसभा की ओर से यह बताया गया है कि प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया है कि अवमानना किस तरह की गई। यह तर्क सही है।

इस संदर्भ में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विधानसभा को किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए सामान्य वारंट द्वारा अर्थात् अवमानना के तथ्यों को बताए बिना जेल भेजने का विशेषाधिकार है, और यदि वह ऐसा करती है, तो क्या न्यायालयों को ऐसी अवमानना की वैधता की जांच करने की शक्ति है? दूसरे शब्दों में, यदि ऐसा कोई विशेषाधिकार है, तो क्या यह हिरासत में लिए गए नागरिक के मौलिक अधिकारों से ऊपर है। विधानसभा की ओर से कहा गया

है कि उसे ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है और वर्तमान मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप क्षेत्राधिकार के बाहर था। अब प्रश्न विधानसभा के विशेषाधिकार का है, क्योंकि यदि उसके पास आवश्यक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने जो किया है, वह वर्तमान प्रयोजनों के लिए अपवाद रहित होगा।

सर्वप्रथम विधानसभा के विशेषाधिकारों के संबंध में। विधानसभा अपने उद्देश्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (3) पर निर्भर करती है। इस चरण में उस अनुच्छेद के पहले तीन खंड निर्धारित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 194(1) इस संविधान के प्रावधानों और विधानसभा की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधायिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी।

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई सदस्य विधान-मंडल या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्राधिकार से किसी रिपोर्ट, पत्र, मतों या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) अन्य मामलों में, किसी राज्य के विधानसभा के एक सदस्य की, तथा ऐसे विधानसभा के एक सदस्य के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जो समय-समय पर विधानसभा द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जाएंगी, और जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती है, तब तक वे इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स की, तथा उसके सदस्यों और समितियों की होंगी।

अनुच्छेद 105 में केंद्रीय विधायिका के संबंध में समान प्रावधान है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दोनों सदनों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया है। इसलिए विधानसभा का दावा है कि उसे वे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो 25 जनवरी, 1950 को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे।

मैं इस स्तर पर हाउस ऑफ कॉमन्स या उसके सदस्यों की "शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों" के बारे में कुछ सामान्य शब्द कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे उद्देश्यों के लिए "विशेषाधिकारों", "शक्तियों" और "उन्मुक्तियों" के बीच अंतर करना आवश्यक नहीं है। वे अपनी-अपनी विषय-वस्तु के मामले में निःसंदेह भिन्न हैं, लेकिन अन्यथा शायद नहीं। इस प्रकार सदन के अपने आंतरिक कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण रखने के अधिकार को उसका विशेषाधिकार माना जा सकता है, अवमानना के लिए किसी को दंडित करने के उसके अधिकार को उसकी शक्ति के रूप में अधिक उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है, जबकि यह अधिकार कि सदन में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा, वास्तव में एक उन्मुक्ति हो सकती है। हालाँकि ये सभी अधिकार एक ही कानून द्वारा बनाए गए हैं और एक ही मानक द्वारा परखे गए हैं। सुविधा के लिए मैं उन सभी को "विशेषाधिकार" के रूप में वर्णित करूंगा। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों से संबंधित है, न कि उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों से। तथापि मैं इस बात पर बल देता हूं कि बाद के दोनों के विशेषाधिकार, उनकी विषय-वस्तु को छोड़कर, किसी भी मामले में पहले वाले से भिन्न नहीं हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों की प्रकृति पर सबसे अच्छी चर्चा मे की संसदीय प्रैक्टिस का संदर्भ देकर की जा सकती है, जो अंग्रेजी संसद से संबंधित मामलों पर एक स्वीकृत प्राधिकारपूर्ण कार्य है। यहां यह देखना उपयोगी होगा कि लंबे समय से कॉमन्स के मान्यता प्राप्त विशेषाधिकारों की प्रकृति के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

मैं विशेषाधिकारों की प्रकृति को उनके और सदन के कार्यों के बीच अंतर को इंगित करके समझाना प्रारम्भ करता हूँ। इस प्रकार, कथान कानून आरंभ करने के लिए

हाउस ऑफ कॉमन्स की वित्तीय शक्तियों को अक्सर उसका विशेषाधिकार कहा जाता है। हालाँकि, यह हाउस ऑफ कॉमन्स का वह विशेषाधिकार नहीं है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 194 के खंड (3) में किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों का अंग्रेजी संसदीय कानून में एक तकनीकी अर्थ है और अनुच्छेद में इस शब्द का उपयोग केवल उसी अर्थ में किया गया है। उस तकनीकी अर्थ को इन शब्दों में वर्णित किया गया है: "प्रत्येक सदन के कुछ मौलिक अधिकार जो आम तौर पर इसके संवैधानिक कार्यों के लिए आवश्यक माने जाते हैं।" एक बिंदु जिस पर मैं अब जोर देना चाहूँगा वह यह है कि विशेषाधिकारों की प्रकृति का सार यह है कि वे हाउस ऑफ कॉमन्स के मुख्य कार्यों के सहायक हैं। एक और बात जो मैं इस स्तर पर देखना चाहता हूँ वह यह है कि "कुछ विशेषाधिकार केवल संसद के कानून और प्रथा पर आधारित हैं, जबकि अन्य को कानून द्वारा परिभाषित किया गया है। केवल इन आधारों पर ही सभी विशेषाधिकार स्थापित होते हैं"। इस मामले में हम केवल पहले प्रकार के विशेषाधिकार से ही संबंधित होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार का विशेषाधिकार संसद के कानून और प्रथा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। इस कानून को लेक्स पार्लियामेंटी का नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति संसद की प्रथा से हुई है। इसलिए यह इंग्लैंड के सामान्य कानून से अलग है, जो कि हालाँकि प्रथा पर आधारित है, लेकिन एक अलग प्रथा पर आधारित है, यानी वह जो बाकी क्षेत्र में प्रचलित है। उत्पत्ति में इस अंतर ने संसद और कानून की अदालतों के बीच गंभीर विवादों को जन्म दिया था, लेकिन वे कई वर्षों से वही सुलझ चुके हैं और सिद्धांत के विवाद को छोड़कर, किसी भी व्यावहारिक विवाद की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं मानी जाती है। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कोलरिज ने ब्रैडलॉफ बनाम गॉसेट मामले में ऐसा अवधारित किया है।

"क्या सभी मामलों में और सभी परिस्थितियों में सदन अपने विशेषाधिकारों के एकमात्र न्यायाधीश हैं? इस अर्थ में कि किसी भी सदन द्वारा इस विषय पर पारित प्रस्ताव का न्यायालय पर संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे अभी निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय द्वारा संसदीय विशेषाधिकार की समीक्षा की अनुमति देने से बहुत गंभीर जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं, और कई संभावित मामलों में कॉमन्स के विशेषाधिकार लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। लेकिन, किसी भी सदन के प्रस्तावों को न्यायालय में जांच से परे रखना हमें ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचा सकता है जो गंभीर जटिलताओं से मुक्त नहीं होंगे। मेरे लिए इतना कहना ही पर्याप्त है कि मुझे लगता है कि सिद्धांत रूप में इस प्रश्न को हल करना अत्यंत कठिन है; व्यवहार में यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और किसी भी स्थिति में अब यह प्रश्न उठता ही नहीं है।"

विवाद की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए यह अंश पर्याप्त है। इस विवाद पर चर्चा करना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होगा, और वास्तव में मैं सोचता हूँ कि यह "हानिप्रद" होगा, क्योंकि इससे केवल वे त्रुटियाँ जो वर्षों से स्पष्ट रूप से हो रही हैं, को सामने लाकर उसे साफ करने का काम होगा। इसके अलावा, इस देश में यह विवाद कभी नहीं उठ सकता क्योंकि यहाँ संविधान की व्याख्या करना निस्संदेह संविधान का और इसलिए अनुच्छेद 194(3) की व्याख्या करना न्यायालयों का काम है। इसका अर्थ यह है कि जब इस देश में उस अनुच्छेद के तहत यह सवाल उठता है कि संविधान के लागू होने पर हाउस ऑफ कॉमन्स के पास कोई विशेष विशेषाधिकार था या नहीं, तो उस सवाल का निस्तारण, और केवल न्यायालयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यहाँ भयावह "द्वैधता", अर्थात् न्यायालयों का विधानसभा के किसी सदन के साथ इस बात पर विवाद करना कि उसके विशेषाधिकार क्या हैं, की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो कहा है वह वर्तमान संदर्भ के प्रयोजनों के लिए विशेषाधिकारों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और अब मैं विधानसभा के मुख्य कार्य के सहायक अधिकारों के अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करते हुए इस मामले में प्रश्नगत विधानसभा के विशेषाधिकारों पर चर्चा करना प्रारम्भ करूँगा।

मैं जिस विशेषाधिकार की बात सबसे पहले करता हूँ, वह है अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास यह शक्ति है। सभी तय मामलों और पाठ्यपुस्तकों में ऐसी शक्ति का उल्लेख है। "दण्ड की शक्ति को सही मायने में "संसदीय विशेषाधिकार की आधारशिला" के रूप में वर्णित किया

गया है...इसके बिना संसद के विशेषाधिकार आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, लेकिन, यदि वे समाप्त नहीं हुए होते, तो वे कष्ट सहते हुए जीवित रहते।" बर्टेड बनाम एबॉट मामले में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलेनबोरो ने कहा,

"क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि अध्यक्ष को अपने तर्क के साथ सदन के अपमान के लिए अभियोग पत्र पेश करने के लिए ब्रैंड जूरी के समक्ष जाने की आवश्यकता होगी? निश्चित रूप से उनके पास अपने हाथों में आत्म-प्रतिशोध और आत्म-सुरक्षा की शक्ति होनी चाहिए....."

इसलिए, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास इस शक्ति का होना संदेहस्पद है।

अवमानना करने की शक्ति की प्रकृति को समझने के लिए इसकी तुलना विशेषाधिकार के उल्लंघन से करना उपयोगी होगा, जो स्वयं अवमानना के समतुल्य हो सकता है। इस प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्यवाही का उसके आदेशों के विरुद्ध प्रकाशन उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन है और अवमानना के समान है। हालाँकि, सभी अवमाननाएँ विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हैं। हालाँकि सदन की गरिमा या अधिकार के विरुद्ध अपराध को "विशेषाधिकार का उल्लंघन" कहा जाता है, लेकिन अवमानना के रूप में अधिक उचित रूप से पहचाना जाता है। अवमानना के लिए जेल भेजना अपने आप में हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार है, चाहे अवमानना उसके विशेषाधिकार के सीधे उल्लंघन से की गई हो या उसकी गरिमा या अधिकार को ठेस पहुँचाने से। "इस प्रकार एक विधायी निकाय के कार्य, विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक शक्तियाँ आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। विशेषाधिकार कार्यों के आवश्यक पूरक हैं, और विशेषाधिकारों की अनुशासनात्मक शक्तियाँ हैं।" मैं यह जोड़ सकता हूँ कि यह विवाद में नहीं है कि अवमानना करने की शक्ति का प्रयोग न केवल सदन के सदस्य के विरुद्ध किया जा सकता है, बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय की ओर से यह तर्क दिया गया कि अवमानना के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति अनुच्छेद 194 के खंड (3) द्वारा राज्य विधानसभा के सदस्यों को प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि हमारे संविधान को शक्तियों के विभाजन के लिए प्रदान करने वाली इसकी मूल योजना के साथ पढ़ा जाना चाहिए और अवमानना के लिए जेल भेजने की शक्ति सार रूप में एक न्यायिक शक्ति है, जो हमारे संविधान के तहत केवल न्यायिक निकाय, अर्थात् न्यायालयों के पास हो सकती है, न कि विधानसभा जैसे विधायी निकाय के पास। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 194 (3) को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा विधायी निकाय को अपने विशेषाधिकारों में से एक के रूप में न्यायिक शक्तियों को प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है और इसलिए विधानसभा के पास यह नहीं है।

मेरे विचार में, उच्च न्यायालय का यह तर्क पूरी तरह से निराधार है; सिद्धांत और प्राधिकार दोनों इसके विरुद्ध हैं। इस न्यायालय ने पहले भी कई अवसरों पर टिप्पणी की है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत हमारे संविधान का अनिवार्य हिस्सा नहीं है: उदाहरण के लिए देखें दिल्ली विधि अधिनियम के संदर्भ में। फिर भी संविधान निश्चित रूप से सर्वोच्च है और भले ही यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित हो, संविधान निर्माताओं को, यदि वे चाहें तो, विधायी निकाय को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि इससे संबंधित प्रावधान गलत था क्योंकि हमारा संविधान शक्तियों के विभाजन पर आधारित था। ऐसा तर्क निश्चित रूप से निराधार होगा। इसलिए, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने विधानसभाओं को दण्डित करने की शक्ति प्रदान की है। प्रश्न यह नहीं है कि उनके पास ऐसा करने की शक्ति थी या नहीं, क्योंकि उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, यह केवल उनके

द्वारा बनाए गए संविधान में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ही पता लगाया जा सकता है। यदि वे शब्द स्पष्ट हैं,

तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए, भले ही हमारा संविधान शक्ति के विभाजन पर आधारित हो या नहीं। यह

मुझे अनुच्छेद 194 के खंड (3) में प्रयुक्त भाषा की ओर ले जाता है। वहाँ जो शब्द दिखाई दे रहे

हैं, वे हैं "एक सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ.... वे हाउस ऑफ कॉमन्स की

होंगी"। मैं इससे ज्यादा स्पष्ट भाषा की कल्पना नहीं कर सकता। उस भाषा का सिर्फ

एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह कि इसका उद्देश्य राज्य विधानमंडलों को वे

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करना था जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ़ कॉमन्स को प्राप्त थी। यहाँ शक्तियों के विभाजन के एक कथित सिद्धांत के प्रति निष्ठा जताकर शब्दों के स्पष्ट अर्थ को नकारने की कोई चतुराई नहीं है। यहाँ तक कि शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में भी यही बात है।

पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा मामले में इस न्यायालय के निर्णय से यह प्रश्न और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। मुझे इस मामले का बाद में विस्तार से उल्लेख करना होगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश दास ने पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के बहुमत से निर्णय सुनाया तथा न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपनी असहमतिपूर्ण राय दी। मुख्य न्यायाधीश दास ने इस आधार पर निर्णय दिया कि राज्य विधानसभा के सदनों को अवमानना का दायित्व सौंपने का अधिकार है। इसलिए, यह माना गया कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विधायी निकाय को न्यायिक शक्तियाँ रखने से रोकता हो। इस बिंदु पर न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कोई असहमति नहीं जताई। इसके अलावा, इंग्लैंड में न्यायिक समिति ने दो मामलों में माना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 194(3) के प्रावधानों के समान ही, हाउस ऑफ़ कॉमन्स की अवमानना करने की शक्ति कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों के कुछ विधायी निकायों को प्रदान की गई थी। स्पीकर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेम्बली ऑफ़ विक्टोरिया बनाम ग्लास मामले में यह अवधारित किया गया कि एक कानून कहता है कि "विक्टोरिया की विधान परिषद्.....ऐसे विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों और शक्तियों को धारण करेगी, उनका उपभोग करेगी और उनका प्रयोग करेगी जैसे कि.....ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संसद के कॉमन्स सदन द्वारा धारण किए गए, उनका उपभोग किया गया और उनका प्रयोग किया गया था" जो विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के विधानसभा के सदनों को अवमानना के लिए न्यायिक शक्ति प्रदान करता है। क्वीन बनाम रिवर्स मामले में यह अवधारित किया गया कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल संविधान अधिनियम, 1901 की धारा 49, जिसमें यह प्रावधान था कि "सीनेट और प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ...ऐसी होंगी जैसी संसद द्वारा घोषित की जाती हैं, और घोषित होने तक, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कॉमन्स हाउस की होंगी....", सदन को अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजने की न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। मुख्य न्यायाधीश डिकसन द्वारा यह टिप्पणी की गई-

"यह उन ऐतिहासिक आधारों पर चर्चा करने का अवसर नहीं है, जिनके आधार पर हाउस ऑफ़ कॉमन्स को ये शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्रदान किये गए। यह कहना पर्याप्त है कि कई अधिकारियों ने उन्हें विधायी कार्य की उचित घटनाओं के रूप में इस तथ्य के बावजूद माना कि अधिक सैद्धांतिक रूप से - शायद कोई यह भी कह सकता है कि वैज्ञानिक रूप से - वे न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हैं। लेकिन हमारा निर्णय इस आधार पर आधारित है कि संविधान और शक्तियों के पृथक्करण का एक सामान्य दृष्टिकोण इन शब्दों को, जो हमें इतने स्पष्ट प्रतीत होते हैं, एक प्रतिबंधात्मक या गौण अर्थ देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, जो वे उचित रूप से धारण नहीं करते हैं।"

ऑस्ट्रेलियाई संविधान और हमारे संविधान में प्रावधानों की भाषा में समानता आश्चर्यजनक है। हालांकि यह कहा गया कि वे समान नहीं हैं क्योंकि धारा 49 के तहत ऑस्ट्रेलियाई सदन प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारों की घोषणा कर सकते हैं जबकि हमारे मामले में विशेषाधिकारों को कानून द्वारा परिभाषित किया जाना था और ऑस्ट्रेलिया में कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस तर्क का बिल्कुल भी पालन नहीं करता। प्रश्न यह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में विशेषाधिकार कैसे घोषित किए जाते हैं या मौलिक अधिकारों का विशेषाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बल्कि उन शब्दों के अर्थ के बारे में है जो दोनों कानूनों में समान हैं। रिवर्स के मामले में मुख्य न्यायाधीश डिकसन के निर्णय से अपील करने की अनुमति के लिए न्यायिक समिति को आवेदन किया गया था, लेकिन ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, विस्काउंट साइमंड्स ने टिप्पणी की कि ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय का निर्णय "अपमानजनक है": क्वीन बनाम रिवर्स। कनाडा में नोवा स्कोटिया के विधानसभा को कॉमन्स के विशेषाधिकार प्रदान करने वाले एक समान प्रावधान की व्याख्या के लिए फीलिडिंग बनाम थॉमस का संदर्भ भी लिया जा सकता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 194(3) विधानसभा को अवमानना करने की शक्ति प्रदान करता है और उसके पास वह शक्ति है।

अगला प्रश्न सामान्य वारंट द्वारा अवमानना करने के विशेषाधिकार के विषय में है। इंग्लैंड में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यदि हाउस ऑफ़ कॉमन्स

अवमानना के तथ्यों को बताए बिना सामान्य वारंट द्वारा अवमानना करता है, तो अदालतें उस आदेश की समीक्षा नहीं करेंगी। हालांकि उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि अंग्रेजी हाउस ऑफ कॉमन्स की यह शक्ति उसके विशेषाधिकारों में से एक नहीं थी, बल्कि यह उस सदन के पास थी क्योंकि वह एक उच्च न्यायालय था और इसलिए, वह शक्ति, जो विशेषाधिकार नहीं है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 194(3) द्वारा राज्य विधानमंडलों को प्रदान नहीं की गई है। विधानसभा द्वारा यह दावा नहीं किया गया है कि यह एक उच्च न्यायालय है और इसलिए, उसके पास सामान्य वारंट द्वारा अवमानना करने का अधिकार है। अगर ऐसा दावा किया गया होता तो मुझे ऐसा कोई औचित्य नहीं मिलता। यह मुझे इस प्रश्न पर ले जाता है कि क्या सामान्य वारंट द्वारा अवमानना करने का अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में से एक है, या, क्या यह कुछ ऐसा है जो इंग्लैंड के सामान्य कानून के तहत उस सदन के पास था क्योंकि वह एक उच्च न्यायालय था?

मुझे इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई अधिकार नहीं मिला कि सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति जिसके परिणामस्वरूप उस दण्ड के संबंध में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से वंचित होना कुछ ऐसा है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास था क्योंकि यह एक उच्च न्यायालय था। सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि हाउस ऑफ कॉमन्स कभी स्वयं एक न्यायालय था। उस सदन का इतिहास इस तरह के तर्क का समर्थन नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना जरूरी समझता हूँ कि हम हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि यह एक अलग निकाय है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ब्रिटिश संसद का एक अभिन्न अंग है, जिसमें राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी शामिल हैं। हालांकि, हम जिन विशेषाधिकारों के बारे में चिंतित हैं, वे वे हैं जिनका दावा हाउस ऑफ कॉमन्स एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अकेले अपने लिए करता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास मौजूद विशेषाधिकारों से अलग है। वास्तव में यह स्पष्ट है कि दोनों सदनों के विशेषाधिकार समान नहीं हैं: मे अध्याय III ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजी इतिहास के प्रारम्भिक दिनों में संसद एक न्यायालय थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हाउस ऑफ कॉमन्स इस न्यायालय का हिस्सा था। मध्यकालीन समय में कानूनी अवधारणा यह थी कि राजा सभी चीजों का स्रोत था; ऐसा माना जाता था कि न्याय राजा से ही आता है, इसलिए न्यायालय को राजा से संबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार राजा का न्यायालय एक कानूनी न्यायालय था और यही "संसद का उच्च न्यायालय" कहलाने वाली संस्था का मूल है। संसद के उच्च न्यायालय का इतिहास पॉटर्स आउटलाइन्स ऑफ इंग्लिश लीगल हिस्ट्री (1958 संस्करण) में संक्षेपित किया गया है और इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: किंग्स काउंसिल, अपने पुराने शीर्षक व्यूरिया रेजिस के अंतर्गत, कॉमन लॉ कोर्ट की जननी थी, लेकिन कॉमन लॉ कोर्ट के सुस्थापित हो जाने के बाद भी इसने कुछ न्यायिक कार्यों को बरकरार रखा। (पृ. 78)। हालांकि बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में यह माना जाने लगा कि राजा के न्यायपीठ से अपील संसद में की जा सकती है, न कि परिषद में। लेकिन संसद के पास करने के लिए बहुत सारा काम था और उसे याचिकाओं की सुनवाई करने या यहां तक कि राजा की न्यायपीठ से त्रुटि के नियमों की सुनवाई के लिए भी बहुत कम समय मिल पाता था और 15वीं शताब्दी में यह अधिकारिता स्थापित हो गई। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसद में कॉमन्स का कोई हिस्सा नहीं था। वर्ष 1485 में सभी न्यायाधीशों ने माना कि त्रुटि के मामले में क्षेत्राधिकार केवल हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है, न कि पूरी संसद का। प्रोफेसर होल्ड्सवर्थ ने इस तथ्य की व्याख्या करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से भुलाया नहीं गया कि क्षेत्राधिकार राजा और संसद में उनकी परिषद का था, जबकि कॉमन्स कभी भी उनकी परिषद का हिस्सा नहीं थे, संसद में उनकी परिषद में राजा का मतलब केवल राजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से था; पृष्ठ 95। यह बताना भी रोचक है कि जब कॉमन्स अलग-अलग विचार-विमर्श करते थे, तो वे वेस्टमिंस्टर के प्रमुख के चौपटर-हाउस या भोजन कक्ष में बैठते थे; और अंतिम रूप से अलग होने के बाद भी वे उसी स्थान पर बैठते रहे; मे, पृष्ठ 12। जिस पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच का पृथक्करण है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब यह कहा जाता है कि इंग्लैंड में कानून राजा द्वारा संसद में बनाए जाते हैं, तो होता यह है कि कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बार में जाते

हैं, जहाँ राजा या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो उनसे कमीशन प्राप्त करता है, किसी अधिनियम को स्वीकृति देता है। यह सब दिखाता है कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स एक

अलग निकाय के रूप में बैठता है तो वह संसद में नहीं बैठता है। इसलिए यह संसद का उच्च न्यायालय नहीं है। मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हम इस मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के बारे में चिंतित हैं जो एक अलग निकाय के रूप

में काम करता है, यानी संसद में नहीं बैठता है। श्रीमान मे ने पृष्ठ 90 पर टिप्पणी की, "क्या हाउस ऑफ कॉमन्स, कानूनी रूप से, एक अभिलेख न्यायालय है, यह निर्धारित करना कठिन होगा:" एन्सन्स लॉ ऑफ द कॉन्स्टीट्यूशन , 5वें संस्करण खंड 1 के पृष्ठ 197 में कहा गया है कि "चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स अभिलेख न्यायालय हो या न हो, न केवल उसे अवमानना के लिए दण्ड द्वारा अपमान से स्वयं को बचाने की समान शक्ति है, बल्कि सुपीरियर कोर्ट ऑफ लॉ ने इस मामले में वही किया, जैसे वे एक-दूसरे के साथ करते हैं, और इस कथन को निर्णायक रूप से स्वीकार कर लिया है कि अवमानना की गई है, बिना यह पूछे कि वह अवमानना क्या हो सकती है।" मुझे लगता है कि प्राधिकारियों की इस स्थिति में यह मानना कम से कम खतरनाक होगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक अभिलेख न्यायालय है। यदि ऐसा नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अभिलेख न्यायालय के रूप में सामान्य वारंट द्वारा अपनी अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति प्राप्त थी।

अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के इस अधिकार को इंग्लैंड के आधिकारिक पाठ्यपुस्तक लेखकों द्वारा किस प्रकार विचारित है। पृष्ठ 173 पर, कॉमन्स और न्यायालयों के बीच विशेषाधिकारों के संबंध में विवाद पर चर्चा करने के बाद और यह कहने के बाद कि सिद्धांत रूप में दोनों के बीच संघर्ष होने पर वास्तविक मुद्दे को हल करने का कोई तरीका नहीं है। श्रीमान मे ने टिप्पणी की, "हालाँकि, व्यवहार में, विशेषाधिकार की प्रकृति और सिद्धांतों पर क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर गतिरोध की अपेक्षा कहीं अधिक सहमति है।" इसके बाद वे कहते हैं, "न्यायालय स्वीकार करते हैं:-(3) कि प्रत्येक सदन का अपनी आंतरिक कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण है और न्यायालयों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (4) कि किसी भी सदन द्वारा अवमानना के लिए किया गया दायित्व व्यवहार में उसके अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है, क्योंकि कथित अवमानना से संबंधित तथ्यों को दायित्व के वारंट पर बताए जाने की आवश्यकता नहीं है।" इसलिए मे हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार को सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के अधिकार को उसके विशेषाधिकारों में से एक मानते हैं, न कि ऐसा कुछ जिसके लिए वह अभिलेखीय न्यायालय के रूप में सामान्य कानून के तहत हकदार है। केर और लॉसन द्वारा संवैधानिक कानून पर मामले, (चौथा संस्करण) पृष्ठ 126 में कहा गया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के निरसंदेह विशेषाधिकारों में "संसद के सदस्यों, या किसी अन्य व्यक्ति को सदन की अवमानना के लिए कारावास में डालकर विशेषाधिकार के मामलों पर निर्णय निष्पादित करने की शक्ति है। इसका उदाहरण मिडिलसेक्स के शेरिफ के मामले में मिलता है।" यह एक ऐसा मामला है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक सामान्य वारंट द्वारा मिडिलसेक्स के शेरिफ को अवमानना के लिए दण्डित किया था, शेरिफ ने हाउस के आदेशों का उल्लंघन करते हुए किंग्स बेंच डिवीजन के एक आदेश का पालन किया था, जिसे करने के लिए वह बाध्य था और न्यायालय ने अवधारित किया कि हाउस द्वारा किए गए समर्पण की वैधता के प्रश्न पर विचार करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है: देखें शेरिफ ऑफ मिडिलसेक्स। हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड, खंड 28, पृष्ठ 467 में कहा गया है कि न्यायालय उन कारणों की जांच नहीं करेगा जिनके लिए किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया जाता है और किसी भी सदन द्वारा उस वारंट के माध्यम से अवमानना की जाती है जिसमें उसकी गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह टिप्पणी हाउस ऑफ कॉमन्स और न्यायालयों के बीच पूर्व के विशेषाधिकारों के संबंध में संघर्ष से निपटने के लिए की गई है और स्पष्ट रूप से एक सामान्य वारंट जारी करने की शक्ति को सदन के विशेषाधिकार के मामले के रूप में माना जाता है। अंत में, डाइसी कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ (10वें संस्करण) में पृष्ठ 58 पर फुटनोट में यह कहा गया है।

"संसदीय विशेषाधिकार कभी भी सटीक प्रकृति की कानूनी परिभाषा का विषय नहीं रहा है। एक या दो बिंदु ध्यान देने योग्य हैं जो स्पष्ट रूप से स्थापित हैं।

(1) संसद का कोई भी सदन अवमानना के लिए दण्ड दे सकता है, और न्यायालय दण्ड की जाँच नहीं करेगा और कथित अवमानना का गठन करने वाले तथ्यों की जांच नहीं करेंगे, बशर्ते कि अवमानना का कारण नहीं बताया गया हो।"

इस प्रकार मैं पाता हूँ कि निःसंदेह अधिकार रखने वाले लेखकों ने सामान्य वारंट द्वारा अपराध करने की इस शक्ति को, जिसके परिणामस्वरूप कारावास की वैधता पर निर्णय करने के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वंचित कर दिया जाता है, सदन के

विशेषाधिकार के रूप में माना है, न कि एक उच्च न्यायालय के रूप में उसके पास मौजूद अधिकार के रूप में।

अब मैं न्यायिक समिति के हाल के निर्णयों का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार के आधार पर सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के अधिकार को भी शामिल किया गया है। पहला मामला जिस पर मैं विचार करूँगा, वह ग्लास का मामला है। वहाँ विक्टोरिया कॉलोनी की विधान सभा ने एक सामान्य वारंट द्वारा ग्लास को अवमानना के लिए जेल में डाल दिया और मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अदालत के समक्ष लाया गया। मैंने पहले कहा है कि कुछ कानूनों के तहत विधानसभा ने उन्हीं विशेषाधिकारों का दावा किया जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थे। विक्टोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने ग्लास के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर मामला न्यायिक समिति के पास ले जाया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ तर्क दिया गया कि "विशेषाधिकार केवल अवमानना के लिए दण्डित करने का विशेषाधिकार है; अपील के बिना अवमानना का न्याय करना, और एक सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति, इस देश पर लागू होने वाली घटनाएँ या दुर्घटनाएँ हैं, और कॉलोनी को हस्तांतरित नहीं की गई है।" "इस देश" शब्द का तात्पर्य इंग्लैंड से था। लॉर्ड कैरेस ने इस तर्क को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया: "अवमानना का न्याय करने और एक सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के तत्व, शायद इस देश में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास मौजूद विशेषाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं; और यह वास्तव में अजीब होगा यदि, हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकारों और शक्तियों को हस्तांतरित करने की शक्ति के तहत, वह जो केवल एक हिस्सा होगा, और तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हिस्सा होगा, इस विशेषाधिकार और शक्ति का हस्तांतरण किया गया।" (पृष्ठ 573)। उन्होंने यह भी कहा, (पृष्ठ 572) "इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का एक विशेषाधिकार और सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार अवमानना के लिए दण्डित करने का विशेषाधिकार है और उस विशेषाधिकार के साथ-साथ, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस देश में यह सुस्थापित है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को स्वयं ही यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या अवमानना है, और उस अवमानना के लिए वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार है, जिसमें यह कहा गया है कि दण्ड सामान्य रूप से सदन की अवमानना के लिए होता है, बिना यह निर्दिष्ट किए कि अवमानना की प्रकृति क्या है। इसलिए, यह लगभग अनिवार्य है कि कॉलोनी के विधानसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ और शक्तियाँ कॉलोनी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है, और संविधि की तिथि पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी विशेषाधिकारों और शक्तियों को कॉलोनी को हस्तांतरित करने के बाद, कॉलोनी की विधान सभा को हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना से संबंधित विशेषाधिकार या शक्ति हस्तांतरित की गई - विशेषाधिकार या शक्ति, अर्थात् अवमानना के लिए दण्डित करने की, अवमानना के बारे में स्वयं निर्णय लेने की, और एक वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति, जिसमें आम तौर पर यह कहा गया हो कि अवमानना हुई है।" रिचर्ड के मामले में सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति को सदन का विशेषाधिकार माना गया था और ग्लास के मामले में लॉर्ड केर्न्स की टिप्पणियों को उस दृष्टिकोण के समर्थन में उद्धृत किया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस दृष्टिकोण को न्यायिक समिति द्वारा बरकरार रखा गया था: क्वीन बनाम रिचर्ड। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुख्य न्यायाधीश डिवसन की राय थी, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि दण्डित करने की शक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक उचित रूप से एक न्यायिक शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पाया कि यह तकनीकी रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार था और इसलिए इसे 1901 के ऑस्ट्रेलियाई संविधान अधिनियम की धारा 49 द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सदनों को हस्तांतरित कर दिया गया था। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि यह मामला वर्ष 1955 का था और यह दर्शाता है कि उस समय यह माना जाता था कि सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार सदन का विशेषाधिकार था। मैं यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह सुझाव दिया गया है कि भले ही यह विशेषाधिकार था, लेकिन यह अप्रचलन के कारण खो गया था। ये मामले दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। फीलिडिंग बनाम थॉमस भी यही दृष्टिकोण रखता है।

यह कहा गया कि न्यायिक समिति के निर्णय हम पर बाध्यकारी नहीं थे। ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर यह नहीं दिखाया गया कि वे गलत हैं और इसलिए, कम से कम प्रेरक अधिकारियों के रूप में वे मूल्यवान हैं। हालाँकि, यह तथ्य कि न्यायिक समिति के निर्णय हम पर एक उच्च न्यायालय के निर्णयों के रूप में बाध्यकारी नहीं हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे निर्णय के लिए असली प्रश्न यह है कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स के पास कोई विशेष

विशेषाधिकार था। हमें या तो उस विशेषाधिकार का न्यायिक संज्ञान लेना होगा या विदेशी कानून के मामले के रूप में उसके अस्तित्व का फैसला करना होगा। यह तय करना अनावश्यक है कि कौन सा दृष्टिकोण सही है। यदि पहला दृष्टिकोण है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के तहत इंग्लैंड की अधिकृत कानून रिपोर्टों का संदर्भ वैध होगा और यदि दूसरा दृष्टिकोण है, तो फिर से उस अधिनियम की धारा 38 के तहत इन रिपोर्टों का संदर्भ उचित होगा। अतः किसी भी स्थिति में हमें इन रिपोर्टों को देखने का अधिकार है और चूंकि इनमें इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालयों में से एक के निर्णय शामिल हैं, इसलिए हम यह कहने के हकदार नहीं हैं कि जिसे वे अपने देश के हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार कहते हैं, वह तब तक विशेषाधिकार नहीं है जब तक कि कोई अन्य समान रूप से उच्च प्राधिकारी इसके विपरीत विचार न व्यक्त कर दे।

अब मैं कुछ ऐसे अंग्रेजी मामलों पर आता हूँ, जिन पर यह प्रस्ताव आधारित है कि सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अधिकार है जो उसे एक उच्चतर न्यायालय के रूप में प्राप्त है, जैसा कि मैंने उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को समझा है। मैं मामलों को तारीख के क्रम में देखूँगा। इन मामलों के तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा और यह बताना पर्याप्त होगा कि उनमें से प्रत्येक, हाउस ऑफ कॉमन्स के सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के अधिकार से संबंधित है। सबसे पहले, बर्डेट बनाम एबॉट है। इस मामले में, पहले न्यायालय के निर्णय मुख्य न्यायाधीश एलेनबोरो और न्यायमूर्ति बेली द्वारा सुनाए गए थे। इस मामले के संबंध में, एन्सन ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ 189 पर लिखा है, "यह ध्यान देने योग्य है कि बर्डेट बनाम एबॉट के मामले में न्यायमूर्ति बेली ने सदन के दावे को न्यायिक न्यायालयों के साथ अपनी स्थिति की समानता पर आधारित किया, जबकि मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलेनबोरो ने अपने निर्णय को समीचीनता के व्यापक आधार पर और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसी शक्ति की आवश्यकता पर आधारित किया।" इसलिए, एंसन के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश एलेनबोरो स्पष्ट रूप से यह नहीं मानते कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक न्यायालय है और न्यायमूर्ति बेली जो कुछ भी करते हैं, उनके अनुसार, वह हाउस ऑफ कॉमन्स को उच्चतर न्यायालय के बराबर रखना है। यदि हाउस ऑफ कॉमन्स एक न्यायालय था, तो निश्चित रूप से, उसे न्यायालय के बराबर रखने का कोई सवाल ही नहीं था। इस निर्णय के विरुद्ध हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की गई और उस अपील में बहस समाप्त होने के बाद लॉर्ड एल्डन एलसी ने न्यायाधीशों से उनकी सलाह के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछा, "क्या, यदि कॉमन प्लीज़ न्यायालय ने किसी कृत्य को न्यायालय की अवमानना करार देते हुए, विशेष परिस्थितियों के बिना सामान्यतः ऐसे निर्णय को बताते हुए एक वारंट के तहत अवमानना के लिए दण्डित किया था, और मामला किंग्स बेंच के न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से वापस लाया गया था। रिटर्न में वारंट को स्थापित करना, सामान्यतः अवमानना के ऐसे निर्णय को बताना; क्या उस मामले में किंग्स बेंच की अदालत कैदी को रिहा कर देगी, क्योंकि विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ, जिनसे अवमानना उत्पन्न हुई थी, वारंट में निर्धारित नहीं थी": बर्डेट बनाम एबॉट। न्यायाधीशों ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया। इसके बाद लॉर्ड एल्डन ने अपना निर्णय सुनाया, जिससे न्यायालय के अन्य सदस्य सहमत हुए, जिसमें कहा गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार है। मैं यह मानने में असमर्थ हूँ कि यह मामला यह दर्शाता है कि लॉर्ड एल्डन इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुँचे क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स एक उच्च न्यायालय था। मुझे लगता है कि लॉर्ड एल्डन ने सोचा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। जिस तरह से एक उच्च न्यायालय दूसरे के साथ व्यवहार करता है और यह जानना चाहता था कि न्यायालय एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं बाद में दिखाऊँगा कि यह वही दृष्टिकोण है जो अन्य मामलों में लॉर्ड एल्डन के फैसले के बारे में लिया गया है। लेकिन अब मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि यदि लॉर्ड एल्डन ने यह माना होता कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक न्यायालय है, तो एन्सन जैसे प्रतिष्ठित संवैधानिक वकील ने इस मामले को उस तरह से नहीं रखा होता जैसा कि मैंने अभी उनके काम से पढ़ा है।

फिर मैं स्टॉकडेल बनाम हंसर्ड के मामले पर आता हूँ। उस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड डेनमैन, न्यायमूर्ति लिटिलडेल, न्यायमूर्ति पैटेसन और न्यायमूर्ति कोलरिज ने की थी। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड डेनमैन ने अवधारित किया, (पृष्ठ 1168):

"इससे पहले कि मैं अंततः इस तर्क को छोड़ दूँ, मैं इस धारणा को खारिज कर दूँगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक अलग न्यायालय है, जिसके पास विषय-वस्तु पर विशेष अधिकारिता है, और इस कारण से, इस पर उसका निर्णय अंतिम होना चाहिए। इस तर्क ने सदन को आध्यात्मिक न्यायालय और एडमिरल्टी न्यायालय के स्तर पर रखा। इस सादृश्य को अपनाने से, मुझे लगता है कि वर्तमान कार्रवाई के लिए किए गए बचाव को नष्ट कर दिया गया है..... हम अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या यह विषय-वस्तु हाउस ऑफ कॉमन्स के क्षेत्राधिकार में आती है। यह तर्क दिया जाता है कि वे इसे अपने क्षेत्राधिकार में घोषित करके ला सकते हैं। उनके विशेषाधिकारों से उत्पन्न इस दावे के लिए, मैंने पहले ही अपना उत्तर दे दिया है: यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी न्यायालय यह निर्णय देकर स्वयं को क्षेत्राधिकार नहीं दे सकता कि वे इसका उपभोग करते हैं।"

स्पष्ट रूप से लॉर्ड डेनमैन इस आधार पर आगे नहीं बढ़े कि कॉमन्स एक न्यायालय था। वास्तव में वे अधिकार को "इस विशेषाधिकार से उत्पन्न होने वाला" बताते हैं। फिर मैं न्यायमूर्ति लिटिलडेल को पृष्ठ 1174 पर यह टिप्पणी करते हुए पाता हूँ: "लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कार्यवाही प्रतिकूल दावों पर आधारित नहीं है; न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं है; वादी पक्षों के बीच निर्णय करने के लिए कोई न्यायाधीश नहीं है; लेकिन यह हाउस ऑफ कॉमन्स ही है जो एकमात्र पक्ष है जो यह घोषणा करता है कि वे जो कहते हैं वह उनका है।" इसलिए न्यायमूर्ति लिटिलडेल ने भी कॉमन्स को न्यायालय नहीं माना। फिर न्यायमूर्ति पैटेसन आए जिन्होंने पृष्ठ 1185 पर कहा, "हाउस ऑफ कॉमन्स अपने आप में संसद का न्यायालय नहीं है"। फिर से पृष्ठ 1185 पर उन्होंने टिप्पणी की:

"मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि मात्र हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रस्ताव...न्यायालय पर बाध्यकारी होगा...और हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव भी, जो कि अपने सदस्यों के चुनाव के संबंध को छोड़कर, वादी पक्षों के बीच कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न के निर्णय के लिए न्याय न्यायालय नहीं है, न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हो सकता।"

अंत में मैं न्यायमूर्ति कोलरिज के पास आता हूँ। उन्होंने पृष्ठ 1196 पर अवधारित किया:

"लेकिन यह कहा जाता है कि यह और अन्य सभी न्यायालय हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में गरिमा में कमतर है। और इसलिए हमारे लिए इसके निर्णय की समीक्षा करना असंभव है। यह तर्क मुझे कई विवरणों की मिथ्याबोध पर आधारित लगता है; पहला, किस अर्थ में यह न्यायालय हाउस ऑफ कॉमन्स से अधीनस्थ है; दूसरा किस अर्थ में यह सदन एक न्यायालय है..."

फिर पृष्ठ 1196 पर उन्होंने अवधारित किया:

"सच तो यह है कि सदन न्यायालय है ही नहीं, उस अर्थ में जिस अर्थ में यह शब्द यहां उचित रूप से लागू हो सकता है; न तो मूल रूप से, न ही अपील द्वारा, यह दो पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी में किसी मामले का निर्णय कर सकता है; इसके पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं है; यह ऐसी किसी शक्ति का दावा नहीं करता है; जांच और अभियोग लगाने की शक्तियाँ इसके पास हैं, लेकिन यह न्यायिक रूप से कुछ भी निर्णय नहीं करता है, सिवाय इसके कि अवमानना के मामले में यह स्वयं एक पक्ष हो। उनके संबंध में न्यायालयों के बीच डिग्री का कोई प्रश्न नहीं उठता:"

न्यायमूर्ति कोलरिज की टिप्पणियाँ विशेष महत्व की हैं, क्योंकि आगे चलकर यही कारण सामने आएंगे। यह स्पष्ट है कि न तो न्यायमूर्ति पैटेसन और न ही न्यायमूर्ति कोलरिज ने सोचा कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक न्यायालय है या उसके पास ऐसी कोई शक्तियाँ हैं।

तारीख के क्रम में अगला मामला मिडिलसेक्स के शेरिफ का है। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड डेनमैन, ने पृष्ठ 426 पर अवधारित किया:

"प्रतिनिधि निकायों को अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के माध्यम से अपने अधिकार को सिद्ध करना चाहिए; और वे साधन अवमानना के लिए दण्डित करने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यह केवल संसद के सदनों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि रूजैसा कि बर्टे बनाम एबॉट (14 ईस्ट, 138) में देखा गया था,, न्यायालयों पर भी लागू होता है, जो सदनों की

तरह ही निरंतर अवरोध और अपमान के लिए उत्तरदायी होंगे यदि उन्हें ऐसी शक्तियाँ नहीं सौंपी गई हों। इस प्रश्न पर चर्चा करना अनावश्यक है कि संसद का प्रत्येक सदन न्यायालय हो या न हो; यह स्पष्ट है कि वे हस्तक्षेप के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करने की शक्ति के बिना अपने उचित कार्यों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड एल्डन द्वारा बर्डेट बनाम एबॉट (5 डॉव, 199) में न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत इस संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार का परीक्षण यह था कि यदि कॉमन प्ली कोर्ट ने किसी कृत्य को न्यायालय की अवमानना माना है, और उसके लिए दण्डित किया है, तो सामान्य रूप से निर्णय बताते हुए, किंग्स बेंच कोर्ट, वारंट को निर्धारित करने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण पर, कैदी को मुक्त कर देगा क्योंकि अवमानना के तथ्य और परिस्थितियाँ नहीं बताई गई थी। नकारात्मक उत्तर दिए जाने के बाद, लॉर्ड एल्डन ने लॉर्ड एस्किन (जो पहले क्षेत्राधिकार के प्रयोग के प्रतिकूल थे) की सहमति से और सदन से असहमति की आवाज़ के बिना, नीचे दिए गए निर्णय की पुष्टि की। और हमें यह मानकर चलना चाहिए कि कोई भी न्यायालय, और विशेषकर संसद का कोई भी सदन, जो महान कानूनी प्राधिकार के आधार पर कार्य करते हुए, अवमानना का आदेश सुनाता है, वह ऐसा ही है।"

यह अवलोकन बर्डेट बनाम एबॉट (1) में लॉर्ड एल्डन के फैसले के बारे में मैंने जो कहा है, उसका समर्थन करेगा। मुख्य न्यायाधीश डेनमैन ने नहीं सोचा कि लॉर्ड एल्डन हाउस ऑफ कॉमन्स को एक न्यायालय मानते थे क्योंकि उन्हें स्वयं इस सवाल पर चर्चा करना अनावश्यक लगा। उन्होंने क्यों सोचा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार होना चाहिए, इसका आधार समीचीनता और उस कद के निकाय में विश्वास था। न्यायमूर्ति कोलरिज ने पृष्ठ 427 पर टिप्पणी की,

"पूर्व उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को अपने वारंट को इस तरीके से आकार देने की आदत लंबे समय से है। अवमानना के मामलों में इस सामान्य रूप में न्याय करने का उनका अधिकार विशेषाधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्हीं आधारों पर आधारित है, जिन पर यह न्यायालय या कॉमन प्ली कोर्ट अवमानना के लिए दण्ड में कोई कारण बताए बिना दण्डित कर सकता है। लॉर्ड एल्डन ने बर्डेट बनाम एबॉट (5 डॉव, 165, 199) में इस मामले को इस तरह से रखा है।"

न्यायमूर्ति कोलरिज की इस टिप्पणी पर अवलम्ब लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक गलत धारणा के कारण है। न्यायमूर्ति कोलरिज ने पृष्ठ 427 पर स्पष्ट रूप से उन सभी बातों की पुष्टि की है जो उन्होंने और स्टॉकडेल बनाम हंसर्ड में अन्य न्यायाधीशों द्वारा कही गई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, उन्होंने वहां कहा था कि "वास्तव में, सदन एक न्यायालय नहीं है।" इसलिए जब उन्होंने कहा कि सामान्य रूप में न्याय करने का अधिकार विशेषाधिकार पर आधारित नहीं है, तो उनका जो भी आशय रहा हो, उनका मतलब यह नहीं था कि यह सदन के न्यायालय होने पर आधारित है। मैं समझता हूँ कि उनका आशय यह था कि यह एक अधिकार था जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स को अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने के लिए धारण करना था, और इसलिए यह कोई ऐसा अधिकार नहीं था जिसे सम्मान और आदर के संकेत के रूप में प्रदान किया गया हो। उनका यह भी अभिप्राय हो सकता है कि यह शक्ति सदन के लिए विशिष्ट नहीं थी, क्योंकि न्यायालयों के पास भी सुविधा के उसी कारण से यह शक्ति थी, और इसलिए यह कोई विशेषाधिकार नहीं था, एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग इस अर्थ में किया गया है कि संसद के पास ऐसी कोई शक्ति है जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास मौजूद शक्तियों से अधिक है: मे 42।

फिर हावर्ड बनाम गॉसेट का मामला आता है। अपील में कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चौबर के फैसले का संदर्भ देना पर्याप्त होगा जो पृष्ठ 158 से प्रारम्भ होता है। यह निर्णय पार्क बी. ने दिया था, जिन्होंने पृष्ठ 171 पर टिप्पणी की थी:

"हमारे विचार में स्पीकर का वारंट वैध है, ताकि सदन के अधिकारी को संरक्षण मिल सके, एक सिद्धांत पर जो, जैसा कि यह प्रत्येक सुपीरियर कोर्ट की प्रक्रिया और अधिकारियों पर लागू होता है, निश्चित रूप से संसद के उच्च न्यायालय और उसकी प्रत्येक शाखा पर भी लागू होना चाहिए।"

यहां भी सदन को उच्च न्यायालय के समान सम्मान का हकदार माना गया है, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि सदन उच्च न्यायालय है।

अंत में, मैं ब्रैडलाफ बनाम गॉसेट मामले पर आता हूं, जिसके पृष्ठ 285 पर न्यायमूर्ति स्टीफन ने कहा है। "हाउस ऑफ कॉमन्स न्याय का न्यायालय नहीं है।" मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इन अधिकारियों के बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने की शक्ति है, क्योंकि यह एक उच्च न्यायालय है।

तब यह कहा गया था कि भले ही सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने का अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के पास नहीं था क्योंकि यह उच्च न्यायालय था, इस विषय पर मामलों में अवलोकन, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह स्थापित करने कि यह अधिकार न्यायालयों की विनम्रता के कुछ नियम, या अनुमानित साक्ष्य या कानून की अदालतों और सदन के बीच एक समझौते से या अंत में पूर्व द्वारा उत्तराधिकार को दी गई कुछ रियायत से उत्पन्न होता है। मैं तुरंत देखता हूं कि ये मामले इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं और किसी भी पाठ्यपुस्तक ने ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया है या यह अधिकार एक विशेषाधिकार के अलावा कुछ भी नहीं है। यह तर्क मुझे स्पष्ट रूप से भ्रामक लगता है और हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार की मूल प्रकृति को नजरअंदाज करता है। मैंने पहले विशेषाधिकार की प्रकृति बताई है लेकिन मैं इसे यहां दोहराऊंगा। हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकार कानून पर आधारित हैं। उस कानून को लेक्स पार्लियामेंटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए विशेषाधिकार वे मामले हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास अधिकार के रूप में हैं। स्टॉकडेल बनाम हंसर्ड में सभी न्यायाधीशों ने माना कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार लेक्स पार्लियामेंटी पर आधारित हैं और किसी भी अन्य कानून की तरह कानून भी देश का कानून है जिसे लागू करने का अधिकार अदालतों को है।

अब अगर किसी सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने का विशेषाधिकार कानून में लागू करने योग्य अधिकार है जो हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित है, तो यह न्यायालयों के नियम द्वारा नियंत्रित मामला नहीं हो सकता। न्यायालयों की विनम्रता केवल एक स्व-आरोपित संयम है। यह कुछ ऐसा है जिसे न्यायालय स्वयं नहीं करना चाहता। यह वास्तव में कानून का नियम नहीं है। यह कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनाता है। विशेषाधिकार का १अधिकार१ इस पर आधारित नहीं हो सकता। इसके अलावा न्यायालयों की सौहार्दता का कोई सवाल ही नहीं है जब तक कि दो न्यायालय न हों, जिनमें से प्रत्येक दूसरे को शिष्टता या विचार प्रदान करता हो। यहाँ हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स और कानून की अदालतें हैं। पहला न्यायालय नहीं है और दूसरे को अपने उचित कामकाज के लिए सदन से किसी शिष्टता या विचार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ न्यायालयों की सौहार्दता के किसी सिद्धांत को लागू करने का कोई स्थान नहीं है।

इसके बाद विशेषाधिकार के बारे में कहा गया कि यह वास्तव में एक अनुमान के नियम से अधिक कुछ नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सामान्य वारंट किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से कैद करता है, ताकि दण्ड की वैधता के सवाल की जांच कानून की अदालत द्वारा न की जाए, मुझे लगता है कि यह एक अनुमान है जिसे कानून द्वारा बनाया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है, तो सदन का अधिकार संबंधित न्यायाधीश की सहूलियत पर निर्भर करेगा और इसलिए, कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, न ही ऐसा कहा गया है कि ऐसा है। फिर क्या? अगर यह कानून की धारणा है, तो वह कानून कौन सा है जिस पर यह धारणा आधारित है? किसी ने भी इस ओर इशारा नहीं किया है और जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा कोई कानून नहीं है जब तक कि यह लेक्स पार्लियामेंटी

न हो। एक बार ऐसा कहने के बाद, यह वास्तव में विशेषाधिकार का मामला बन जाता है क्योंकि लेक्स पार्लियामेंटी विशेषाधिकार स्थापित करने के अलावा धारणा नहीं बनाएगा। लेक्स पार्लियामेंटी द्वारा बनाया गया अधिकार एक विशेषाधिकार है। यह मैंने पहले विशेषाधिकारों की प्रकृति पर चर्चा करते हुए कहा है।

अंत में, क्या अधिकार की उत्पत्ति हाउस ऑफ कॉमन्स और कानून की अदालतों के बीच समझौते में हुई है, या बाद में पूर्व की ओर से दी गई रियायत में? यह एक नया तर्क है। मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता है जहाँ कोई अधिकार, और इसलिए, जिस कानून पर वह आधारित है, अदालतों के साथ समझौते द्वारा बनाया गया हो। न्यायालय कानून बिल्कुल नहीं बनाते, कम से कम सहमति से तो नहीं; वे उन्हें सुनिश्चित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। इसी कारण से, न्यायालय रियायत देकर कानून नहीं बना सकते। न्यायालय को कानून के किसी प्रश्न को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कानून पहले से मौजूद न हो। मुझे यह कल्पना करना असंभव लगता है कि कोई भी संसदीय विशेषाधिकार जो लागू करने योग्य अधिकार बनाता है, न्यायालयों के साथ समझौते या उनके द्वारा दी गई रियायत से अस्तित्व में लाया जा सकता है।

वर्तमान विषय के समापन से पहले मैं यह कहने की स्वतंत्रता लेता हूँ कि हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के बारे में नए विचार शुरू करना हमारे लिए नहीं है, ऐसे विचार जिनकी इंग्लैंड में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। हमारा काम अपने शोधों के जरिए विशेषाधिकारों के बारे में कोई नवीनता शुरू करना नहीं है। इन नवीन विचारों को अंग्रेजी मामलों के निर्णयों में की गई विविध टिप्पणियों पर आधारित करना असुरक्षित होगा, क्योंकि वे संदर्भ से परे हैं और जिस उद्देश्य के लिए वे बनाए गए थे, उसकी उपेक्षा करते हैं। मैंने इन मामलों से जो कुछ उद्धृत किया है, उससे कम से कम एक व्यक्ति रुककर यह सोचेगा कि ये मामले हाउस ऑफ कॉमन्स के सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के अधिकार के बारे में किसी नए सिद्धांत के लिए कोई निश्चित आधार प्रदान नहीं कर सकते। पुराने अंग्रेजी इतिहास पर शोध वर्तमान संदर्भ में पूरी तरह से अनुपयुक्त है और इससे भी अधिक, भ्रांतियों को जन्म देने की संभावना है। पुरावशेषों पर शोध के आधार पर विशेषाधिकारों के बारे में अपने निष्कर्ष निकालना, एक गलत प्रक्रिया होगी, क्योंकि प्रश्न यह है कि 1950 में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों को क्या माना गया था। जिस समय ये विशेषाधिकार आकार ले रहे थे, उस अवधि के बारे में शोध करने से 1950 में उनकी विषय-वस्तु और प्रकृति के बारे में कोई उत्तर नहीं मिल सकता। इस प्रश्न का उत्तर केवल यह पता लगाकर दिया जा सकता है कि क्या 1950 से पहले के वर्षों में इंग्लैंड में आधिकारिक राय द्वारा चर्चा के अंतर्गत अधिकार को हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार के रूप में माना जाता था।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करने का अधिकार जिसके परिणामस्वरूप उस दण्ड की जांच करने के लिए कानून की अदालतों के क्षेत्राधिकार से वंचित होना हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार है। मेरे विचार में, यह विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 194(3) के कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास है।

फिर कहा गया कि विधानसभा के उस विशेषाधिकार का प्रयोग संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिक के मौलिक अधिकारों के अधीन ही किया जा सकता है। यह मुझे शर्मा के मामले की ओर ले जाता है। जैसा कि मैंने उस मामले में बहुमत के निर्णय को पढ़ा, मुझे विचार में वे यह मानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 194(3) द्वारा राज्य विधानसभा के सदनों को प्रदान किए गए थे, मौलिक अधिकारों पर वरीयता लेते हैं। तथ्य ये थे। बिहार विधानसभा के एक सदन ने अनुच्छेद 194(3) के तहत अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपनी कार्यवाही के कुछ हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने अपने अखबार में कार्यवाही का पूरा विवरण प्रकाशित किया, जिसमें हटाए गए हिस्से भी शामिल थे। इसके बाद सदन द्वारा उसे नोटिस जारी किया गया कि वह कारण बताए कि सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कदम क्यों न उठाए जाएं। उस मामले में दावा किया गया विशेषाधिकार इसकी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार था। इसके बाद याचिकाकर्ता, अखबार के संपादक ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि विशेषाधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार को नियंत्रित नहीं करता है, और इसलिए सदन को उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी विवाद किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास वह विशेषाधिकार है जिसका दावा बिहार विधानसभा ने किया है। बहुमत ने माना कि सदन के पास अपनी

कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का विशेषाधिकार है और यह विशेषाधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिक के मौलिक अधिकार के अधीन नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और अवधारित किया कि मौलिक अधिकार विशेषाधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा सदन को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का विशेषाधिकार नहीं है। वर्तमान मामले में हम बाद वाले प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। परिणामस्वरूप शर्मा मामले की याचिका खारिज कर दी गई।

इस मामले के संबंध में उच्च न्यायालय की ओर से दो बिंदु उठाए गए हैं। पहले कहा गया कि बहुमत के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और फिर कहा गया कि किसी भी स्थिति में, उस निर्णय में केवल यह कहा गया है कि वहां दावा किया गया विशेषाधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर वरीयता प्राप्त करता है, न कि यह कि कोई अन्य विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त करता है। मैं इनमें से किसी भी तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

विधानसभा की ओर से यह बताया गया है कि अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ में हमारे पास इस न्यायालय के पहले के फैसले को अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें कानून के आधार पर संदर्भित प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इस न्यायालय का निर्णय जब तक वह मौजूद है, तब तक निश्चित रूप से कानून निर्धारित करता है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि यह तर्क निरर्थक है। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि दिल्ली विधि अधिनियम के मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या संघीय न्यायालय का निर्णय सही था, जिसे हमारे संविधान के तहत हमारे निर्णयों के समान ही अधिकार प्राप्त है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह मामला सहायता नहीं करता, क्योंकि प्रस्तुत प्रश्न के लिए ही पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। मैं इस मामले पर आगे चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं रखता, क्योंकि मैं विधानसभा के तर्क के पक्ष में इतना दृढ़ता से महसूस नहीं करता कि मैं इस प्रश्न पर अपने विद्वान भाईयों के विचार से अलग राय रखूं।

हालाँकि, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शर्मा के मामले में बहुमत का फैसला पूरी तरह से सही था जब उसने कहा कि विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं थे। मैंने पहले अनुच्छेद 194 के पहले तीन खंडों को निर्धारित किया है। पहला खंड स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों के अधीन बनाया गया था - चाहे जो भी प्रावधान हों - जबकि तीसरा खंड ऐसा नहीं था। बहुमत और अल्पमत दोनों निर्णय इस बात पर सहमत हैं कि तीसरे खंड को, इसलिए, इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता है जैसे कि इसे स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों के अधीन बनाया गया हो। मैं नहीं समझता कि मेरे लिए इसका कोई अन्य अर्थ संभव है। इस प्रकार अनुच्छेद 194 का खंड (3) स्पष्ट रूप से संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन नहीं है, तो इसके और संविधान के किसी अन्य उपबंध के बीच टकराव का समाधान कैसे किया जा सकता है? बहुमत ने माना कि दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 194(3) एक विशेष प्रावधान होने के कारण अनुच्छेद 19(1)(ए) में उल्लिखित मौलिक अधिकार पर वरीयता लेनी चाहिए जो एक सामान्य प्रावधान था: (पृष्ठ 860)। यद्यपि न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 194(3) के बीच कोई अंतर्निहित असंगति नहीं है, फिर भी उन्होंने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू किया। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि विधायिका के पास व्यापक शक्तियां और विशेषाधिकार हैं और उन विशेषाधिकारों का प्रयोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना किया जा सकता है, इसलिए विशेषाधिकार को मौलिक अधिकार के अधीन कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस निर्माण ने दोनों अनुच्छेदों को पूर्ण प्रभाव दिया: (पृष्ठ 880-1)। विद्वान न्यायाधीश के प्रति अत्यन्त सम्मान रखते हुए, मुझे यह समझना मुश्किल लगता है कि इस व्याख्या के परिणामस्वरूप दोनों अनुच्छेदों का प्रभाव पड़ा और इस प्रकार एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण प्राप्त हुआ।

स्पष्टतः अनुच्छेद 194(3) और 19(1)(ए) के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वे अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं को इंग्लिश हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जबकि अनुच्छेद 19(1)(ए) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता

होगी। हालांकि, जब हम अनुच्छेद 194(3) के तहत दावा किए गए विशेष विशेषाधिकारों पर विचार करते हैं तो यह संघर्ष सतह पर आ जाता है। जब अनुच्छेद 194(3) कहता है कि राज्य विधानमंडलों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, तो यह वास्तव में उन विशेषाधिकारों को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए, अनुच्छेद 194(3) का उचित अर्थ यह है कि यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडलों को अन्य विशेषाधिकारों के साथ-साथ अपनी किसी भी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। तभी अनुच्छेद 194(3) और 19(1)(ए) के बीच संघर्ष देखा जा सकता है; एक कुछ प्रकाशित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है जबकि दूसरा कहता है कि सभी चीजें प्रकाशित की जा सकती हैं। मेरा मानना है कि शर्मा के मामले में सभी न्यायाधीशों ने इसी तरह से अनुच्छेद पढ़े थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो दोनों प्रावधानों के बीच टकराव या उनमें सामंजस्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अब यदि अनुच्छेद 19(1)(ए) को प्राथमिकता दी जाए तो नागरिक को अपनी पसंद की कोई भी चीज प्रकाशित करने की पूरी स्वतंत्रता है; वह सदन की कार्यवाही को प्रकाशित कर सकता है, भले ही सदन ने उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी हो। हालांकि, इस फैसले का परिणाम अनुच्छेद 194(3) के उस हिस्से को खत्म करना है जिसमें कहा गया था कि राज्य विधानमंडलों को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने की शक्ति और विशेषाधिकार होगा। इसे प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण पाठ नहीं कहा जा सकता, बल्कि ऐसा पाठ जो दोनों प्रावधानों को प्रभावी बनाता है। यह एक ऐसा पाठ है जो एक प्रावधान को प्रभावी बनाता है तथा दूसरे को इस प्रकार मानता है मानो वह अस्तित्व में ही न हो।

यह सच है कि यदि अनुच्छेद 19(1)(ए) लागू होता है, तो यह हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी अन्य विशेषाधिकारों को खत्म नहीं करेगा, जिन्हें अनुच्छेद 194(3) में पढ़ा जाना था। इस प्रकार, सदन का अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का अधिकार बरकरार रहा, भले ही कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अपरिचितों को बाहर रखने के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ और सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम द्वारा दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब किसी प्रावधान का एक भाग ही किसी अन्य प्रावधान के साथ संघर्ष में हो, तो कानून की पुस्तक से संघर्षशील भाग को हटा देने से तथा यह कह देने से कि इस प्रकार दोनों प्रावधान सुसंगत हो गए हैं, दोनों में सामंजस्य नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसे हटाए जाने के बाद भी पहले प्रावधान का शेष भाग तथा दूसरे प्रावधान का पूरा भाग प्रभावी रहता है। हम दो परस्पर विरोधी प्रावधानों को सर्वोत्तम संभव प्रभाव प्रदान करते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए चिंतित हैं, तथा यह कार्य कानून से परस्पर विरोधी भाग को हटाकर जटिल समस्या को सुलझाने से नहीं किया जा सकता।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि अनुच्छेद 194(3) और अनुच्छेद 19(1)(ए) के बीच संघर्ष, जो पूर्व के बताए गए तरीके से उत्पन्न होता है, को देखते हुए इसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा हल किया जाना चाहिए। जहां तक मैं सिद्धांत को समझता हूँ, वह यह है। जब यहां विधानसभा ने दोनों प्रावधानों को अधिनियमित किया तो संविधान निर्माताओं का इरादा दोनों को प्रभावी बनाने का था। यदि संयोग से ऐसा होता है कि दोनों का पूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता है, तो विधानसभा की मंशा प्रावधानों को वह व्याख्या देकर पूरी होगी जिससे दोनों को सबसे अधिक प्रभावकारिता मिले। मेरा मानना है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के पीछे यही सिद्धांत है। शर्मा के मामले में उस नियम को लागू करते हुए, यदि विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 194(3) के तहत कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए दावा किया गया विशेषाधिकार पूर्ण रूप से प्रभावी होता, तो अनुच्छेद 19(1)(ए) संविधान से पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, अंतिम उल्लेखित अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य मामलों के संबंध में लागू रहती। इसके विपरीत यदि अनुच्छेद 19(1)(ए) को पूर्ण प्रभाव देना था, अर्थात् नागरिक को अपनी इच्छानुसार कुछ भी कहने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी, तो अनुच्छेद 194(3) का वह भाग जो कहता है कि सदन अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा सकता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे इसे संविधान में कभी रखा ही नहीं गया था। मेरे विचार से, संविधान की यह व्याख्या शायद ही कभी की गई हो या उचित हो। इन कारणों से मैं कहूंगा

कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम शर्मा के मामले में बहुमत द्वारा की गई व्याख्या का समर्थन करता है।

न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने एक और कारण बताया कि उन्होंने क्यों विचार किया कि मौलिक अधिकारों को विधायिका के विशेषाधिकारों पर वरीयता दी जानी चाहिए और इस पर भी उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में अवलम्ब लिया। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि अनुच्छेद 194(3) का वह भाग जिसके अंतर्गत राज्य विधानसभा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के समान विशेषाधिकार का दावा करता है, जिसे इस खंड का दूसरा भाग कहा गया है, स्पष्ट रूप से एक अस्थायी प्रावधान था क्योंकि यह तब तक प्रभावी था जब तक विधानसभा संविधान निर्माताओं द्वारा इच्छित विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला कानून नहीं बना देता। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा ऐसा कानून बनाएगा तो वह मौलिक अधिकारों के अधीन होगा और यह अजीब होगा कि जो प्रावधान अस्थायी है उन्हें उन अधिकारों से मुक्त समझा जाए। शर्मा के मामले में बहुमत ने बिना किसी चर्चा के निःसंदेह कहा कि अनुच्छेद 194(3) के तहत बनाया गया कानून सभी मौलिक अधिकारों के अधीन होगा। हालांकि विधानसभा के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने तर्क दिया कि यह दृष्टिकोण उचित नहीं था। वर्तमान मामले में मुझे लगता है कि जो भी दृष्टिकोण लिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि विधानसभा द्वारा अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला बनाया गया कानून मौलिक अधिकारों के अधीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा केवल इसलिए होगा क्योंकि अनुच्छेद 13 ऐसा कहता है। वास्तव में अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत बनाए गए कानून को मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं पढ़ा जाना चाहिए; स्थिति यह है कि यदि वह कानून किसी मौलिक अधिकार के विपरीत है, तो वह कानून बन ही नहीं सकता है। यह अनुच्छेद 13 का प्रभाव है। इसलिए यह तर्क कि चूंकि अनुच्छेद 194(3) के तहत बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों के अधीन है, इसलिए खंड (3) के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार भी मौलिक अधिकारों के अधीन होने चाहिए, गलत धारणा पर आधारित है। अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करता है तो वह कानून गलत माना जाता है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि चूंकि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 194 के खंड (3) के तहत बनाए गए कानूनों को शून्य बना सकता है, इसलिए उस खंड के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार भी शून्य होने चाहिए। अनुच्छेद 13 संविधान के किसी प्रावधान पर लागू नहीं होता। यह केवल राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को नियंत्रित करता है, जो अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों माना जाना चाहिए कि यदि विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला कोई कानून बनाया जाता है तो वह मौलिक अधिकारों के साथ टकराव होने पर अमान्य हो जाएगा, अनुच्छेद 194(3) में सम्मिलित विशेषाधिकारों के संबंध में, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग को इसी प्रकार पढ़ा जाना चाहिए-इसका भी मूल अधिकारों के अधीन होने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसा आशय था, तो खंड (3) इस प्रावधान के साथ प्रारम्भ होता कि यह संविधान के अधीन होगा। तथ्य यह है कि खंड (1) में "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" शब्द आते हैं जबकि उन्हें खंड (3) से हटा दिया गया है, यह एक मजबूत संकेत है कि बाद वाले खंड को इस तरह के अधीन होने का इरादा नहीं था। इसके अलावा, यह आशय नहीं हो सकता था क्योंकि तब वह विशेषाधिकार, जिससे वर्तमान मामला संबंधित है, अर्थात्, न्यायालय की समीक्षा के अधीन आए बिना सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करना, संविधान से समाप्त हो जाएगा क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्रता के प्रत्येक वंचन की वैधता की न्यायालय में जांच की जा सके।

यह भी कहा गया कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। यदि वे सर्वोपरि हैं तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि संविधान ने उन्हें ऐसा बनाया है। संविधान, निःसंदेह अनुच्छेद 13 के द्वारा विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के अधीन बनाता है, लेकिन मैं नहीं जानता, और न ही हमें यह बताया गया है कि संविधान किस अन्य तरीके से मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि बनाता है। हमें संविधान में

ऐसी बातें पढ़ने का अधिकार नहीं है जो उसमें हैं ही नहीं। हम निश्चित रूप से यह कहने के हकदार नहीं हैं कि संविधान में किसी विशिष्ट प्रावधान का केवल इसलिए कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वह मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करता है, या क्योंकि मौलिक अधिकार, यद्यपि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है, अपनी प्रकृति से ही सर्वोपरि हैं।

फिर जहां तक अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग के क्षणिक होने का प्रश्न है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी। इसमें कोई

संदेह नहीं कि जब विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 194(3) के प्रथम भाग के अधीन कानून बनाया गया था, तो उस उपबंध के उत्तरार्द्ध भाग के अधीन हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार समाप्त हो गए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दूसरा भाग क्षणिक था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी कि विधानसभा अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला अपना कानून बनाए। जब संविधान निर्माताओं ने 1950 में संविधान का निर्माण किया था, तो उनके सामने ऑस्ट्रेलियाई संविधान अधिनियम, 1901 के कमोबेश समान प्रावधान थे और वे जानते थे कि पचास वर्षों के दौरान ऑस्ट्रेलिया में विधानमंडलों के सदनों के विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले कानून नहीं बनाए गए थे, लेकिन सदनों ने अपने संविधान द्वारा उन्हें दिए गए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के साथ काम करना जारी रखा था। उनके सामने इस उदाहरण को देखते हुए मेरे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारे संविधान में इसी प्रकार का प्रावधान किया था, तो वे चाहते थे कि हमारे विधानमंडलों को अपने स्वयं के विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले कानून बनाने चाहिए और अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग द्वारा उन्हें दिए गए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों से छुटकारा पाना चाहिए। मैं यह कहना भी सही समझता हूँ कि भले ही अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षणिक हों, लेकिन इससे यह औचित्य सिद्ध नहीं होगा कि इसका परिणाम यह होगा कि संविधान से इसके एक भाग को हटा दिया जाएगा।

इस स्तर पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि गणपति केशव राम रेडी बनाम नफीसुल हसन मामले में उनकी अदालत ने माना कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेषाधिकार हनन के लिए अध्यक्ष के आदेश के तहत किसी नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना गिरफ्तार करना वहां वर्णित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। रेडी के मामले में लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है। यद्यपि न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इस बात को देखा था, फिर भी वे इससे बंधे हुए महसूस करते थे। बहुमत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां निर्णय अधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत पर आधारित था। इस न्यायालय में उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पहले के मामले में कोई रियायत नहीं दी गई थी। मैंने देखा है कि शर्मा मामले में बहुमत का फैसला देने वाले मुख्य न्यायाधीश दास रेडी मामले पर निर्णय देने वाली पीठ के सदस्य थे। यदि रेडी के मामले में निर्णय रियायत के आधार पर नहीं था, कम से कम इस अर्थ में कि विद्वान अधिवक्ता इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थ थे कि विशेषाधिकार मौलिक अधिकार से ऊपर है, तो यह आश्चर्यजनक होगा कि इस बिंदु पर निर्णय में चर्चा नहीं की गई। हालाँकि यह सब इस तथ्य के मद्देनजर हो सकता है कि रेडी मामले में दिए गए निर्णय से ऐसा नहीं लगता है कि अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग ने विशेषाधिकारों का सृजन किया है जो मौलिक अधिकारों पर वरीयता लेते हैं, क्योंकि निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है, मेरे लिए रेडी मामले का पालन न करने में कोई कठिनाई नहीं है, विशेषकर जब शर्मा मामले में बहुमत ने इसका पालन नहीं किया।

यह भी कहा गया कि विशेषाधिकारों का उद्देश्य केवल विधानमंडलों को सुचारु रूप से और बिना किसी बाधा के कार्य करने देना है। यह बताया गया कि विधानमंडलों का मुख्य कार्य कानून बनाना है और विशेषाधिकारों का उद्देश्य उस कार्य के समुचित निर्वहन में सहायता करना है। यह तर्क दिया गया कि यदि विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून, जिसके निर्माण के लिए वह मुख्य रूप से अस्तित्व में है, मौलिक अधिकारों के अधीन हैं, तो यह आश्चर्यजनक है कि जो कुछ उस प्राथमिक कार्य के लिए सहायक है, वह उनसे मुक्त हो। मुझे इसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगता। विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों के अधीन हैं क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। विशेषाधिकार इसके अधीन नहीं हैं क्योंकि वे संविधान द्वारा ही प्रदान किए गए हैं और न तो उन्हें इसके अधीन बनाया गया है और न ही उचित व्याख्या के आधार पर ऐसा पाया गया है।

मेरा मानना है कि मैंने अब उन सभी कारणों पर चर्चा कर ली है जो इस दृष्टिकोण के समर्थन में दिए गए हैं कि शर्मा के मामले में बहुमत का निर्णय गलत था। जैसा कि मैंने कहा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये कारण सही हैं।

आर.के. करंजिया बनाम माननीय श्री एम अनंतशयनम अयंगर, स्पीकर, लोक सभा (डब्ल्यू.पी. संख्या 221/1961 अप्रतिवेद्य) मामले में, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका थी, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ से शर्मा मामले में बहुमत के फैसले की सत्यता पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसने उस फैसले को सही माना और याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह इस बात को मानने का एक और कारण है कि शर्मा मामले में सही तरीके से निर्णय लिया गया था।

अब मैं शर्मा के मामले से संबंधित दूसरे तर्क पर आता हूँ। यह कहा गया कि उस मामले में बहुमत के निर्णय में केवल इतना कहा गया था कि अनुच्छेद 194 के खंड (3) के दूसरे भाग द्वारा विधानसभा को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का जो विशेषाधिकार दिया गया था, वह अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अधीन नहीं था। यह बताया गया कि उस मामले में यह नहीं कहा गया था कि अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग के तहत सभी विशेषाधिकार सभी मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त होंगे। इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश दास ने उस मामले में प्रस्तुत तर्क पर विचार किया कि सदन द्वारा अवमानना के लिए विशेषाधिकार का प्रयोग करने से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगी, क्योंकि गिरफ्तारी और हिरासत अनुच्छेद 208 के तहत सदन द्वारा तैयार प्रक्रिया के नियमों के अनुसार होगी। यह तर्क दिया गया कि इसलिए बहुमत ने माना कि अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार, दण्डित करने के विशेषाधिकार पर वरीयता लेगा।

यह तर्क भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शर्मा का मामला अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग के तहत सदन को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने के विशेषाधिकार के बीच टकराव से संबंधित था और इसलिए, अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना अनावश्यक था। हालाँकि, जिस कारण से बहुमत ने यह माना कि दोनों के बीच संघर्ष को विशेषाधिकार को प्राथमिकता देकर हल किया जाना चाहिए, वह कई अन्य विशेषाधिकारों और कई अन्य मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष के मामले में उपलब्ध होगा। अब वह कारण यह था कि संघर्ष को हल करने के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करना होगा और इसका परिणाम यह होगा कि मौलिक अधिकार, जो अपनी प्रकृति में सामान्य थे, को उन विशेषाधिकारों के आगे झुकना होगा जो विशेष थे। उस मामले में बहुमत का पूरा निर्णय यह था कि जब अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग द्वारा बनाए गए विशेषाधिकार और मौलिक अधिकार के बीच संघर्ष हो, तो उस संघर्ष को दोनों में सामंजस्य स्थापित करके हल किया जाना चाहिए। यह निर्णय निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा वारंट की वैधता की समीक्षा किए बिना सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए जेल भेजने के विशेषाधिकार और अनुच्छेद 21, 22 और 32 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष पर लागू होगा। बहुमत का निर्णय यह मानने के लिए अधिकार होगा कि संघर्ष को सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा हल किया जाना चाहिए। वास्तव में अल्पमत का भी यही दृष्टिकोण था। अंतर वास्तविक निर्माण के संबंध में था।

मुख्य न्यायाधीश दास ने निःसंदेह कहा कि शर्मा के मामले में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता से वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार था। मेरे विचार से यह केवल एक वैकल्पिक कारण था, क्योंकि वह उसी आधार पर इस मुद्दे पर विचार कर सकते थे जिस आधार पर उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मौलिक अधिकार को सदन के विशेषाधिकार के आगे झुकना होगा, अर्थात् सामंजस्यपूर्ण अर्थ के नियम के आवेदन द्वारा अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाना होगा। वह उसी तर्क से कह सकते थे जो उन्होंने पहले दिया था, कि अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार सामान्य है और सामान्य वारंट द्वारा हिरासत में लेने का विशेषाधिकार एक विशेष प्रावधान है और इसलिए इसे लागू होना चाहिए। मैं यह मानने में असमर्थ हूँ कि अनुच्छेद

21 पर आधारित तर्क पर जिस तरह से उन्होंने विचार किया, उससे मुख्य न्यायाधीश दास ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, सामान्य वारंट द्वारा समर्पण के विशेषाधिकार पर वरीयता लेता है, जो विधानसभा के पास अनुच्छेद 194 के खंड (3) के दूसरे भाग के तहत है। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो फिर कोई कारण नहीं था कि वे यह मानते कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सदन की कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने के विशेषाधिकार के आगे झुकना चाहिए। यह कहने का एक और कारण कि मुख्य न्यायाधीश दास ने

यह नहीं माना कि अनुच्छेद 21 सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करने के विशेषाधिकार पर वरीयता लेता है, यह तथ्य है कि उन्होंने माना कि रेडी के मामले में गलत निर्णय लिया गया था। उस मामले में यह अवधारित किया गया था कि अनुच्छेद 22 को दण्ड के विशेषाधिकार पर वरीयता प्राप्त है। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश दास ने माना होगा, यदि अनुच्छेद 22 को वरीयता नहीं प्राप्त थी, क्योंकि उन्होंने रेडी के मामले की सत्यता को स्वीकार नहीं किया था, तो वे यह नहीं कह सकते थे कि अनुच्छेद 21 को अवमानना के लिए दण्डित करने के विशेषाधिकार पर वरीयता प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 194 के खंड (1) और (2) का कुछ संदर्भ यह दिखाने के लिए दिया गया था कि शर्मा के मामले में निर्णय लिया गया था कि अनुच्छेद 19(1)(ए) को ही अनुच्छेद 194 के खंड (3) के दूसरे भाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार के अधीन होना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शर्मा के मामले में बहुमत का निर्णय उन खंडों पर आधारित था। यह स्मरणीय है कि ये धाराएं सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित थीं। मुख्य न्यायाधीश दास ने इनका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि इन धाराओं के आधार पर कुछ तर्क दिए गए थे, जिनका उल्लेख करना अब अनावश्यक है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि ये विशेषाधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अधीन हैं। अल्पमत और बहुमत दोनों ही निर्णय इन तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ रहे। वास्तव में, उस मामले में प्रश्न सदन के बाहर किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की शक्ति से संबंधित था और खंड (1) और (2) केवल सदन में किसी सदस्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हैं और ऐसी स्वतंत्रता से उस मामले का कोई संबंध नहीं था।

इस न्यायालय में अनुच्छेद 194 के खंड (1) में संविधान के उपबंधों के अधीन शब्दों के अर्थ के संबंध में कुछ चर्चा हुई। मेरे विचार में, ये शब्द केवल संविधान के उन प्रावधानों को संदर्भित कर सकते हैं जो सदन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, अन्यथा खंड (1) और (2) एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। अब मैं विषयांतर करते हुए कहना चाहूंगा कि विधानसभा के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अनुच्छेद 194 में संविधान निर्माताओं ने सदस्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अलग तरीके से समझा, इसके लिए खंड (1) और (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया और खंड (3) में अन्य विशेषाधिकारों, अर्थात् सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा अन्य विशेषाधिकारों का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि यदि सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खंड (3) द्वारा प्रदत्त की गई है तो यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नियंत्रित होगी और तब सत्ता में बैठी पार्टी संभवतः उस स्वतंत्रता को नष्ट कर सकती है। आशय यह था कि सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा ही दी जानी चाहिए ताकि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से उस पर कोई आंच न आए। मैं समझता हूं कि यही एकमात्र कारण है कि संविधान में अनुच्छेद 194 के खंड (1) और (2) में स्वतंत्रता को अलग से माना गया है। इसलिए उन धाराओं का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। न ही शर्मा मामले में लिए गए फैसले से उनका कोई संबंध है। परिणाम यह है कि मेरे निर्णय में शर्मा का मामला वर्तमान मामले को संदर्भित करता है और इसे इससे अलग नहीं किया जा सकता है।

पहले बताए गए कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग द्वारा सदन को प्रदान किए गए विशेषाधिकार और मौलिक अधिकार के बीच संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष को दोनों प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करके हल किया जाना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि मौलिक अधिकारों को विशेषाधिकार पर सिर्फ इसलिए वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि यह मौलिक अधिकार है या किसी अन्य कारण से ऐसा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में संघर्ष सदन के उस विशेषाधिकार के बीच है जिसके तहत वह किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए दोषी ठहरा सकता है, जबकि उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जांचे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तथा अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत उस अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार के बीच संघर्ष है। यदि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन में न्यायालयों में जाने के अधिकार को वरीयता दी जाती है, तो वह विशेषाधिकार जो यह उपबंध करता है कि यदि सदन किसी व्यक्ति को सामान्य वारंट द्वारा दण्डित करता है तो उस दण्ड की न्यायालयों द्वारा समीक्षा नहीं की

जाएगी, अपना संपूर्ण प्रभाव खो देगा और यह ऐसा होगा मानो अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग द्वारा सदन को वह विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया हो। मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने पर, इसका अर्थ यह होगा कि जब सदन किसी व्यक्ति को सामान्य वारंट द्वारा अवमानना के लिए दण्डित करता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही न्यायालय ऐसे आदेश पर निर्णय दे सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि नियम में अपवाद नहीं हो सकते, लेकिन मैं वर्तमान मामले में इन अपवादों, यदि कोई हों, पर चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं रखता। उन अपवादों के अस्तित्व को बर्देत बनाम एबॉट मामले में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलेनबोरो की टिप्पणियों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। मैंने पृष्ठ 159 पर मामले को इस प्रकार रखा है: "मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलेनबोरो ने इस संभावना को स्वतंत्र छोड़ दिया कि ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें अदालतों को अवमानना के लिए दण्ड की वैधता पर निर्णय लेना होगा, जहां रिटर्न में दिखाए गए तथ्यों को किसी भी उचित व्याख्या द्वारा अवमानना के रूप में नहीं माना जा सकता है"।

मैं समझता हूं कि मैंने अब इस विषय पर कानून पर पर्याप्त चर्चा कर ली है तथा अब मैं संदर्भ क्रम में उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आगे बढ़ सकता हूं।

प्रश्न संख्या 1- क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति एन.यू. बेग और माननीय न्यायमूर्ति जी.डी. सहगल शामिल थे, श्री केशव सिंह की याचिका पर विचार करने और उस पर कार्यवाई करने और श्री केशव सिंह को उनकी याचिका के निस्तारण होने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने के लिए सक्षम थी, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा अवमानना और उसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उन पर लगाए गए कारावास की सजा की वैधता को चुनौती दी गई थी।

मेरी राय में इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। लखनऊ पीठ निश्चित रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर विचार करने में सक्षम थी। विधानसभा द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा यह है कि जब शिकायत की गई, निरुद्धि अध्यक्ष द्वारा जारी सामान्य वारंट के तहत हो तो ऐसी याचिकाओं पर विचार करने का उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन लखनऊ बेंच को यह पता लगाना था कि क्या केशव सिंह की निरुद्धि ऐसे किसी वारंट के तहत थी, इससे पहले कि वह क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर याचिका को खारिज कर सके। याचिका में यह नहीं दिखाया गया कि निरुद्धि किसी सामान्य वारंट के तहत थी। यह स्थिति तब आती जब विधानसभा अध्यक्ष और जेलर जो याचिका के प्रत्यर्थी थे, वापस लौटते। वह स्थिति तब नहीं आई जब लखनऊ पीठ ने याचिका पर विचार किया और उस पर आदेश दिया। जब तक लखनऊ बेंच को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया कि जिस व्यक्ति की निरुद्धि की शिकायत की गई है, वह सामान्य वारंट के तहत है, तब तक उसके पास याचिका पर विचार करने और उस पर आदेश देने का पूरा अधिकार था। यह कहा गया कि जमानत का आदेश अवैध है, क्योंकि कानून में अवमानना के लिए कारावास की स्थिति में जमानत पर रिहाई की अनुमति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह कानून के उस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त अवसर है, क्योंकि यदि जमानत का आदेश कानून में न्यायोचित नहीं भी हो, तो भी इससे अन्यथा आदेश देने की पीठ की क्षमता प्रभावित नहीं होगी। मैं नहीं मानता कि इस संदर्भ का उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, जहां कारावास अवमानना के लिए है, कानून जमानत पर रिहाई की अनुमति देता है।

प्रश्न संख्या 2- क्या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर श्री केशव सिंह ने अपनी ओर से उक्त याचिका उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करवाकर, श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता द्वारा उक्त याचिका प्रस्तुत करके तथा उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों द्वारा उक्त याचिका पर विचार करके तथा उस पर कार्यवाही करके तथा उक्त याचिका के निस्तारण तक श्री केशव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर उत्तर प्रदेश विधान सभा की अवमानना की है।

पहली बात जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि यह प्रश्न कि क्या विधानसभा की अवमानना हुई है, इसका निर्णय विधानसभा को करना है। यदि उस निर्धारण में

तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो न्यायालय उसकी वैधता की समीक्षा नहीं कर सकते। यह टिप्पणी करने के बाद, मैं इस प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ।

इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी कृत्य को अवमानना मानने के लिए, उसे न केवल अवैध होना चाहिए, बल्कि जानबूझकर अवैध भी होना चाहिए। अब वर्तमान मामले में ऐसा नहीं लगता कि उल्लेखित व्यक्तियों में से किसी को भी इस बात का ज्ञान था कि कारावास सामान्य वारंट के तहत था। ऐसा होने पर, मेरे पास यह कहने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिका प्रस्तुत करना अवैध कार्य था, और यह जानबूझकर अवैध कार्य तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए, माननीय न्यायाधीशों या बी. सोलोमन या केशव सिंह द्वारा याचिका के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए संबंधित कदमों के लिए कोई अवमानना नहीं की गई।

प्रश्न संख्या 3- क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा इस बात के लिए यह सक्षम थी कि वह उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों और श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता को हिरासत में अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दे या अपनी अवमानना के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगे।

स्मरण रहे कि, उक्त विवरण के अनुसार, 21 मार्च 1964 के प्रस्ताव में माननीय न्यायाधीशों को हिरासत में लेकर पेश करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने केशव सिंह की याचिका दिनांक 19 मार्च, 1964 के संबंध में जो कुछ किया, उससे उन्होंने सदन की अवमानना की थी और विधानसभा इस बात पर विवाद करती है कि प्रस्ताव में ऐसा प्रावधान किया गया था। हालाँकि, हमें संदर्भ क्रम में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है और हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि सही तथ्य क्या हैं। एक बात तो यह है कि विधानसभा के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह माननीय न्यायाधीशों और बी. सोलोमन को सुनवाई का अवसर दिए बिना अवमानना का दोषी ठहराए। ऐसी स्थिति में, विधानसभा को उन्हें हिरासत में पेश करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं था। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में विधानसभा ने माननीय न्यायाधीशों को अवमानना के प्रश्न पर सुनवाई के लिए नहीं, बल्कि इस आधार पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था कि उन्होंने अवमानना की है। इसलिए सदन के विशेषाधिकार के प्रश्न पर चर्चा करना अनावश्यक है कि "अवमानना के आरोपों का उत्तर देने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को बार में लाया जाए"। देखें मे पृष्ठ 94। इसके अलावा, सभा ने न्यायाधीशों, सोलोमन और केशव सिंह को हिरासत में लेने के अपने प्रस्ताव को संशोधित कर दिया था और माननीय न्यायाधीशों और बी. सोलोमन से उनके आचरण के लिए केवल स्पष्टीकरण मांगा था। इसलिए, दृढ़ता से कहा जाए तो मामले के तथ्यों के आधार पर उन्हें हिरासत में सदन के समक्ष लाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक दोनों न्यायाधीशों और बी. सोलोमन से स्पष्टीकरण मांगने की विधानसभा की क्षमता का प्रश्न है, मेरा मानना है कि उसे इसकी आवश्यकता थी। यह सदन के विशेषाधिकारों में से एक है। चूंकि इसमें अवमानना करने की शक्ति है, इसलिए इसमें अवमानना से संबंधित तथ्यों का पता लगाने की शक्ति भी होनी चाहिए।

प्रश्न संख्या 4- क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ उक्त दोनों माननीय न्यायाधीशों और श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता की याचिकाओं को स्वीकार करने और उस पर विचार करने तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और उक्त याचिकाओं के अन्य प्रत्यर्पण को उक्त विधान सभा के उपरोक्त निर्देश को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने में सक्षम थी।

मैं इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से दूंगा। पूर्ण पीठ के समक्ष दो न्यायाधीशों और बी. सोलोमन की याचिकाएं थी, जिनमें विधानसभा के उस प्रस्ताव के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसमें उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया था। मैंने पूर्व में कहा है कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर उन्हें इतना दोषी नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब यह है कि पूर्ण पीठ के पास अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार था, जो उसने किया।

प्रश्न संख्या 5- क्या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जो विधानसभा के किसी आदेश या निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करता है या विचार करता है,

जिसमें याचिकाकर्ता पर कोई दंड लगाया जाता है या याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी अवमानना या उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन के लिए कोई प्रक्रिया जारी की जाती है या जो ऐसी याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो वह उक्त विधानसभा की अवमानना करता है और क्या उक्त विधानसभा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग और प्रवर्तन में ऐसे न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

यह बहुत सामान्य प्रश्न है और इसका कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता; परिस्थितियों के अनुसार उत्तर भी अलग-अलग होंगे और सभी परिस्थितियों की कल्पना करना संभव नहीं है। न ही मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने के लिए कहा गया है। जैसा कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर इस मामले के तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। उन तथ्यों के आधार पर प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में दिया जाना चाहिए।

अब मैं इस मामले के एक पहलू का उल्लेख करना चाहता हूँ जिस पर बार में काफी बहस हुई थी। यह अवमानना के लिए न्यायाधीश के दायित्व से संबंधित है। यदि मैंने जो पूर्व में कहा वह सही है, तो किसी न्यायाधीश को सामान्य वारंट के तहत सदन द्वारा दिए गए दण्ड में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा कोई आदेश देता है जो ऐसे दण्ड में हस्तक्षेप करता है, तो उसकी कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर होगी। तब यह शून्य हो जाएगी। कोई भी अधिकारी यदि उस आदेश को निष्पादित करता है तो वह सदन द्वारा किए जाने वाले कार्य में हस्तक्षेप करेगा और ऐसा हस्तक्षेप अवैध होगा, क्योंकि वह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है और इसलिए शून्य है। यदि सदन ने उनके विरुद्ध अवमानना का मामला चलाया होता, तो किसी भी स्थिति में न्यायालय उस आदेश के आधार पर उन्हें कोई सहत नहीं दे सकता था। हो सकता है कि ऐसा आदेश देकर न्यायाधीश सदन की अवमानना कर रहे हों, क्योंकि ऐसा करके वे सदन के आदेश में अवैध रूप से तथा पूर्णतः क्षेत्राधिकार के बिना हस्तक्षेप कर रहे होंगे। हालाँकि, अब मैं जिस प्रश्न की ओर संकेत करना चाहता हूँ वह यह है कि यह मानते हुए कि उसने अवमानना की है तो क्या न्यायाधीश को सदन द्वारा इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधीश को उसके द्वारा की गई अवमानना के लिए सदन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध उन्मुक्ति प्राप्त है? यदि उसका आदेश वैध था, तो निश्चित रूप से उसने अवमानना नहीं की होगी और उसके लिए उन्मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि यदि मान भी लिया जाए कि कोई न्यायाधीश सदन की अवमानना कर सकता है, तो भी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। इसे सबसे पहले संविधान की उस योजना पर रखा गया, जिसके बारे में कहा गया कि वह पूरी न्यायिक स्वतंत्रता का पक्षधर है। इसके बाद यह बताया गया कि हमारे संविधान के तहत न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया, अर्थात् संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक निश्चित बहुमत से समर्थित अभिभाषण पर राष्ट्रपति के आदेश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 211 का हवाला दिया गया, जो न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के बारे में विधानसभा में चर्चा पर रोक लगाता है और कहा गया कि यह इस बात का संकेत है कि न्यायाधीश अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ऐसा उत्तरदायी बनाने के लिए उसके आचरण पर चर्चा की जानी चाहिए। हालाँकि यह माना गया कि अनुच्छेद 211 अनुच्छेद 194(2) के मदेनजर प्रवर्तनीय अधिकार नहीं देता है, लेकिन कहा गया कि यह संविधान निर्माताओं की मंशा को दर्शाता है कि न्यायाधीश को विधानसभा की अवमानना के लिए दायित्व से मुक्त रखा जाना चाहिए।

इन तर्कों की सत्यता को विधानसभा की ओर से चुनौती दी गई। न्यायिक स्वतंत्रता के मुद्दे के संबंध में, यह कहा गया कि यह शायद ही कभी इरादा किया गया होगा कि एक न्यायाधीश को उन्मुक्ति मिलनी चाहिए, भले ही उसने जानबूझकर सदन की अवमानना की हो। यह बताया गया कि अवमानना जानबूझकर की गई होगी, क्योंकि न्यायाधीश को पता होगा कि सामान्य वारंट के मामले में उसके पास आने बढने का कोई अधिकार नहीं है।

जहां तक विहित रीति को छोड़कर न्यायाधीशों को हटाए न जा सकने पर

आधारित तर्क का संबंध है, यह कहा गया कि इसका अवमानना के लिए उन्मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह बताया गया कि संविधान में राज्य स्वायत्तता का प्रावधान है और इसका यह आशय नहीं हो सकता कि जब कोई न्यायाधीश राज्य विधानसभा की अवमानना करता है, तो उस निकाय का एकमात्र उपाय यह होगा कि वह न्यायाधीश को हटाने के लिए कदम उठाने के अनुरोध के साथ केन्द्रीय संसद से संपर्क करे। इससे राज्य विधायिका की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगी। ऐसे मामले में राहत देना केंद्रीय संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा और राहत मिलना मुश्किल होगा, खासकर तब जब राज्य और केंद्र में सत्ताधारी पार्टियां अलग-अलग हों। ऐसा कहा गया कि न्यायाधीशों को हटाना न जा सकने का उद्देश्य उनके जानबूझकर किए गए त्रुटिपूर्ण कार्य को बचाना नहीं था, बल्कि शक्तिशाली प्रभावों से अवैध हस्तक्षेप के विरुद्ध उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना था। यह तर्क दिया गया कि न्यायाधीश की उन्मुक्ति न्यायालय के अधिकारियों को भी असहाय और अनिश्चित स्थिति में डाल देगी, जो उसके सभी आदेशों को निष्पादित करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि उन्हें न्यायाधीशों के अवैध आदेशों का भी पालन करना होगा और इस तरह वे स्वयं को सदन द्वारा वैध रूप से लगाए गए दंड के जोखिम में डाल देंगे। अंत में कहा गया कि यदि देश की भलाई के लिए न्यायाधीशों की स्वतंत्रता आवश्यक है, तो विधानमंडलों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है।

अनुच्छेद 211 के संबंध में यह देखा गया कि इसमें ऐसा कोई आशय नहीं दर्शाया गया है कि न्यायाधीश स्वयं द्वारा की गई अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह तर्क दिया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 194(1) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक निश्चित तरीके से नियंत्रित करने की अनुमति देना था। इसके अलावा, यह बताया गया कि अनुच्छेद 211 तब तक किसी चर्चा पर रोक नहीं लगाएगा जब तक कि पहले यह निर्णय न लिया जाए कि वह चर्चा न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आवरण से संबंधित है, ऐसा निर्णय जो अक्सर कठिन होगा और किसी भी स्थिति में सदन के निर्णय पर कानून की अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में से एक है जिसे राज्य विधानसभा ने अनुच्छेद 194(3) के तहत प्राप्त किया है कि इसका अपनी आंतरिक कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण है: (ब्रैडलॉफ बनाम गोसेट देखें)। इन सभी आधारों पर यह तर्क दिया गया कि हमारा संविधान किसी न्यायाधीश को उसके द्वारा की गई स्वीकार की गई अवमानना के लिए कोई छूट नहीं देता। यह बताया गया कि इंग्लैंड में न्यायिक अधिकारियों, जिनमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं, को ऐसी छूट नहीं है और जे बनाम टोपहम तथा ब्रास क्रॉसबी के मामले का संदर्भ दिया गया।

मैं आश्चर्य नहीं हूँ कि मैंने इस सवाल पर सभी तर्क प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन मैंने जो कहा है, उससे विरोधी तर्कों का उचित अंदाजा लग जाएगा। इस मामले के उद्देश्य के लिए, मुझे नहीं लगता कि उन तर्कों के मेरिट पर जाना जरूरी है। मेरे विचार से, संदर्भ के तथ्यों पर उठने वाले प्रश्नों का उत्तर न्यायाधीशों की निष्पक्षता के प्रश्न पर निर्णय लिए बिना ही दिया जा सकता है। अक्सर यह बेहतर होता है कि सैद्धांतिक विवादों को विद्वानों के लेखों में ही दफन रहने दिया जाए और उन्हें हमारे दैनिक जीवन को दूषित करने की अनुमति न दी जाए।

मैं यह उल्लेख करना उचित समझता हूँ कि बिहार के महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित श्री वर्मा ने यह मुद्दा उठाया था कि यह संदर्भ अपर्याप्त है या कम से कम इसका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा केवल तभी संदर्भ दिया जा सकता है जब उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में इस न्यायालय की सलाह की आवश्यकता हो। श्री वर्मा का तर्क था कि संदर्भ में पूछे गए प्रश्न ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनका राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई सलाह से राष्ट्रपति के समक्ष आने वाली किसी भी कठिनाई का समाधान नहीं होगा। दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति इस न्यायालय से प्राप्त उत्तरों के आलोक में संविधान संशोधन पर विचार कर सकते हैं। श्री वर्मा ने अपने तर्क के उत्तर में कहा कि संविधान में संशोधन पर विचार करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है और अनुच्छेद 143 का उद्देश्य यह नहीं है कि कानून बनाने के लिए इस न्यायालय से परामर्श किया जाए। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि श्री वर्मा का तर्क पूर्णतः निराधार है, लेकिन मैं वर्तमान मामले में उस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस बात

से बेहद दुखी हूँ कि परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ ले लिया और राष्ट्रपति द्वारा इस मामले को इस न्यायालय में भेजना आवश्यक हो गया। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे थोड़े अधिक कौशल, संयम और दूसरों के प्रति विचारशीलता से टाला जा सकता था। मुझे कोई संदेह नहीं है कि न्यायमूर्ति बेग और न्यायमूर्ति सहगल ने पूरे तथ्य जानने के बाद 19 मार्च, 1964 की याचिका को खारिज कर दिया होता। मुझे खेद है कि उस अवसर पर अपेक्षित संयम बरतने के बजाय, विशेष रूप से जब कि कारावास का आदेश, जिसे चुनौती दी गई थी, विधानसभा के स्तर के निकाय द्वारा उसके प्रति की गई अवमानना के लिए पारित किया गया था, जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतीक्षा के लिए बहुत समय नहीं था, लेकिन केशव सिंह अंतिम क्षण में आकर न्यायालय पर दबाव नहीं बना सकते थे। माननीय न्यायाधीशों के आदेश का परिणाम विधानसभा की पूरी तरह से वैध कार्रवाई में हस्तक्षेप करना था, जिसमें हस्तक्षेप उचित नहीं था और निश्चित रूप से टाला जा सकता था। दूसरी ओर, विधानसभा संयम बरतकर और न्यायाधीशों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही प्रारम्भ न करके भी संकट से बच सकती थी। यह बात ध्यान में रखी जा सकती है कि न्यायाधीशों के पास कठिन कर्तव्य थे, अक्सर उन्हें अपूर्ण सामग्रियों पर कार्य करना पड़ता है, और इसलिए त्रुटियाँ संभव हैं। इसे यह समझना चाहिए था कि न्यायाधीशों के समक्ष पूर्ण तथ्य रखे जाने पर इसके पक्ष को भी समझा जाता और पूर्ण तथ्य के अभाव में जो किया गया था उसे बदलने के लिए उचित आदेश दिए जाते। विधानसभा की ऐसी कार्रवाई से उसका कद और प्रतिष्ठा बढ़ती और राज्य के विभिन्न अंगों के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में सहायता मिलती।

मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यह महसूस करते हैं कि विधान सभा को अवमानना का पूर्ण अधिकार नहीं दिया जा सकता। संविधान द्वारा विधानमंडलों को स्पष्ट रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। संविधान के लागू होने के चौदह वर्षों के दौरान, विधानमंडलों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे यह धारणा सही साबित हो कि वे सत्ता सौंपे जाने के लायक नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि अनुच्छेद 211 लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी विधानमंडलों ने संयम की सराहनीय भावना दिखाई है और इतने वर्षों में एक बार भी न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की है। हमें अपने लोगों पर विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि विधानमंडल संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे या यह कि सुरक्षा केवल न्यायिक सुधार में ही निहित है। इस तरह के सुधार से टकराव पैदा हो सकता है और लाभ के बजाय हानि हो सकती है। आधुनिक राज्य में देश की भलाई के लिए प्रायः यह आवश्यक होता है कि विभिन्न प्राधिकारों में समानांतर शक्तियाँ विद्यमान हों। यह अपरिहार्य नहीं है कि ऐसी शक्तियों में टकराव हो। यह मानना निराशावाद होगा कि हमारे देश में इन शक्तियों को सुचारु रूप से तथा जनता के सर्वोत्तम हित में तथा बिना किसी टकराव के चलाने के लिए लोग उपलब्ध नहीं होंगे। मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि जो कुछ हुआ है, वह फिर कभी नहीं होगा और हमारे संविधान पर राज्य के विभिन्न अंगों द्वारा सौहार्दपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, सहस्रपूर्ण तरीके से तथा उसी भावना से कार्य किया जाएगा, जिस भावना से संविधान निर्माताओं ने उनसे कार्य करने की अपेक्षा की थी।

आभार अभिव्यक्ति

परम सम्मान के साथ, हम माननीय ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एवसीआर एवं आईएलआर कमेटी, उत्तम न्यायालय का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता से न्यायिक निर्णयों को आम जनमानस की भाषा में उपलब्ध कराया जा सका।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एवसीआर एवं आईएलआर कमेटी के तत्वावधान में सुवास प्रकोष्ठ द्वारा ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका एवं त्रैमासिक ई-पत्रिका - न्यायाभा - न्याय की किरण के प्रकाशन के पश्चात, ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय का प्रकाशन किया जा रहा है। यह कड़ी न्यायिक एवं विधिक ज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बनेगी।

इस ई पुस्तिका के प्रथम संस्करण में ऐतिहासिक मुकदमा चौरी चौरा का प्रकाशन किया गया तथा यह द्वितीय संस्करण ऐतिहासिक केशव सिंह प्रकरण को संदर्भित है।

इस अवसर पर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है।

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एवसीआर एवं आईएलआर कमेटी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार जी, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों की पुस्तिका के प्रकाशन का विचार प्रस्तुत किया और संपादक मंडल का कुशल नेतृत्व किया एवं समिति के सदस्यगण माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी का हृदय से धन्यवाद, जिनके दिशा-निर्देशन में यह प्रकाशन साकार हो रहा है। श्री मंजीत सिंह श्योराण, विद्वान महानिबंधक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रकाशन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष धन्यवाद।

इस अवसर पर हम ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एवसीआर एवं आईएलआर कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण के निजी सचिव श्री संदीप भट्टाचार्य उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री अभिषेक अग्रहरी उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री अवधेश कुमार उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री विश्व मोहन अरोरा, उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री भास्कर, उप निबंधक- सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री संजीव रंजन, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री धीरेन्द्र तमांग, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री शशि प्रकाश, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री आत्मेश केसरी, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री इरफान उदीन सिद्दीकी, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री राजेश कुमार मौर्य, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्रीमती मधुरिमा गर्ग, निजी सचिव ग्रेड-I एवं श्री निर्मल सिन्हा, निजी सचिव ग्रेड-I का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रकाशन में अपना अमूल्य योगदान दिया है।

अंत में, हम माननीय उच्च न्यायालय के सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करने के साथ ही आशा करते हैं कि यह प्रकाशन न्यायिक ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

संपादक मण्डल

सुवास प्रकोष्ठ की संरचना

संयुक्त निबंधक

श्री विवेक श्रीवास्तव

सहायक निबंधक

श्री गोपाल सिंह (लखनऊ)

अनुभाग अधिकारी

सर्वश्री डॉ० मो. शहाब सिद्दीकी, सुधीर तिवारी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार कुशवाहा, अमित शुक्ला, बृजेन्द्र मणि पांडेय, राजेश तिवारी (लखनऊ)

समीक्षा अधिकारी

सर्वश्री राधा रमन, डॉ० अनुपम श्रीवास्तव, देवेन्द्र सिंह, अमित कुमार पांडे, सुश्री प्रियंका गौतम, सुश्री आकृति मिश्रा, श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी, श्री धीरेन्द्र प्रताप, श्री मनीष कुमार सिंह, सुश्री शालिनी सिंह, श्रीमती अंजलि कुशवाहा

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)

सर्वश्री प्रियरंजन, कुलदीप निगम, आदित्य मिश्रा, सुश्री अक्षिता चौधरी, सर्वेश कुमार वर्मा, शुभम पांडे, शुभम गुप्ता, सूरज गोस्वामी, सैयद असीम रसीद, जय शंकर यादव, प्रदीप कौशल, सुश्री अंकिता सचान, आशुतोष कुमार (लखनऊ), गजेन्द्र प्रताप सिंह (लखनऊ), श्रीमती काव्या यादव (लखनऊ), जितेंद्र कुमार (लखनऊ)

सहायक समीक्षा अधिकारी

श्री अतुल सागर

निर्णय अनुवादक (संविदा कर्मी)

सर्वश्री मनीष पाण्डेय, दिलीप शुक्ला, मनीष मिश्रा, उमेश शुक्ला

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

श्रीमती मंजू दुबे, श्री राकेश कुमार

संपादक मण्डल

वरिष्ठ संपादक

श्री विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विनय सरन, वरिष्ठ अधिवक्ता

संपादक मण्डल

श्री कुणाल शाह,
श्री आशीष सिंह,
श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव,
श्री पी. के. श्रीवास्तव,
श्री अनिल मिश्रा,
श्री अनिल गुप्ता,
श्री यावर मुख्तार,

श्री पंकज कुमार अस्थाना,
श्री प्रखर सरन श्रीवास्तव,
सुश्री गौरी दुबे,
सुश्री साक्षी मेहरोत्रा,
श्री ब्रिज भूषण मिश्रा,
सुश्री अर्चना सिंह,
श्री कार्तिकेय सिंह

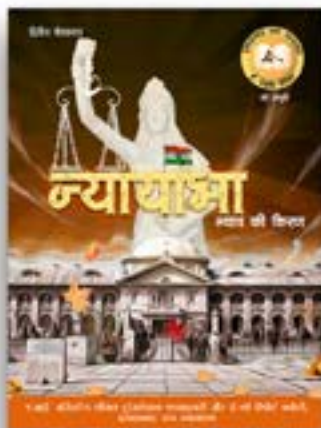
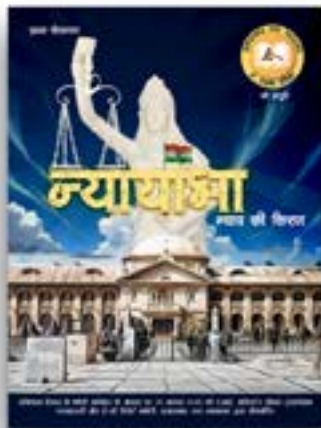
श्री आशीष कुमार,
श्री आशुतोष कुमार राय,
सुश्री निधि वर्मा,
श्री विनायक वर्मा,
सुश्री साधना सिंह,
सुश्री नाज़िया नफीस,

पदेन सदस्य

श्री दिवाकर द्विवेदी, (समिति के निवर्तमान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)-समन्वयक-संपादक मंडल
श्री अरविन्द वर्मा (समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)-समन्वयक-संपादक मंडल
श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ इलाहाबाद
श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री मनीष कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा न्याय की किरण



ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय





ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय